रायपुर,जबलपुर, कटनी, मंडला, भोपाल, इंदौर, मुंबई, दिल्ली, नरसिंहपुर, सिवनी से एक साथ प्रकाशित

yashbharat.co.in

नये जमाने के साथ..

यश भारत

● वर्ष-1 अंक-166 ● रायपुर ● गुरुवार ,5नवम्बर , 2026 ● मूल्य- 4 रुपए ● पृष्ठ-8 ●कार्तिक कृष्ण पक्ष 11● विक्रम संवत् 2083

आत्म-नियंत्रण जीवन की असली शक्ति है। इसे मजबूत बनाना रोज़ का काम है।



अग्निवीरों को दो साल का सेवा विस्तार

अब 6 साल तक कर सकेंगे नौकरी

25 प्रतिशत को नियमित सैनिक बनाने का नियम बरकरार ,शेष 75 प्रतिशत को भी अतिरिक्त मौका

नई दिल्ली। यशभारत। अग्निपथ योजना के तहत सेना में भर्ती होने वाले अग्निवीरों के लिए बड़ी राहत की घोषणा की गई है। अब अग्निवीर चार साल के बजाय छह साल तक सेना में सेवाएं दे सकेंगे। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (सीडीएस) जनरल एनएस राजा सुब्रमणि ने बुधवार को दो साल का अतिरिक्त सेवा विस्तार देने का ऐलान किया। इस फैसले से उन 75 प्रतिशत अग्निवीरों को फायदा मिलने की उम्मीद है, जिन्हें चार साल की सेवा पूरी होने के बाद सेना से बाहर होना पड़ता था। हालांकि, अतिरिक्त दो साल की सेवा का लाभ अग्निवीरों की सहमति और निर्धारित शर्तों के आधार पर मिलेगा।

नई व्यवस्था में अग्निपथ योजना के मूल प्रावधान को बरकरार रखा गया है। इसके तहत प्रत्येक बैच के 25 प्रतिशत अग्निवीरों को चार साल की सेवा पूरी होने के बाद योग्यता और प्रदर्शन के आधार पर नियमित सैनिक के रूप में शामिल किया जाएगा। वहीं, शेष 75 प्रतिशत अग्निवीरों को दो साल का अतिरिक्त सेवा अवसर मिलेगा। इस अवधि में उन्हें बढ़ा हुआ वेतन और निर्धारित भत्ते भी दिए जाएंगे। छह साल की सेवा पूरी होने के बाद भी सेना में स्थायी नौकरी पाने के इच्छुक अग्निवीरों को चयन प्रक्रिया से गुजरना होगा। उनका चयन मेरिट, कार्यक्षमता और सेवा के दौरान प्रदर्शन के आधार पर किया जाएगा। दरअसल, अग्निपथ योजना के तहत भर्ती किए गए पहले बैच का चार साल का कार्यकाल दिसंबर 2026 तक पूरा होने जा रहा है। आंकड़ों के मुताबिक, 31 दिसंबर तक पहले बैच के करीब 18,300 अग्निवीरों की सेवा अवधि समाप्त होनी थी। यह संख्या पहले बैच में भर्ती हुए कुल 24,400 अग्निवीरों का लगभग 75 प्रतिशत है।









अमेरिकी मध्यावधि चुनाव में ट्रंप को बड़ा झटका

दोनों सदनों में डेमोक्रेट्स का कब्जा

डेमोक्रेटिक पार्टी को बहुमत, पिछले 21 में से 19 चुनावों में राष्ट्रपति की पार्टी हारी

मिशिगन से अब्दुल अल-सैयद बने अमेरिका के पहले मुस्लिम सीनेटर

वॉशिंगटन डीसी। यशभारत। अमेरिका के मिडटर्म चुनाव में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प और उनकी रिपब्लिकन पार्टी को करारा झटका लगा है। डेमोक्रेटिक पार्टी ने अमेरिकी संसद के दोनों सदनों सीनेट और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में बहुमत हासिल कर लिया है। चुनाव नतीजों को ट्रम्प की नीतियों और उनके राजनीतिक नेतृत्व के खिलाफ बड़े जनादेश के रूप में देखा जा रहा है। इस जीत के साथ विपक्षी डेमोक्रेट्स को संसद में ट्रम्प सरकार की नीतियों पर अंकुश लगाने और उसके फैसलों को चुनौती देने का मजबूत अवसर मिलेगा।

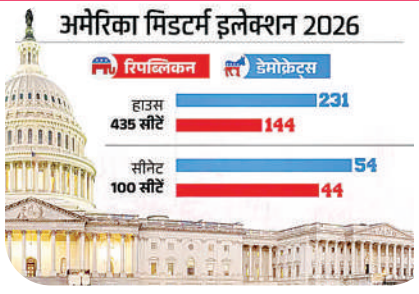
इस चुनाव का सबसे चर्चित परिणाम मिशिगन से सामने आया है, जहां डेमोक्रेटिक उम्मीदवार अब्दुल अल-सैयद ने जीत दर्ज कर इतिहास रच दिया। वह अमेरिकी इतिहास में सीनेटर चुने जाने वाले पहले मुस्लिम बन गए हैं। उनकी जीत इसलिए भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि चुनाव प्रचार के दौरान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने उन पर तीखे व्यक्तिगत हमले किए थे। ट्रम्प ने सार्वजनिक मंच से उन्हें जिहादी तक कह दिया था और उन पर आतंकियों का समर्थन करने के आरोप लगाए थे। 25 अक्टूबर को मिशिगन में आयोजित चुनावी रैली में ट्रम्प ने कहा था कि वह एक जिहादी और मुस्लिम ब्रदरहुड के सदस्य को अमेरिकी सीनेटर बनने से रोकने आए हैं।

हाउस में डेमोक्रेट्स को स्पष्ट बहुमत

अमेरिकी संसद के निचले सदन हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स की सभी 435 सीटों पर चुनाव हुए। इनमें डेमोक्रेटिक पार्टी ने 231 सीटें जीतकर स्पष्ट बहुमत हासिल किया, जबकि रिपब्लिकन पार्टी को 144 सीटें मिलीं। इस सदन में बहुमत के लिए 218 सीटों की आवश्यकता होती है। डेमोक्रेट्स की जीत का अंतर बताता है कि पार्टी को मजबूत समर्थन मिला है।

सीनेट में भी बदला सत्ता का समीकरण

सीनेट की 100 सीटों में से इस बार 35 सीटों पर चुनाव हुए।



उपलब्ध नतीजों के मुताबिक, डेमोक्रेटिक पार्टी ने 20 और रिपब्लिकन पार्टी ने 13 सीटों पर जीत दर्ज की है। दो सीटों पर मतगणना जारी थी। इन नतीजों के बाद सीनेट में डेमोक्रेट्स की संख्या बढ़कर 54 हो गई, जबकि रिपब्लिकन के पास 44 सीटें बताई गईं। सीनेट में बहुमत के लिए 51 सीटों की जरूरत होती है।

गवर्नर चुनाव में भी डेमोक्रेट्स आगे

गवर्नर पदों के चुनाव में भी डेमोक्रेट्स ने बढ़त बनाई है। कुल 36 राज्यों में गवर्नर पद के लिए मतदान हुआ था। इनमें से 34 राज्यों के नतीजे सामने आ चुके हैं। डेमोक्रेटिक उम्मीदवारों ने 22 और रिपब्लिकन उम्मीदवारों ने 12 राज्यों में जीत दर्ज की, जबकि दो राज्यों में मतगणना जारी थी।

भारतीय मूल के उम्मीदवारों ने भी लहराया परचम

मध्यावधि चुनाव में भारतीय मूल के उम्मीदवारों ने भी अपनी राजनीतिक ताकत दिखाई। फ्लोरिडा के 22वें कांग्रेसनल जिले से डेमोक्रेटिक उम्मीदवार पिया डांडिया ने जीत हासिल कर प्रतिनिधि सभा में जगह बनाई। वहीं वर्जीनिया के 10वें कांग्रेसनल जिले से सुहास सुब्रमण्यम दोबारा निर्वाचित हुए। इन सफलताओं को अमेरिकी राजनीति में भारतीय मूल के समुदाय की बढ़ती भागीदारी और प्रभाव के तौर पर देखा जा रहा है।

ट्रम्प विरोधी देशों के नेताओं ने किया स्वागत

डेमोक्रेट्स की जीत का अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी असर दिखाई दिया। स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज ने नतीजों का स्वागत करते हुए कहा कि अमेरिकी मतदाताओं ने नफरत, जलवायु परिवर्तन से इनकार और अमीर-ताकतवर लोगों के दबदबे के खिलाफ मतदान किया है। नॉर्वे के प्रधानमंत्री जोनास गार स्टोर ने भी इसे सकारात्मक संकेत बताया। दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामफोसा ने कहा कि इन नतीजों से दुनिया के देशों के रिश्तों में नए दौर की शुरुआत हो सकती है।

दो से ज्यादा बच्चे करने पर कानूनी पाबंदी सही नहीं-सुको

आने वाले समय में बुजुर्गों की आबादी बढ़ेगी और कामकाजी लोगों का अनुपात घटेगा

नई दिल्ली, एजेंसी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि दो से ज्यादा बच्चे होने पर चुनाव लड़ने से रोकने वाले कानून अब प्रासंगिक नहीं रह गए हैं। कोर्ट के मुताबिक, भारत की प्रजनन दर 2003 में 3 थी, जो अब घटकर 1.9 रह गई है। कोर्ट ने कहा कि आने वाले समय में बुजुर्गों की आबादी बढ़ेगी और कामकाजी लोगों का अनुपात घटेगा। अगर इन बदलावों पर ध्यान नहीं दिया गया तो देश को गंभीर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस आलोक अराधे की बेंच ने इस मामले में 2003 के अपने फैसले को बड़ी बेंच के पास भेज दिया, जिसमें कोर्ट ने हरियाणा के दो बच्चों वाले नियम को सही ठहराया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र की पूर्व सरपंच मंगला भीमराव की अयोग्यता भी रद्द कर दी। उन्हें तीसरे बच्चे के जन्म के कारण पद से अयोग्य ठहराया गया था।

कोर्ट बोला- बढ़ती आबादी का डर अब कानूनों का आधार नहीं - जस्टिस नरसिम्हा ने फैसला सुनाते हुए कहा- हमारी स्पष्ट राय है कि दो से ज्यादा बच्चे होने पर सजा देने वाले कानून अब अपनी प्रासंगिकता खो चुके हैं।

ध्यान नहीं दिया गया तो देश को गंभीर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं

इन कानूनों का आधार बढ़ती आबादी का डर था। पिछले कुछ दशकों में जनसंख्या से जुड़े बदलावों के कारण यह आधार खत्म हो गया है।कोर्ट ने बताया कि 2.1 की प्रजनन दर को रिप्लेसमेंट रेट माना जाता है। इस दर पर एक पीढ़ी अपनी जगह अगली पीढ़ी को ले सकती है। कोर्ट ने कहा कि जनसंख्या वृद्धि को रोकने के लिए बनाए गए कानूनों की अब समीक्षा जरूरी है।दो बच्चों की शर्त से राजनीतिक अधिकारों से वंचित करना गलत- कोर्ट ने 2003 के फैसले में दो बच्चों की शर्त को सही ठहराने के लिए इस्तेमाल किए गए तर्कों पर भी चिंता जताई। कोर्ट ने कहा कि ऐसे कानूनों के जारी रहने से नागरिकों का एक पूरा वर्ग राजनीतिक प्रतिनिधित्व से बाहर हो जाता है।कोर्ट के मुताबिक, किसी व्यक्ति के बच्चों की संख्या का उसके सार्वजनिक पद संभालने की क्षमता से कोई खास संबंध नहीं है। ऐसे कानून लोगों को बच्चे पैदा करने और लोकतांत्रिक प्रक्रिया में हिस्सा लेने के बीच एक विकल्प चुनने के लिए मजबूर करते हैं। यह संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत मिले प्रजनन स्वायत्तता के अधिकार का उल्लंघन है।



पूर्व सरपंच के खिलाफ शिकायत के बाद शुरू हुई थी कार्रवाई

मंगला भीमराव महाराष्ट्र के काकोड़ा ग्राम पंचायत की पूर्व सरपंच थीं। उन्हें महाराष्ट्र ग्राम पंचायत अधिनियम, 1959 की धारा 14(1)(j-1) के तहत अयोग्य ठहराया गया था। इस कानून में 13 सितंबर 2000 से दो से ज्यादा बच्चे होने पर चुनाव लड़ने की अयोग्यता का प्रावधान लागू हुआ था। मंगला के खिलाफ अतिरिक्त कलेक्टर के सामने शिकायत की गई थी। इसके बाद उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया गया। उन्होंने अतिरिक्त आयुक्त के पास अपील की, लेकिन वहां से भी राहत नहीं मिली। इसके बाद उन्होंने बॉम्बे हाईकोर्ट में याचिका लगाई। 5 अगस्त 2025 को हाईकोर्ट ने उनकी अयोग्यता बरकरार रखी। कोर्ट ने कहा था कि तीसरे बच्चे के जन्म प्रमाणपत्र में माता-पिता दोनों के नाम दर्ज हैं और इसके उलट कोई सबूत नहीं है।

महादेव सट्टा एप केसः सौरभ चंद्राकर सीबीआई रिमांड पर, दिल्ली में होगी पूछताछ

रायपुर, यशभारत। महादेव ऑनलाइन सट्टा एप मामले में आरोपी सौरभ चंद्राकर को रायपुर की विशेष अदालत ने आठ दिन की सीबीआई रिमांड पर भेज दिया है। बुधवार को अदालत में पेशी के दौरान दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद यह आदेश दिया गया। सीबीआई अब 11 नवंबर तक उससे पूछताछ करेगी। सुरक्षा कारणों से जांच एजेंसी उसे रायपुर के बजाय दिल्ली ले जाकर पूछताछ करने की तैयारी में है। वहीं प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने भी सौरभ की कस्टडी हासिल करने के लिए अदालत में आवेदन दिया है। ऐसे में आने वाले दिनों में इस बहुचर्चित सट्टा नेटवर्क से जुड़े आर्थिक लेनदेन, अन्य आरोपियों और कथित अंतरराष्ट्रीय कनेक्शन की जांच तेज होने की संभावना है।

सीबीआई को उम्मीद है कि पूछताछ के दौरान सौरभ चंद्राकर से मामले से जुड़े कई अहम तथ्य सामने आ सकते हैं। रिमांड अवधि पूरी होने के बाद 12 नवंबर को उसे दोबारा अदालत में पेश किया जाएगा। जांच एजेंसी उससे सट्टा एप के संचालन, नेटवर्क से जुड़े लोगों और वित्तीय लेनदेन के संबंध में पूछताछ करेगी। दूसरी ओर ईडी की ओर से भी कस्टडी की मांग किए जाने से आरोपी की गिरफ्तारी के बाद जांच का दायरा और बढ़ने के संकेत हैं।



ओमान से हुई थी गिरफ्तारी

सौरभ चंद्राकर को रेड कॉर्नर नोटिस के आधार पर 8 जुलाई 2026 को ओमान की रॉयल पुलिस ने गिरफ्तार किया था। इसके बाद सीबीआई और ईडी ने भारत सरकार के माध्यम से ओमान को प्रत्यर्पण का औपचारिक प्रस्ताव भेजा। भारतीय एजेंसियों ने मामले से जुड़े साक्ष्य भी ओमान पुलिस को उपलब्ध कराए थे। भारत सरकार की एजेंसियों, इंटरपोल और ओमान के अधिकारियों के बीच बातचीत तथा कानूनी प्रक्रिया पूरी होने के बाद प्रत्यर्पण को मंजूरी मिली।इसके बाद सीबीआई की टीम ओमान की राजधानी मस्कट पहुंची और आवश्यक कानूनी औपचारिकताएं पूरी करने के बाद एक नवंबर को सौरभ चंद्राकर को भारत लेकर आई। अब आठ दिन की रिमांड के दौरान उससे होने वाली पूछताछ पर सबकी नजर है। महादेव सट्टा एप मामले में उसकी भूमिका और नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों के बारे में मिलने वाली जानकारियां जांच की दिशा तय कर सकती हैं।

कोहली ने तोड़ा सचिन का विश्व रिकॉर्ड

वनडे रनचेज में बने नंबर-1 बल्लेबाज



ऑकलैंड,एजेंसी। भारत ने पहले वनडे मुकाबले में न्यूजीलैंड को पांच विकेट से हराकर शानदार जीत दर्ज की। इस मुकाबले में विराट कोहली ने रिकॉर्ड्स की झड़ी लगा दी। उन्होंने महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर का विश्व रिकॉर्ड तोड़ते हुए वनडे क्रिकेट में लक्ष्य का पीछा करते हुए सर्वाधिक रन बनाने वाले बल्लेबाज का गौरव हासिल किया। कोहली के नाम अब रनचेज में 8741 रन हो गए हैं, जबकि सचिन तेंदुलकर ने 8720 रन बनाए थे। इसके साथ ही कोहली ने एक और बड़ी उपलब्धि हासिल करते हुए वनडे में नंबर-3 पर बल्लेबाजी करते हुए 13 हजार रन पूरे कर लिए। वह ऐसा करने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज बन गए हैं।कोहली ने न्यूजीलैंड के खिलाफ भी अपना शानदार रिकॉर्ड कायम रखा। उन्होंने कीवी टीम के विरुद्ध वनडे क्रिकेट में 1971 रन पूरे कर ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान रिकी पोंटिंग की बराबरी कर ली। दोनों बल्लेबाज इस मामले में संयुक्त रूप से शीर्ष पर पहुंच गए हैं। कोहली ने मुकाबले में 35 गेंदों पर अपना अर्धशतक पूरा किया। विदेशी मैदानों पर वनडे क्रिकेट में यह उनका दूसरा सबसे तेज अर्धशतक रहा। इससे पहले उन्होंने 2016 में ऑस्ट्रेलिया के कैनबरा में 34 गेंदों पर फिफ्टी लगाई थी। भारत ने पहले वनडे में न्यूजीलैंड को 5 विकेट से हरा दिया। इसी के साथ टीम इंडिया 5 मैचों की सीरीज में 1-0 से आगे हो गई हैऑकलैंड के ईडन पार्क में भारत ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। अर्शदीप सिंह के 4 विकेट की बदौलत न्यूजीलैंड की टीम 40.2 ओवर में 185 रन पर ऑलआउट हो गई। गुरनूर बरार ने भी 3 विकेट लिए।बारिश के कारण भारत को 32 ओवर में 143 रन का रिवाइज्ड टारगेट मिला। टीम ने 22.4 ओवर में 5 विकेट खोकर इसे हासिल कर लिया।

राजस्थान में ट्रेन उड़ाने की साजिश!

पैसेंजर ट्रेन गुजरने के 45 मिनट बाद रेलवे ट्रैक पर भीषण धमाका

अनूपगढ़ (श्रीगंगानगर)। राजस्थान के श्रीगंगानगर जिले में भारत-पाकिस्तान अंतरराष्ट्रीय सीमा के नजदीक मंगलवार रात रेलवे ट्रैक पर हुए भीषण विस्फोट ने सुरक्षा एजेंसियों में हड़कंप मचा दिया। अनूपगढ़-सूरतगढ़ रेलखंड पर 50 जीबी गांव के पास रात करीब 9ः45 बजे हुए धमाके से रेलवे पटरी के नीचे करीब दो फीट गहरा गड्ढा बन गया और सीमेंट के दो स्लीपर क्षतिग्रस्त हो गए। चौंकाने वाली बात यह रही कि इसी ट्रैक से रात 9 बजे पैसेंजर ट्रेन गुजर चुकी थी। यानी ट्रेन के सुरक्षित निकलने के करीब 45 मिनट बाद विस्फोट हुआ। यदि धमाका ट्रेन के गुजरने के दौरान होता तो बड़ा रेल हादसा हो सकता था।



पाकिस्तानी नेटवर्क की आशंका के बीच एटीएस, आईबी, सीआईडी, एफएसएल और बम निरोधक दस्ते ने जांच शुरू कर दी है। सुरक्षा के मद्देनजर रेलवे ने चार ट्रेनें रद्द कर दीं।विस्फोट इतना जोरदार था कि इसकी आवाज करीब 200 मीटर दूर तक सुनाई दी। आसपास की ढाणियों में रहने वाले ग्रामीण मौके पर पहुंचे तो रेलवे लाइन क्षतिग्रस्त मिली। इसके बाद रामसिंहपुर थाना पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी तत्काल घटनास्थल पर पहुंचे। शुरुआती निरीक्षण में पटरी के नीचे गहरा गड्ढा, टूटे स्लीपर और आसपास बिखरी कंक्रीट सामग्री मिली। रेलवे की तकनीकी टीम ने मौके पर पहुंचकर नुकसान का आकलन शुरू किया। मामले की गंभीरता को देखते हुए एटीएस, आईबी, सीआईडी, एफएसएल और बम निरोधक दस्ते की टीमें घटनास्थल पर पहुंचीं। पुलिस अधीक्षक हरिशंकर के मुताबिक मामले की जांच जारी है।



बच्चों की मौत और लापता होने पर हाईकोर्ट सख्त, 11 कोर्ट कमिश्नर करेंगे घरोंदा केंद्रों का निरीक्षण

बिलासपुर, यशभारत। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने रायपुर के घरोंदा केंद्र में आठ बच्चों की मौत और पांच बच्चों के लापता होने के मामले को गंभीरता से लेते हुए कड़ा रुख अपनाया है। अदालत ने इस पूरे घटनाक्रम को अमानवीय करार देते हुए प्रदेश में संचालित घरोंदा केंद्रों की वास्तविक स्थिति का पता लगाने के लिए 11 कोर्ट कमिश्नरों की विशेष टीम गठित की है। कोर्ट ने सभी कमिश्नरों को केंद्रों का निरीक्षण कर जल्द विस्तृत रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए हैं। जांच में बच्चों की स्वास्थ्य, पोषण, सुरक्षा और देखभाल से जुड़ी व्यवस्थाओं की पड़ताल की जाएगी।

अदालत में राज्य शासन की ओर से मुख्य सचिव, वित्त सचिव और समाज कल्याण विभाग के सचिव ने शपथ पत्र प्रस्तुत कर बताया कि पिछले तीन वर्षों में घरोंदा केंद्रों में रहने वाले बच्चों की देखभाल पर नौ करोड़ रुपये से अधिक खर्च किए गए हैं। शासन के मुताबिक, इस अवधि में चार प्रमुख संस्थाओं को कुल 9 करोड़ 76 लाख रुपये का अनुदान जारी किया गया। इनमें पीतांबरा संस्था भी शामिल है। इसके बावजूद केंद्रों में बच्चों की मौत और उनके लापता होने की घटनाओं ने सरकारी निगरानी और संस्थाओं की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।

हाईकोर्ट ने वास्तविक स्थिति का आकलन करने के लिए 11 कोर्ट कमिश्नरों का विशेष दल बनाया है। इसमें अधिवक्ता विवेक श्रीवास्तव, अपूर्व त्रिपाठी, संघर्ष पांडेय, सूर्या कंवलकर डांगी, शिवाली दुबे, अदिति सिंघवी और ईश्वर जायसवाल सहित अन्य अधिवक्ताओं को शामिल किया गया है। टीम को केंद्र और राज्य सरकार की कल्याणकारी योजनाओं के तहत संचालित विभिन्न घरोंदा केंद्रों का निरीक्षण करना है। अदालत चाहती है कि सरकारी दावों और केंद्रों में उपलब्ध वास्तविक सुविधाओं के बीच की स्थिति सामने आए।

जनहित याचिका से सामने आया मामला

यह मामला रायपुर की सामाजिक संस्था कोपलवाणी की ओर से दायर जनहित याचिका के बाद सामने आया। याचिका में आरोप लगाया गया था कि गैर-सरकारी संगठनों के सहयोग से संचालित घरोंदा केंद्रों में पर्याप्त व्यवस्थाएं नहीं हैं और बच्चों को भोजन तक की परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। संस्था ने बच्चों की बदहाल स्थिति और देखभाल में लापरवाही का मुद्दा उठाया था। याचिका पर सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने शासन से जवाब मांगा। उपलब्ध जानकारी के अनुसार, वर्ष 2014 से अब तक इन संस्थाओं में आठ बच्चों की मौत हो चुकी है। अब कोर्ट कमिश्नरों की जांच से यह स्पष्ट होने की उम्मीद है कि केंद्रों में बच्चों की देखभाल, भोजन, चिकित्सा और सुरक्षा के इंतजाम किस स्तर के हैं।

विशेष जरूरत वाले बच्चों और वयस्कों के लिए है योजना - घरोंदा योजना का उद्देश्य सेरिब्रल पाल्सी, ऑटिज्म और एडीएचडी जैसी गंभीर मानसिक एवं शारीरिक चुनौतियों से जूझ रहे निराश्रित बच्चों और वयस्कों को आश्रय तथा देखभाल उपलब्ध कराना है। इन केंद्रों में 18 वर्ष से अधिक आयु के विशेष आवश्यकता वाले व्यक्तियों के साथ बच्चों को भी रखा जाता है। ऐसे में इन संस्थानों की जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। हाईकोर्ट के निर्देश के बाद अब इन केंद्रों की व्यवस्थाओं की व्यापक जांच होगी।

अबू धाबी में मनाया गया भगवान बिरसा मुंडा का जयंती समारोह

प्रवासी भारतीयों ने दिखाई सांस्कृतिक एकजुटता





अबू धाबी, यशभारत। बिहार एंड झारखंड समाज, अबू धाबी द्वारा भगवान बिरसा मुंडा दिवस के अवसर पर भारतीय दूतावास, अबू धाबी में भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। समारोह में संयुक्त अरब अमीरात में भारत के राजदूत डॉ. दीपक मित्तल मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। कार्यक्रम का शुभारंभ भारत और संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रगीतों के गायन तथा दीप प्रज्वलन के साथ हुआ। इस अवसर पर स्कूली विद्यार्थियों द्वारा भगवान बिरसा मुंडा के जीवन, संघर्ष और आदिवासी संस्कृति पर आधारित बनाई गई पेंटिंग्स की आकर्षक प्रदर्शनी लगाई गई। प्रदर्शनी के माध्यम से बच्चों ने अपनी कला प्रतिभा का प्रदर्शन करने के साथ ही महान स्वतंत्रता सेनानी बिरसा मुंडा के जीवन और उनके योगदान को रेखांकित किया। समारोह को संबोधित करते हुए भारतीय राजदूत डॉ. दीपक मित्तल ने भगवान बिरसा मुंडा के जीवन, उनके संघर्ष, साहस और देश की आजादी में उनके योगदान पर विस्तार से प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि भगवान बिरसा मुंडा का जीवन देशभक्ति, सामाजिक चेतना और अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करने की प्रेरणा देता है। उन्होंने विदेश में रहते हुए भी भारतीय संस्कृति, परंपराओं और महापुरुषों की विरासत को जीवित रखने के लिए बिहार एंड झारखंड समाज सहित अबू धाबी में रह रहे प्रवासी भारतीयों की सराहना की। कार्यक्रम के दौरान अबू धाबी में निवासरत विभिन्न प्रदेशों के प्रतिष्ठित व्यक्तियों को स्मृति चिह्न एवं शॉल भेंटकर सम्मानित किया गया। समारोह में महिलाओं और बच्चों ने नृत्य एवं गायन की मनमोहक प्रस्तुतियां दीं। भारतीय लोक संस्कृति और परंपराओं पर आधारित इन प्रस्तुतियों ने आयोजन को उत्साह, उमंग और रंगों से भर दिया। विदेश की धरती पर भारतीय सांस्कृतिक विरासत की जीवंत झलक देखने को मिली। पूरे कार्यक्रम में देशप्रेम, सामाजिक एकजुटता और सांस्कृतिक गौरव का वातावरण बना रहा।

सिवनी के छोटे गांव से लाल किले तक पहुंचा पत्रकार सलीम का सफर

डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम रत्न पुरस्कार से हुए सम्मानित

कभी साइकिल से घर-घर अखबार पहुंचाते थे सलीम रेहमान, मुंबई से लेकर दुबई तक पत्रकारिता में बनाई पहचान



नई दिल्ली , यश भारत। मध्य प्रदेश के सिवनी जिले के एक छोटे से गांव गोपालगंज से शुरू हुआ संघर्ष और मेहनत का सफर आज दिल्ली के ऐतिहासिक लाल किले तक पहुंच गया है। गांव की गलियों में साइकिल से अखबार बेचने वाले सलीम रेहमान को डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। उनकी इस उपलब्धि ने न केवल उनके परिवार, बल्कि पूरे सिवनी जिले और मध्य प्रदेश को गौरवान्वित किया है। सलीम रेहमान की कहानी किसी बड़े शहर की सुविधाओं या संसाधनों से शुरू नहीं हुई। उनका ताल्लुक सिवनी जिले के छोटे से गांव गोपालगंज से है। शुरुआती दिनों में उन्होंने साइकिल पर घूम-घूमकर अखबार बेचने का काम किया। इसी दौरान समाचारों और पत्रकारिता के प्रति उनकी रुचि बढ़ी और उन्होंने धीरे-धीरे लिखना शुरू किया। यहीं से उनके पत्रकारिता के सफर की नींव पड़ी। सीमित संसाधनों के बावजूद आगे बढ़ने का उनका जुनून उन्हें एक शहर से दूसरे शहर और फिर देश की सीमाओं के पार ले गया। सलीम ने अपने पत्रकारिता करियर में सिवनी से शुरुआत की और फिर नागपुर तथा मुंबई में अपनी पहचान बनाई। इसके बाद उनका सफर संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) तक पहुंचा, जहां वे वर्तमान में पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। मुंबई और दुबई में भी उन्हें कई पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। दिल्ली के ऐतिहासिक लाल किले में आयोजित सम्मान समारोह में उन्हें डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम रत्न पुरस्कार प्रदान किया गया। इनमें यूएई के शाही परिवार के वरिष्ठ सलाहकार एवं ट्रस्ट इन ट्रेड के सीईओ डॉ. अर्शी अयूब जवेरी, डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम के भतीजे और हाउस ऑफ कलाम, रामेश्वरम के सचिव एपीजेएम जैनुलाबुद्दीन प्रमुख रूप से शामिल रहे।

भिलाई में विकास कार्यों को मिलेगी गति, महापौर परिषद की बैठक में 15 प्रस्तावों पर चर्चा

2 करोड़ की लागत से बनेगा मांगलिक एवं सांस्कृतिक भवन, सेमरिया में 10 मेगावाट सोलर प्लांट लगाने की पहल

यश भारत



भिलाईनगर। नगर पालिक निगम भिलाई में महापौर नीरज पाल की अध्यक्षता एवं निगम आयुक्त सुरूचि सिंह की उपस्थिति में महापौर परिषद की बैठक आयोजित की गई। बैठक में शहर के विकास, नागरिक सुविधाओं, स्वच्छता व्यवस्था और निगम की आय बढ़ाने से जुड़े 15 प्रस्तावों पर चर्चा की गई। इस दौरान कई महत्वपूर्ण कार्यों को सहमति एवं अनुशंसा प्रदान की गई।

बैठक में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत कुरूद के 19 तथा खम्हरिया-जुनवानी के 27, कुल 46 पात्र हितग्राहियों की अंतिम सूची सामान्य सभा में प्रस्तुत करने पर सहमति बनी। वहीं, ग्राम सेमरिया स्थित निगम की भूमि पर 10 मेगावाट क्षमता का ऑनग्रिड सोलर प्लांट स्थापित करने के लिए शासन को पत्र भेजने की मंजूरी दी गई। इसके अलावा वार्ड क्रमांक 18 काट्रेक्टर कॉलोनी के सामुदायिक भवन के संचालन के लिए प्रक्रिया शुरू करने तथा नेहरू नगर पश्चिम में सीसी रोड एवं नाली निर्माण के प्रस्तावित स्थल में परिवर्तन को सहमति दी गई। अधोसंरचना मद से जोन क्रमांक 2 के वार्ड 28 कैंप-1 स्थित सुभाष चौक के पास बीएसपी स्कूल के समीप 2 करोड़ रुपये की लागत से मांगलिक एवं सांस्कृतिक भवन निर्माण के लिए निविदा आमंत्रित करने की अनुमति दी गई। वहीं, हुडको में डॉ. भीमराव अंबेडकर सर्व समाज मांगलिक भवन और वार्ड 51 स्थित पंडित दीनदयाल उपाध्याय खेल परिसर के संचालन एवं संधारण के लिए आरएफपी आमंत्रित करने की अनुशंसा की गई। हुडको क्षेत्र की सीवरेज लाइन के नवीनीकरण कार्य को भी स्वीकृति प्रदान की गई। बैठक में महापौर परिषद के सदस्यों ने पेयजल, स्वच्छता, ऊर्जा संरक्षण, सामाजिक एवं सांस्कृतिक सुविधाओं तथा शहर के आधारभूत विकास से जुड़े विषयों पर विचार-विमर्श किया। इस दौरान महापौर परिषद के सदस्य लक्ष्मीपति राजू, सीजू एन्थोनी, संदीप निरंकारी, आदित्य सिंह, केशव चौबे, एकांश बंछोर, चंद्रशेखर गंवई, मालती ठाकुर सहित निगम के अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे।

दुर्ग पुलिस की जुआरियों पर बड़ी कार्रवाई

18 लोग पकड़े गए; 17,950 रुपये नगद और 208 ताश की पत्ती जब्त



नंदिनी, धमधा और उतई थाना क्षेत्रों में चार अलग-अलग जगहों पर दबिश, जुआ प्रतिषेध अधिनियम के तहत कार्रवाई

यश भारत

दुर्ग । सार्वजनिक स्थानों पर रुपये-पैसों का दांव लगाकर जुआ खेलने वालों के खिलाफ दुर्ग पुलिस ने अभियान चलाकर चार अलग-अलग मामलों में कार्रवाई की है। 3 और 4 नवंबर को नंदिनी, धमधा एवं उतई थाना क्षेत्रों में पुलिस ने दबिश देकर कुल 18 लोगों को पकड़ा। आरोपियों के कब्जे से 17,950 रुपये नगद और 208 पत्ती ताश जब्त की गई है। पुलिस के अनुसार, थाना नंदिनी क्षेत्र के ग्राम कोड़िया में शासकीय स्कूल के पीछे जुआ खेलते चार लोगों को पकड़ा गया। उनके पास से 1,800 रुपये और 52 पत्ती ताश जब्त की गई।

इसी तरह धमधा थाना क्षेत्र के ग्राम राजपुर में पत्थर खदान के किनारे जुआ खेलते छह लोगों को पकड़ा गया। यहां से 12,020 रुपये नगद और 52 पत्ती ताश बरामद हुई। उतई थाना क्षेत्र में दो अलग-अलग स्थानों पर कार्रवाई की गई। ग्राम पतोरा में पानी टंकी के नीचे जुआ खेलते पांच लोगों को पकड़ा गया, जिनके पास से 2,280 रुपये और 52 पत्ती ताश जब्त की गई। वहीं, इडरा नहर के पास भी पुलिस ने जुआ खेलने वालों के खिलाफ कार्रवाई की। चारों मामलों में आरोपियों के विरुद्ध छत्तीसगढ़ जुआ प्रतिषेध अधिनियम की धारा 3(2) के तहत अपराध पंजीबद्ध कर वैधानिक कार्रवाई की गई है। दुर्ग पुलिस ने सार्वजनिक स्थानों पर अवैध रूप से जुआ खेलने वालों के खिलाफ अभियान लगातार जारी रखने की बात कही है।

दीपावली पर बाजारों में अतिक्रमण पर रहेगी नजर, महापौर बाघमार और आयुक्त ने किया निरीक्षण

इंदिरा मार्केट, पुराना बस स्टैंड और निब्बू लाइन में दो घंटे पैदल घूमकर देखी व्यवस्था, दुकानों के सामने 8×8 फीट की मार्किंग

यश भारत



दुर्ग । दीपावली और छठ पर्व पर बाजारों में बढ़ती भीड़ को देखते हुए नगर निगम प्रशासन ने यातायात और पार्किंग व्यवस्था दुरुस्त करने की कवायद शुरू कर दी है। इसी कड़ी में महापौर अलका बाघमार एवं निगम आयुक्त लीना कोसम ने इंदिरा मार्केट, पुराना बस स्टैंड और निब्बू लाइन सहित प्रमुख बाजार क्षेत्रों का करीब दो घंटे तक पैदल निरीक्षण किया।

निरीक्षण के दौरान दुकानों के सामने अतिक्रमण, पसरा, ठेला-खोमचा और यातायात व्यवस्था का जायजा लिया गया। दुकानदारों को निर्धारित सीमा में रहकर व्यापार करने की समझाइश दी गई। साथ ही दुकानों के सामने 8म8 फीट की चूने से मार्किंग कराई गई, ताकि दुकान और ठेले निर्धारित दायरे में रहें तथा सड़क पर आवागमन बाधित न हो। महापौर एवं आयुक्त ने पुराना बस स्टैंड स्थित पार्किंग स्थल का भी निरीक्षण किया और अधिकारियों को त्योहार के दौरान वाहनों की आवाजाही एवं पार्किंग व्यवस्था सुचारू रखने के निर्देश दिए। महापौर अलका बाघमार ने व्यापारियों से अपील की कि वे दुकान का सामान सड़क पर न फैलाएं और निर्धारित मार्किंग के भीतर ही व्यवसाय करें।

वहीं, आयुक्त लीना कोसम ने बाजार विभाग एवं अतिक्रमण अमले को मार्किंग से बाहर दुकान लगाने, सामान फैलाने और सड़क पर वाहन खड़े करने वालों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई करने के निर्देश दिए। नियमों का उल्लंघन करने पर सामान जब्त करने और जुर्माना लगाने की चेतावनी भी दी गई। इंदिरा गांधी प्रतिमा के आसपास भी विशेष मार्किंग कराई गई है।

निगम प्रशासन का उद्देश्य त्योहार के दौरान बाजारों में स्वच्छता, यातायात और पार्किंग व्यवस्था बनाए रखना है, ताकि व्यापारियों के साथ ग्राहकों को भी खरीदारी में परेशानी न हो। निरीक्षण के दौरान लोक कर्म प्रभारी देव नारायण चन्द्राकर, एमआईसी सदस्य शेखर चन्द्राकर, निलेश अग्रवाल, खलीक रिजवी, स्वास्थ्य अधिकारी दुर्गेश गुप्ता, अतिक्रमण अधिकारी परमेश्वर कुमार सहित निगम के अधिकारी-कर्मचारी मौजूद रहे।

भिलाई विद्यालय में 41वां कब-बुलबुल उत्सव और 50वीं स्काउट्स-गाइड्स रैली का आयोजन

130 प्रतिभागियों ने लिया हिस्सा, सांस्कृतिक प्रस्तुतियों और विभिन्न प्रतियोगिताओं में दिखाया हुनर

यश भारत



भिलाई। भिलाई इस्पात संयंत्र के शिक्षा विभाग एवं भारत स्काउट्स एवं गाइड्स, जिला संघ भिलाई के संयुक्त तत्वावधान में 41वें कब-बुलबुल उत्सव एवं 50वीं स्काउट्स-गाइड्स रैली का आयोजन भिलाई विद्यालय, सेक्टर-2 में किया गया। 4 नवंबर को आयोजित कब-बुलबुल उत्सव में बीएसपी की विभिन्न शालाओं के लगभग 130 बच्चों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया।

कार्यक्रम का शुभारंभ महाप्रबंधक (शिक्षा) एवं जिला मुख्य आयुक्त श्रीमती शिखा दुबे ने ईश वंदना, ध्वजारोहण और ध्वज गीत के साथ किया। तीन दिवसीय स्काउट्स-गाइड्स रैली एवं कब-बुलबुल उत्सव का समापन कार्यपालक निदेशक (मानव संसाधन) पवन कुमार के मुख्य आतिथ्य तथा महाप्रबंधक प्रभारी (नगर सेवाएं) ए.बी. श्रीनिवास की विशेष उपस्थिति में हुआ।

मुख्य अतिथि पवन कुमार ने बच्चों की गतिविधियों और प्रस्तुतियों की सराहना करते हुए कहा कि स्काउटिंग एवं गाइडिंग अनुशासन, सेवा भावना और व्यक्तित्व विकास का महत्वपूर्ण माध्यम है। शिविर में प्राप्त सीख को बच्चों को अपने दैनिक जीवन में अपनाना चाहिए। वहीं ए.बी. श्रीनिवास ने कहा कि शिविर में अर्जित कौशल और अनुभव बच्चों को भविष्य की चुनौतियों का सामना करने में मदद करेंगे।

उत्सव के दौरान सामूहिक नृत्य, चित्रकला, बुलबुल ट्री, विविध वेशभूषा, गंध, स्वाद और गांठ बांधने सहित आठ प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं। बच्चों ने प्रकृति संरक्षण, बालिका शिक्षा, पर्यावरण जागरूकता और देशप्रेम जैसे विषयों पर अपनी रचनात्मक प्रतिभा दिखाई। स्काउट्स-गाइड्स एवं कब-बुलबुल ने सांस्कृतिक प्रस्तुतियों और ड्रिल के माध्यम से भी आकर्षक प्रदर्शन किया।

समारोह में विभिन्न प्रतियोगिताओं के विजेताओं को पुरस्कृत किया गया। साथ ही श्रेष्ठ स्काउट, श्रेष्ठ गाइड और श्रेष्ठ टुकड़ी को सम्मानित किया गया। जिला आयुक्त (स्काउट) एवं भिलाई विद्यालय सेक्टर-2 के प्राचार्य विजय सिंह पवार ने शिविर की गतिविधियों का विवरण प्रस्तुत किया।

कार्यक्रम में शिक्षा विभाग के अधिकारी, विभिन्न विद्यालयों के प्राचार्य, शिक्षक-शिक्षिकाएं एवं स्काउट्स-गाइड्स से जुड़े पदाधिकारी उपस्थित रहे। आयोजन के सफल संचालन में रोवर एवं रेंजर्स ने भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। कार्यक्रम का संचालन मनीष तिवारी एवं डॉ. शीतल चंद्र शर्मा ने किया।

पाहंदा (अ) में सरपंच के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव ध्वस्त, ईश्वरवती ठाकुर ने बचाई कुर्सी

21 पंचों के मतदान में प्रस्ताव के पक्ष में 11 और विरोध में पड़े 10 मत, निर्धारित बहुमत नहीं मिलने से प्रस्ताव हुआ निरस्त

पाटन। जनपद पंचायत पाटन के ग्राम पंचायत पाहंदा (अ) में सरपंच ईश्वरवती ठाकुर के खिलाफ लाया गया अविश्वास प्रस्ताव बुधवार को मतदान के बाद ध्वस्त हो गया। आवश्यक बहुमत नहीं मिलने के कारण सरपंच अपनी कुर्सी बचाने में सफल रहीं। ग्राम पंचायत भवन में पीठासीन अधिकारी एवं अतिरिक्त तहसीलदार पाटन मनोज रस्तोगी की अध्यक्षता में अविश्वास प्रस्ताव पर विशेष सम्मिलन आयोजित किया गया। मतदान में प्रस्ताव के पक्ष में 11 और विरोध में 10 मत पड़े। प्रस्ताव के पक्ष में एक मत अधिक होने के बावजूद निर्धारित वैधानिक बहुमत नहीं मिलने के कारण अविश्वास प्रस्ताव पारित नहीं हो सका। इस परिणाम के साथ ही सरपंच ईश्वरवती ठाकुर का पद सुरक्षित रहा। उल्लेखनीय है कि सरपंच के खिलाफ गंगाराम पटेल सहित अन्य पंचों ने अविश्वास प्रस्ताव की सूचना दी थी, जिसके बाद प्रशासन ने 4 नवंबर को विशेष सम्मिलन और मतदान की तिथि निर्धारित की थी।

ट्रक की चपेट में आने से बाइक सवार की मौत, एक घायल

राजनांदगांव। नेशनल हाईवे पर ग्राम बनभेड़ी स्थित दिल्ली पब्लिक स्कूल के सामने मंगलवार देर शाम सड़क दुर्घटना में बाइक सवार एक युवक की मौत हो गई, जबकि दूसरा घायल हो गया। हादसा शाम करीब पौने आठ बजे हुआ। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, बाइक सवार तुमड़ीबोड़ की ओर से राजनांदगांव आ रहे थे। इसी दौरान उनकी बाइक पीछे से आ रहे ट्रक की चपेट में आ गई। दुर्घटना में एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरा घायल हो गया। पुलिस ने शव को पेंड्री स्थित मेडिकल कॉलेज अस्पताल भेज दिया है। हादसे के बाद ट्रक चालक वाहन छोड़कर फरार हो गया। पुलिस ने मर्ग कायम कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। बता दें कि पिछले तीन महीनों में नेशनल हाईवे पर यह छठवीं मौत है।

खुड़मुड़ा में शराब दुकान खोलने पर अड़ा प्रशासन,

ग्रामीणों के विरोध के आगे फिर नहीं खुल पाई दुकान: राकेश ठाकुर

धरना स्थल पहुंचे कांग्रेस जिलाध्यक्ष, भाजपा सरकार पर साधा निशाना; ग्रामीणों की मांग पर दुकान खोलने का प्रस्ताव निरस्त करने की मांग

यश भारत



पाटन। नगर पालिका अमलेश्वर अंतर्गत ग्राम खुड़मुड़ा में शराब दुकान खोले जाने का विरोध लगातार जारी है। ग्रामीणों की असहमति के बावजूद प्रशासन द्वारा दोबारा शराब दुकान खोलने की तैयारी किए जाने से क्षेत्र में नाराजगी है। इसी बीच जिला कांग्रेस कमेटी दुर्ग ग्रामीण के अध्यक्ष राकेश ठाकुर धरना स्थल पहुंचे और आंदोलनरत ग्रामीणों के साथ खड़े होकर प्रशासन के प्रयासों का विरोध किया। ग्रामीणों के विरोध और जनदबाव के चलते मंगलवार को भी शराब दुकान नहीं खुल पाई।

गौरतलब है कि खुड़मुड़ा में शराब दुकान खोलने का प्रयास पहले भी किया गया था। उस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, कांग्रेस जिलाध्यक्ष राकेश ठाकुर सहित विभिन्न जनप्रतिनिधियों और ग्रामीणों ने विरोध दर्ज कराया था। व्यापक विरोध के चलते उस समय भी दुकान शुरू नहीं हो सकी थी। अब दोबारा प्रयास किए जाने से ग्रामीणों में आक्रोश है।

राकेश ठाकुर ने भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि एक ओर सरकार सुशासन और जनहित की बात करती है, वहीं दूसरी ओर जनता की इच्छा के विरुद्ध शराब दुकान खोलने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने सवाल उठाया कि जब ग्रामीण स्पष्ट रूप से शराब दुकान नहीं चाहते, तो प्रशासन बार-बार इसे खोलने की तैयारी क्यों कर रहा है? उन्होंने कहा कि ग्रामीणों का विरोध किसी राजनीतिक स्वार्थ से नहीं, बल्कि गांव के सामाजिक वातावरण, परिवारों और युवा पीढ़ी के भविष्य की चिंता से जुड़ा है। जनता की आपत्तियों को नजरअंदाज कर निर्णय थोपना लोकतांत्रिक व्यवस्था की भावना के विपरीत है।

राकेश ठाकुर ने प्रशासन से खुड़मुड़ा में शराब दुकान खोलने के प्रस्ताव को तत्काल निरस्त करने और ग्रामीणों को स्पष्ट आश्वासन देने की मांग की। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी ग्रामीणों के साथ खड़ी है और उनकी मांग पूरी होने तक लोकतांत्रिक तरीके से आंदोलन का समर्थन करती रहेगी।

इस दौरान महेंद्र साहू, ओमप्रकाश साहू, गिरधर साहू, डोमन यादव, धर्मेंद्र साहू, घनश्याम साहू, अमृत राजपूत, संदीप निर्मलकर, घनश्याम यादव, ओंकार घिंघोडे सहित सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण उपस्थित रहे।



दो वार्डों में 47.54 लाख के विकास कार्यों का महापौर ने किया भूमिपूजन

गायत्री मंदिर वार्ड में डामरीकरण और कसारीडीह में बॉक्स कल्वर्ट व सड़क निर्माण से मिलेगी राहत

यश भारत

दुर्ग । नगर निगम क्षेत्र में विकास कार्यों को गति देते हुए महापौर अलका बाघमार ने मंगलवार को गायत्री मंदिर वार्ड और कसारीडीह में कुल 47.54 लाख रुपये के विकास कार्यों का भूमिपूजन किया। 15वें वित्त आयोग मद से वार्ड क्रमांक 25 गायत्री मंदिर वार्ड में 8.32 लाख रुपये की लागत से डामरीकरण तथा वार्ड क्रमांक 43 कसारीडीह में सहगल ऑटो के पास कुर्मी भवन की ओर जाने वाले मार्ग पर 39.22 लाख रुपये की लागत से बॉक्स कल्वर्ट एवं सड़क निर्माण कराया जाएगा। इस अवसर पर महापौर अलका बाघमार ने कहा कि निगम की प्राथमिकता शहर के प्रत्येक वार्ड में बेहतर सड़क, नाली और मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराना है। इन कार्यों के पूर्ण होने से नागरिकों को आवागमन में सुविधा मिलेगी और क्षेत्र की आधारभूत संरचना मजबूत होगी। उन्होंने कहा कि शहर के सभी वार्डों में जरूरत के अनुसार विकास कार्यों को प्राथमिकता से कराया जा रहा है। भूमिपूजन कार्यक्रम में लोक कर्म प्रभारी देव नारायण चन्द्राकर, ज्ञानेश्वर ताम्रकार, पार्षद दीपक साहू, मनीषा सोनी, खालिक रिजवी, सहायक अभियंता हरिशंकर साहू, उप अभियंता अपर्णा मिश्रा, भारती ठाकुर सहित जनप्रतिनिधि एवं बड़ी संख्या में वार्डवासी उपस्थित रहे। नागरिकों ने विकास कार्यों की सौगात के लिए महापौर एवं निगम प्रशासन के प्रति आभार जताया।

छत्तीसगढ़ राज्योत्सव

वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग की प्रदर्शनी को प्रथम पुरस्कार

'बदलता बस्तर-संवरता छत्तीसगढ़' थीम पर आधारित प्रदर्शनी में वन संरक्षण, पर्यटन और आजीविका की पहल को मिला सम्मान

बस्तर में बदलाव की तस्वीर से लेकर वन्यजीव संरक्षण और डिजिटल नवाचारों की दिखी झलक

यश भारत

रायपुर । छत्तीसगढ़ राज्य स्थापना की 26वीं वर्षगांठ पर नवा रायपुर में आयोजित राज्योत्सव 2026 में वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग की प्रदर्शनी को विभागीय प्रदर्शनियों की श्रेणी में प्रथम पुरस्कार प्राप्त हुआ है। राज्योत्सव के समापन एवं राज्य अलंकरण समारोह में मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने यह सम्मान प्रदान किया। विभाग की ओर से अपर मुख्य सचिव श्री मनोज कुमार पिंगुआ और प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख श्री अरुण कुमार पांडेय ने पुरस्कार प्राप्त किया। वन मंत्री श्री केदार कश्यप ने इस उपलब्धि पर विभागीय अधिकारियों- कर्मचारियों और वन धन केंद्रों से जुड़े सदस्यों को बधाई दी।

गौरतलब है कि वन मंत्री श्री केदार कश्यप के मार्गदर्शन में 'बदलता बस्तर-संवरता छत्तीसगढ़' थीम पर तैयार प्रदर्शनी में बस्तर में शांति के साथ बढ़ते पर्यटन और आजीविका के अवसरों से लेकर प्रदेश में वन एवं वन्यजीव संरक्षण की पहलों को आकर्षक ढंग से प्रस्तुत किया गया।

प्रदर्शनी को दो प्रमुख हिस्सों में विभाजित किया गया था। प्रवेश द्वार पर जगदलपुर के जनजातीय गौरव वाटिका, बीजापुर स्थित इंद्रावती टाइगर रिजर्व के चेंदरू गेट और दंतेवाड़ा के वन मंदिर के प्रतिरूप बनाए गए थे। इनके माध्यम से बस्तर की जनजातीय संस्कृति, प्रकृति के प्रति आस्था और वन्यजीवों के साथ सह-अस्तित्व की परंपरा को प्रदर्शित किया गया।

'बदलता बस्तर' खंड में सुकमा के तुंगल डैम स्थित 'तुंगल कैफे' की पहल विशेष आकर्षण रही। यहां मुख्यधारा में लौट चुकी पूर्व महिला नक्सली कैफे का संचालन कर रही हैं, जबकि स्थानीय युवा पर्यटकों को नौकायन और कयाकिंग की सुविधा उपलब्ध कराकर आजीविका अर्जित कर रहे हैं। प्रदर्शनी में इस पहल के माध्यम से बस्तर में बदलते सामाजिक परिवेश और रोजगार के नए अवसरों को सामने रखा गया।

इसके साथ ही कांगेर घाटी के समीप धुड़मारास गांव के होमस्टे, कोंडागांव की पुष्पाल घाटी के इको-कॉटेज, तीरथगढ़ जलप्रपात और इंद्रावती टाइगर रिजर्व के मड़ीमरका क्षेत्र के मॉडल प्रदर्शित किए गए। धुड़मारास गांव का चयन संयुक्त राष्ट्र पर्यटन संगठन के 'बेस्ट टूरिज्म



विलेज अपग्रेड प्रोग्राम' में हुआ है।

प्रदर्शनी में बस्तर की 572 देवगुड़ियों के जीर्णोद्धार, मनरेगा के अंतर्गत 21.67 लाख मानव दिवस रोजगार सृजन तथा कांगेर वैली में 35 सफारी जिप्सियों के संचालन से 200 स्थानीय युवाओं को प्रत्यक्ष रोजगार मिलने की जानकारी भी दी गई।

'संवरता छत्तीसगढ़' भाग में प्रदेश की जैव विविधता और वन्यजीव संरक्षण के प्रयासों को त्रिआयामी मॉडल एवं जीवंत प्रदर्शनों के माध्यम से प्रस्तुत किया गया। इसमें बिलासपुर के कोपरा जलाशय को दिसंबर 2025 में प्रदेश के पहले रामसर स्थल के रूप में मिली मान्यता, बारनवापारा अभयारण्य में दशकों बाद काले हिरणों की रिलोकेशन और औरापानी में गिद्ध संरक्षण के प्रयास प्रमुखता से प्रदर्शित किए गए। बारनवापारा में काले हिरणों के पुनर्व्यवस्थापन की सराहना प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 'मन की बात' कार्यक्रम में भी की थी।

मानव-हाथी द्वंद्व प्रबंधन के लिए 'गजरथ यात्रा' जागरूकता अभियान और 'गज संकेत' ऐप का प्रदर्शन किया गया। यह ऐप हाथियों की आवाजाही की जानकारी ग्रामीणों तक वॉयस कॉल, एसएमएस और व्हाट्सऐप के माध्यम से पहुंचाता है।

वृक्षारोपण की उपलब्धियों में 'एक पेड़ मां के नाम' अभियान के अंतर्गत वर्ष 2024 में 3.50 करोड़ और वर्ष 2025 में 3.55 करोड़ पौधों के रोपण की जानकारी दी गई। इसी तरह किसान वृक्ष मित्र योजना के अंतर्गत 36 हजार 896 किसानों द्वारा 62 हजार 441 एकड़ क्षेत्र में 3.67 करोड़ पौधे लगाने की जानकारी प्रस्तुत की गई।

प्रदर्शनी में क्यूआर कोड आधारित वन्यजीव प्रश्नोत्तरी, इंटरैक्टिव गेम, 360 डिग्री वर्चुअल रियलिटी, लाइट एंड साउंड प्रभाव तथा सेल्फी प्वाइंट दर्शकों, विशेषकर युवाओं के आकर्षण का केंद्र रहे। क्यूआर कोड स्कैन कर दर्शकों ने विभाग की विशेष वेबसाइट के माध्यम से वानिकी योजनाओं और प्रदेश के इको-टूरिज्म स्थलों की जानकारी प्राप्त की।

संयुक्त वन प्रबंधन के स्टॉल पर ग्रामीण कारीगरों द्वारा निर्मित बांस के घर, नाव, लालटेन और सजावटी वस्तुओं की बिक्री हुई। 'छत्तीसगढ़ हर्बल्स' के स्टॉल पर वन मधु, सफेद मूसली, त्रिफला चूर्ण, एलोवेरा शैम्पू और महाभृंगराज तेल जैसे वन धन केंद्रों में तैयार उत्पादों ने भी लोगों को आकर्षित किया। राज्य औषधीय पादप बोर्ड ने घरेलू बाड़ियों में सिंगी और शतावरी जैसी औषधीय वनस्पतियों की खेती से ग्रामीण महिलाओं के लिए सालाना 20 से 30 हजार रुपए की अतिरिक्त आय की संभावनाओं को प्रदर्शित किया।

अपेक्स बैंक रायपुर के बोर्ड की शक्तियों का प्रयोग करने के लिए गठित कमेटी में बदलाव

यश भारत

रायपुर । छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी बैंक मर्यादित (अपेक्स बैंक), रायपुर के बोर्ड की शक्तियों का प्रयोग करने के लिए गठित कमेटी में बदलाव किया गया है। पंजीयक सहकारी संस्थाएं रमेश कुमार शर्मा ने केदार नाथ गुप्ता को अध्यक्ष और जगदलपुर निवासी शिव नारायण पाण्डेय को उपाध्यक्ष नामांकित किया है। इस संबंध में 2 नवंबर 2026 को आदेश जारी किया गया है। नई कमेटी अगले आदेश तक अपेक्स बैंक के बोर्ड की शक्तियों का प्रयोग करेगी।

केदार नाथ गुप्ता अध्यक्ष बने रहेंगे- पंजीयक सहकारी संस्थाएं के कार्यालयीन आदेश के अनुसार, 21 मई 2025 को जारी आदेश के तहत केदार नाथ गुप्ता को अपेक्स बैंक के बोर्ड की शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत किया गया था। अब पुराने आदेश में संशोधन करते हुए



अशासकीय व्यक्तियों की कमेटी गठित की गई है। इसमें केदार नाथ गुप्ता को अध्यक्ष और शिव नारायण पाण्डेय को उपाध्यक्ष नामांकित किया गया है।

छानबीन समिति की अनुशंसा पर फैसला- छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 की धारा 49 (8) और छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी नियम 1962 के नियम 43-ख के उपनियम (3) के तहत गठित छानबीन समिति की बैठक 2 नवंबर 2026 को हुई थी। बैठक में शिव नारायण पाण्डेय को सदस्य नामांकित किए जाने की अनुशंसा की गई। इसी अनुशंसा के आधार पर पंजीयक ने कमेटी में उन्हें उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी दी है।

अगले आदेश तक कमेटी करेगी बोर्ड की शक्तियों का प्रयोग- जारी आदेश में कहा गया है कि छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 की धारा 49 (8) के तहत गठित कमेटी आगामी आदेश तक अपेक्स बैंक के बोर्ड की शक्तियों का प्रयोग करेगी। कमेटी में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के नामांकन के साथ पूर्व में जारी आदेश में संशोधन किया गया है।

लोकतंत्र को सबसे बड़ा खतरा कांग्रेस और इंडी गठबंधन की दोहरी राजनीति से- देव साय

लोकतंत्र की हत्या करने वाली कांग्रेस आज लोकतंत्र बचाने की बात कर रही है, इससे बड़ा राजनीतिक विरोधाभास क्या होगा : मुख्यमंत्री साय

आपातकाल लगाकर लोकतांत्रिक अधिकारों का दमन करने और चुनी हुई सरकारों को बर्खास्त करने का कांग्रेस का रहा है इतिहास

चुनाव हारने पर ईवीएम और निर्वाचन आयोग पर सवाल, जीतने पर उन्हीं संस्थाओं पर भरोसा कांग्रेस की दोहरी नीति : मुख्यमंत्री



कांग्रेस और इंडी गठबंधन की दोहरी राजनीति से जनता को अवगत कराने के लिए आयोजित की जा रही %लोकतंत्र बचाओ, अराजकता हटाओ% पदयात्रा

महादेव सट्टा ऐप मामले में सौरभ चंद्राकर से सीबीआई की पूछताछ में हो सकते हैं कई बड़े खुलासे : मुख्यमंत्री श्री साय

सौरभ चंद्राकर को हीरो बताने संबंधी अमित जोगी के बयान पर मुख्यमंत्री श्री साय का तीखा पलटवार, कहा - ऐसे बयान उनकी सोच और मानसिकता को

यश भारत

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कांग्रेस और इंडी गठबंधन पर तीखा राजनीतिक प्रहार करते हुए कहा है कि देश के लोकतंत्र को सबसे बड़ा खतरा उन लोगों से है, जिन्होंने अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए बार-बार लोकतांत्रिक मूल्यों और संवैधानिक व्यवस्थाओं को कमजोर करने का काम किया है। उन्होंने कहा कि जिस कांग्रेस ने देश में आपातकाल लगाकर लोकतंत्र का गला घोंटा, विपनेताओं को जेलों में डाला और मीडिया की स्वतंत्रता छीन ली, आज वही कांग्रेस लोकतंत्र बचाने की बात कर रही है। यह अपने आप में बेहद हास्यास्पद और कांग्रेस की दोहरी राजनीति का परिचायक है। मुख्यमंत्री साय ने आज जशपुर में आयोजित %लोकतंत्र बचाओ, अराजकता हटाओ% पदयात्रा में शामिल होने के लिए रवाना होने से पूर्व पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए कहा कि कांग्रेस का इतिहास लोकतांत्रिक संस्थाओं और जनादेश के प्रति उसके वास्तविक रवैये को उजागर करता है। आपातकाल के दौरान कांग्रेस ने देश के गैर-कांग्रेसी नेताओं को जेलों में डालने और प्रेस की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाने का काम किया। इतना ही नहीं, कांग्रेस ने कई अवसरों पर संविधान के अनुच्छेद 356 का दुरुपयोग कर जनता द्वारा चुनी गई गैर-कांग्रेसी सरकारों को बर्खास्त किया। आज उसी कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों द्वारा लोकतंत्र की दुहाई देना राजनीतिक अवसरवादिता की पराकाष्ठा है। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि कांग्रेस और इंडी गठबंधन के नेता अपनी चुनावी पराजय को स्वीकार करने के बजाय संवैधानिक संस्थाओं की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े करते हैं। कभी वोट चोरी का आरोप लगाते हैं, कभी विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) की प्रक्रिया पर प्रश्नचिह्न लगाते हैं और कभी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) तथा निर्वाचन आयोग को कटघरे में खड़ा करने का प्रयास करते हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की दोहरी नीति का सबसे बड़ा उदाहरण यह है कि जब चुनाव परिणाम उनके पक्ष में आते हैं, तब उन्हें उसी ईवीएम और उसी निर्वाचन आयोग पर पूरा भरोसा होता है, लेकिन जब जनता उन्हें नकार देती है, तो वे अपनी हार का ठीकरा संवैधानिक संस्थाओं पर फोड़ने लगते हैं। लोकतांत्रिक व्यवस्था के प्रति यह दोहरा रवैया कांग्रेस की राजनीतिक हताशा को दर्शाता है। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि कांग्रेस और इंडी गठबंधन की इसी दोहरी राजनीति को जनता के सामने उजागर करने तथा लोकतंत्र और संवैधानिक संस्थाओं के प्रति जनजागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से %लोकतंत्र बचाओ, अराजकता हटाओ% पदयात्रा का आयोजन किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जनता को यह जानने का अधिकार है कि लोकतंत्र की रक्षा की बात करने वालों का अपना राजनीतिक इतिहास क्या रहा है।

महादेव सट्टा ऐप मामले में सीबीआई की पूछताछ से सामने आ सकते हैं कई बड़े नाम

महादेव ऑनलाइन सट्टा ऐप मामले में पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा कि इस प्रकरण के मुख्य अभियुक्त सौरभ चंद्राकर को विदेश से लाया गया है। अब सीबीआई उससे पूछताछ करेगी, जिससे इस पूरे मामले से जुड़े कई महत्वपूर्ण तथ्य सामने आ सकते हैं। उन्होंने संभावना जताई कि जांच के दौरान इस अवैध कारोबार से जुड़े अन्य लोगों की भूमिका भी उजागर हो सकती है। मुख्यमंत्री साय ने अमित जोगी द्वारा सौरभ चंद्राकर को लेकर दिए गए बयान पर भी तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की। उन्होंने कहा कि अमित जोगी सौरभ चंद्राकर को हीरो बता रहे हैं। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि ऐसे बयान संबंधित नेताओं की तुच्छ सोच को स्वयं उजागर करते हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे व्यक्ति को हीरो बताने के पीछे कैसी सोच काम कर रही है, इसका आकलन प्रदेश की जनता स्वयं कर सकती है।

नक्सल प्रभावित सुकमा के 50 ग्रामीण पहली बार ट्रेन से पहुंचे गुजरात, प्रधानमंत्री की मौजूदगी में राष्ट्रीय एकता परेड के बने साक्षी

यश भारत

रायपुर। बस्तर के जंगलों से निकलकर गुजरात के एकता नगर तक पहुंची यह यात्रा केवल 50 ग्रामीणों का सफर नहीं थी, बल्कि बदलते सुकमा की एक ऐसी तस्वीर थी, जिसमें पहली बार ट्रेन में बैठने का उत्साह भी था और देश के सबसे बड़े राष्ट्रीय आयोजनों में से एक का हिस्सा बनने का गौरव भी। कभी नक्सल चुनौती के कारण चर्चा में रहने वाले सुकमा के ग्रामीणों ने गुजरात के केवड़िया में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गरिमामयी उपस्थिति में आयोजित राष्ट्रीय एकता दिवस समारोह और भव्य परेड को अपनी आंखों से देखा।

जब परेड में छत्तीसगढ़ पुलिस के ष्ठत्रन्न और STF के जवानों ने कदमताल की, तो सुकमा से पहुंचे ग्रामीणों ने तालियों की गूंज के साथ उनका उत्साह बढ़ाया। सुकमा जिले के अलग-अलग गांवों से आए 50 नागरिकों के इस दल के लिए गुजरात की यात्रा कई मायनों में खास रही। इनमें बड़ी संख्या ऐसे ग्रामीणों की थी, जिन्होंने अपने जीवन में पहली बार ट्रेन से सफर किया। गांवों की परिचित सीमाओं से बाहर निकलकर लंबी रेल यात्रा करना, नए प्रदेश को देखना और राष्ट्रीय स्तर के भव्य समारोह में शामिल होना उनके लिए एक नया अनुभव था। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के सानिध्य में आयोजित राष्ट्रीय एकता परेड ने इस यात्रा को यादगार बना दिया।



एकता नगर में आयोजित समारोह के दौरान ग्रामीणों ने छत्तीसगढ़ पुलिस के उन जवानों को परेड में हिस्सा लेते देखा, जो बस्तर के चुनौतीपूर्ण क्षेत्रों में सुरक्षा और शांति बनाए रखने की जिम्मेदारी निभाते हैं।

DRG और STF के जवानों की अनुशासित कदमताल ने ग्रामीणों को गौरवान्वित किया। अपने ही प्रदेश के जवानों को राष्ट्रीय मंच पर प्रतिनिधित्व करते देख उन्होंने तालियां बजाकर उनका मनोबल बढ़ाया। यह उनके लिए केवल परेड देखना नहीं, बल्कि अपने क्षेत्र के जवानों के योगदान को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिलने का अनुभव भी था। इस विशेष यात्रा का आयोजन पुलिस अधीक्षक सुकमा मयंक गुर्जर (भापुसे) के निर्देशन और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मनोज तिर्की के मार्गदर्शन में किया गया। उप पुलिस अधीक्षक सपन चौधरी के नेतृत्व में 50 सदस्यीय दल गुजरात पहुंचा। यात्रा के दौरान ग्रामीणों को राष्ट्रीय एकता समारोह में भाग लेने के साथ स्टैच्यू ऑफ यूनिटी देखने और गुजरात की संस्कृति तथा परिवेश से परिचित होने का अवसर मिला।

लौटे सभी 50 नागरिकों का पुलिस अधीक्षक मयंक गुर्जर ने अपने कार्यालय में आत्मीय स्वागत किया। उन्होंने प्रत्येक सदस्य को पुष्पगुच्छ भेंट कर अभिनंदन किया और उनसे यात्रा के अनुभव सुने। ग्रामीणों ने बताया कि पहली बार ट्रेन में बैठने से लेकर प्रधानमंत्री की उपस्थिति में आयोजित राष्ट्रीय समारोह देखने तक, यह पूरी यात्रा उनके जीवन की अविस्मरणीय स्मृति बन गई है। दल के सदस्यों ने इस अवसर के लिए सुकमा पुलिस और छत्तीसगढ़ शासन के प्रति आभार व्यक्त किया। उनके लिए यह यात्रा केवल गुजरात भ्रमण नहीं, बल्कि अपने गांव से निकलकर देश की विविधता, एकता और राष्ट्रीय गौरव को करीब से देखने गुजरात प्रवास के बाद सुकमा का अवसर बन गई।

स्मार्ट सिटी ड्रेनेज घोटाले की लीपापोती के लिए 2.96 करोड़ का डामरीकरण; पहले चौड़ीकरण और ड्रेनेज ऑडिट कराएं: मनोज सिंह ठाकुर

यश भारत

रायपुर । वामनराव लाखे वार्ड (क्र. 66) के अंतर्गत कुशालपुर-प्रोफेसर कॉलोनी मार्ग पर 296.85 लाख (लगभग 3 करोड़ रुपए) की लागत से कराए जा रहे डामरीकरण के भूमिपूजन पर अधिवक्ता एवं छत्तीसगढ़ श्रम कल्याण मंडल के पूर्व सदस्य मनोज सिंह ठाकुर ने कड़ा रुख अपनाया है। उन्होंने हाल ही में स्मार्ट सिटी मिशन को लेकर केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय से सूचना के अधिकार के तहत मिले आधिकारिक खुलासों के हवाले से जनप्रतिनिधियों और प्रशासन की मिलीभगत पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। मनोज सिंह ठाकुर ने भूमिपूजन में शामिल सांसद बृजमोहन अग्रवाल, विधायक सुनील सोनी और महापौर मीनल चौबे से सीधा सवाल किया कि करोड़ों के ड्रेनेज घोटाले पर चुप्पी साधकर केवल डामर की लीपापोती किसके दबाव में की जा रही



है?RTI से उजागर हुआ था ड्रेनेज घोटाला-अधिवक्ता मनोज सिंह ठाकुर ने आधिकारिक दस्तावेज़ों का हवाला देते हुए बताया कि स्मार्ट सिटी मिशन के तहत वर्ष 2021-22 में निष्पादित कुशालपुर-संतोषी नगर-सुंदर नगर ड्रेनेज प्रोजेक्ट का अनुबंध समय-सीमा बीतने के बाद भी अधूरा रहा। इसके बावजूद स्मार्ट सिटी प्रशासन ने ठेकेदारों पर 'शून्य' (Nil) पेनाल्टी लगाई और बिना थर्ड-पार्टी क्वालिटी ऑडिट व भौतिक सत्यापन के कागजों पर 100त्न फंड व्यय दिखा दिया। नतीजा यह है कि आज भी सामान्य बारिश में कुशालपुर, संतोषी नगर और प्रोफेसर कॉलोनी में नाली का गंदा पानी घरों और सड़कों पर भर जाता है।

सड़क चौड़ीकरण और अतिक्रमण हटाने से परहेज क्यों?

उन्होंने कहा कि गोपिया पारा से माँ दंतेश्वरी मंदिर, संतोषी चौक, तिरंगा चौक होते हुए रिंग रोड तक का मार्ग अत्यंत संकरा हो चुका है। दिन-रात भीषण जाम से स्कूली बच्चे, एंबुलेंस और आम नागरिक त्रस्त हैं। बिना अतिक्रमण हटाए और सड़क को चौड़ा किए सिर्फ डामर पोत देना न तो जाम खत्म करेगा और न ही जलभराव रोकेगा। पहली ही बारिश में यह ?2.96 करोड़ जनता के टैक्स का पैसा नाले में बह जाएगा। प्रमुख मांगें-ड्रेनेज का ऑडिट एवं EOW जांच- कुशालपुर-संतोषी नगर स्मार्ट सिटी ड्रेनेज में कागजी भुगतान और शून्य पेनाल्टी की निष्पक्ष जांच हो। पहले चौड़ीकरण, फिर डामरीकरण- अतिक्रमण हटाकर सड़क को मास्टर प्लान के अनुसार चौड़ा किया जाए और भूमिगत जलनिकासी सुनिश्चित करने के बाद ही डामर बिछाया जाए। जनता के पैसे की बर्बादी पर रोक- जलभराव की स्थिति ठीक किए बिना डामर बिछाने वाले ज़िम्मेदार अधिकारियों व जनप्रतिनिधियों की जवाबदेही तय हो।मनोज सिंह ठाकुर ने चेतावनी दी कि यदि कागजी लीपापोती को रोककर बुनियादी समस्याओं का समाधान नहीं किया गया, तो वे क्षेत्रवासियों के साथ मिलकर उग्र आंदोलन करेंगे और इस विषय को विधिक मंच तक ले जाएंगे।

वार्ड 47 में 35 लाख से अधिक के नये विकास कार्यों का भूमिपूजन संपन्न

आंगनबाडी भवन के ऊपरी तल पर निर्माण हेतु उत्तर विधायक ने विधायक निधि से 10 लाख का स्वेच्छानुदान देने की घोषणा की

रायपुर। रायपुर उत्तर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत नगर पालिक निगम रायपुर जोन कमांक 3 क्षेत्र अंतर्गत मदर टेरेसा वार्ड क्रमांक 47 क्षेत्र अंतर्गत तेलीबांधा बीएसयूपी कालोनी में नवनिर्मित आंगनबाडी भवन एवं उद्यान निर्माण कार्य का पार्षद निधि एवं सामान्य मद से 16 लाख रू. की स्वीकृत लागत से लोकार्पण कर रायपुर उत्तर विधायक पुरंदर मिश्रा और नगर पालिक निगम रायपुर की महापौर मीनल चौबे और सभापति सूर्यकांत राठौड ने लोककर्म विभाग अध्यक्ष दीपक जायसवाल, वार्ड 47 पार्षद एवं जलविभाग अध्यक्ष संतोष साहू, जोन 3 अध्यक्ष साधना साहू,पार्षद प्रदीप वर्मा, महेश ध्रुव, एल्डरमेन राजू राघवानी, मित्रसेन धीमान, नगर निगम रायपुर के पूर्व पार्षद डॉ. प्रमोद साहू, सीमा साहू सहित बडी संख्या में महिलाओ, गणमान्यजनो, सामाजिक कार्यकर्ताओं, नवयुवको, आमजनो और नगर निगम जोन 3 जोन कमिश्नर खीरसागर नायक, कार्यपालन अभियंता ईश्वर लाल टावरे, सहायक अभियंता नरेश कुमार साहू की उपस्थिति में नागरिको को शानदार सौगात दी। रायपुर उत्तर विधायक पुरंदर मिश्रा, महापौर मीनल चौबे, सभापति सूर्यकांत राठौड ने लोककर्म विभाग अध्यक्ष दीपक जायसवाल, वार्ड पार्षद व एमआईसी सदस्य संतोष साहू, जोन 3 अध्यक्ष साधना साहू, पार्षद प्रदीप वर्मा, महेश ध्रुव, एल्डरमेन राजू राघवानी, मित्रसेन धीमान की उपस्थिति में मदर टेरेसा वार्ड कमांक 47 अंतर्गत अधोसंरचना मद से सरदार प्रीतम सिंह सैनी स्कूल में आवश्यक मरम्मत एवं जीर्णोद्धार कार्य 6 लाख 70 हजार में, कपूर होटल के सामने गोंदपारा में सीसी नाली एवं पुलिया निर्माण कार्य 9 लाख 52 हजार रू. में, सामान्य मद अंतर्गत श्यामनगर आदि जगहों पर श्रीफल फोड़कर एवं कुदाल चलाकर नये विकास कार्यों का भूमिपूजन करते हुए नागरिको को शानदार सौगात दी ।

संपादकीय

आरोपों की राजनीति बनाम जमीनी हकीकत

वोट चोरी के आरोपों से कितना बदल पाएगा देश का सियासी मिजाज?

भारतीय राजनीति इन दिनों आरोप-प्रत्यारोप के एक ऐसे दौर से गुजर रही है, जहां लोकतंत्र, चुनावी पारदर्शिता और संवैधानिक संस्थाओं की विश्वसनीयता राजनीतिक संघर्ष के केंद्र में आ गई है। दिल्ली के रामलीला मैदान में विपक्ष के 21 राजनीतिक दलों की भागीदारी वाली वोट चोरी रैली के बाद सियासी माहौल और गरमा गया है। विपक्ष इसे लोकतंत्र बचाने की लड़ाई बता रहा है, तो सत्तापक्ष इन आरोपों को राजनीतिक हताशा और जनता के जनादेश को नकारने की कोशिश के रूप में देख रहा है। रैली की सफलता और उसमें जुटी भीड़ को लेकर भले ही दोनों पक्ष अपने-अपने दावे कर रहे हों, लेकिन इस पूरे घटना म ने एक बड़ा सवाल जरूर खड़ा किया है कि क्या चुनावी प्र िया वास्तव में संदेह के घेरे में है या फिर लोकतांत्रिक व्यवस्था से जुड़े मुद्दों को राजनीतिक लड़ाई का हथियार बनाया जा रहा है?कांग्रेस सहित विपक्षी दलों के नेता, विशेषकर राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे, मतदाता सूची में कथित गड़बड़ियों को लेकर चुनाव आयोग पर लगातार सवाल उठा रहे हैं। विपक्ष का दावा है कि मतदाता सूचियों से करोड़ों नाम हटाए गए और इसका चुनावी परिणामों पर असर पड़ा। उसका तर्क है कि जब जीत और हार का अंतर कई सीटों पर बेहद कम था, तब मतदाता सूची में बड़े पैमाने पर हुई कथित कटौती को सामान्य प्रशासनिक प्र िया मानकर नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, लेकिन इस पूरे आरोप की पड़ताल करते समय कुछ बुनियादी सवालों का जवाब भी जरूरी है। यदि विपक्ष 2024 के लोकसभा चुनाव को व्यापक स्तर पर अवैध और धांधलीपूर्ण मानता है, तो क्या उस चुनाव से निर्वाचित केवल भाजपा के सांसदों का जनादेश ही संदिग्ध होगा? क्या विपक्ष के 99 सांसदों और स्वयं नेता प्रतिपक्ष का निर्वाचन भी उसी कसौटी पर नहीं आएगा? आखिर जिस चुनावी प्र िया पर सवाल उठाए जा रहे हैं, उसी प्र िया से विपक्ष को भी संसद में प्रतिनिधित्व मिला है। ऐसे में आरोपों की गंभीरता के साथ उनके तार्किक आधार को भी स्पष्ट करना आवश्यक है। यह भी ध्यान देने योग्य है कि चुनाव में भाजपा को लगभग 38 प्रतिशत मत मिले, जबकि कांग्रेस का मत प्रतिशत करीब 21 प्रतिशत रहा। हालांकि, मत प्रतिशत अपने आप में चुनावी प्र िया की निष्पक्षता का प्रमाण नहीं हो सकता, लेकिन जनादेश का आकलन करते समय इसे भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। चुनावी अनियमितताओं के आरोपों की जांच तथ्यों और प्रमाणों के आधार पर होनी चाहिए, न कि केवल राजनीतिक दावों के आधार पर। दूसरी ओर, मतदाता सूचियों को दुरुस्त करने के लिए चल रही एसआईआर जैसी प्र िया को भी केवल राजनीतिक चश्मे से देखना उचित नहीं होगा। मतदाता सूची में मृत व्यक्ति यों के नाम, दोहरे पंजीकरण और स्थान परिवर्तन के कारण मौजूद त्रुटियों को दूर करना किसी भी स्वस्थ लोकतंत्र के लिए जरूरी है। लेकिन इसके साथ यह सुनिश्चित करना भी चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है कि किसी भी वास्तविक मतदाता का नाम बिना उचित प्र िया और सूचना के सूची से बाहर न हो। सुधार की प्र िया और मताधिकार की सुरक्षा, दोनों एक-दूसरे के पूरक होने चाहिए। यहां चुनाव आयोग की जवाबदेही भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। आयोग एक संवैधानिक संस्था है और उसकी निष्पक्षता पर जनता का भरोसा लोकतंत्र की बुनियादी शर्त है। इसलिए विपक्ष के सवालों को केवल राजनीतिक बयानबाजी कहकर खारिज करना भी उचित नहीं होगा। यदि किसी स्तर पर गड़बड़ी हुई है तो उसका पारदर्शी तरीके से जवाब सामने आना चाहिए। लोकतंत्र में सवाल पूछने का अधिकार विपक्ष को है और उन सवालों का तथ्यात्मक जवाब देना संस्थाओं की जिम्मेदारी है। हालांकि, इस पूरे विवाद का एक दूसरा पहलू भी है। क्या वोट चोरी का मुद्दा आम नागरिक की रोजमर्रा की चिंता बन पाया है? महंगाई, बेरोजगारी, सड़क, बिजली, पानी, स्वास्थ्य और स्थानीय अव्यवस्थाओं से जूझ रहे आम आदमी के लिए चुनावी प्र िया का सवाल निश्चित रूप से महत्वपूर्ण है, लेकिन क्या यह उसकी प्राथमिक चिंताओं में शामिल हो पाया है? विपक्ष की लगातार कोशिशों के बावजूद इस मुद्दे को लेकर देशव्यापी जनभावना कितनी मजबूत हुई है, इसका आकलन केवल रैलियों और राजनीतिक भाषणों से नहीं किया जा सकता। दरअसल, भारतीय राजनीति में अब आरोपों की विश्वसनीयता का फैसला केवल मंचों से नहीं, बल्कि जनता के बीच उनके प्रभाव से भी होगा। विपक्ष को अपने आरोपों के समर्थन में ठोस प्रमाण और तथ्य प्रस्तुत करने होंगे, वहीं सत्तापक्ष और चुनाव आयोग को भी पारदर्शिता के साथ संदेह दूर करने होंगे। लोकतंत्र केवल चुनाव जीतने या हारने का नाम नहीं है। उसकी असली ताकत निष्पक्ष चुनाव, मजबूत संस्थाओं और जनता के अटूट विश्वास में निहित है। इसलिए सवाल यह नहीं कि वोट चोरी का आरोप कौन लगा रहा है और उसका राजनीतिक लाभ किसे मिलेगा, बल्कि असली सवाल यह है कि क्या देश की चुनावी व्यवस्था पर उठ रहे सवालों का विश्वसनीय समाधान सामने आ रहा है? आखिर लोकतंत्र में आरोपों से राजनीति तो गर्म हो सकती है, लेकिन जनता का भरोसा केवल तथ्यों, पारदर्शिता और जवाबदेही से ही कायम रह सकता है।

कड़वे वचन



जीवन का यहनियम याद रखो। जो आप देने वाले हैं वह आपके पास लौटके आने वाला है। कई गुना बढ़कर आने वाला है। हर किसान यह नियम जानता है, मानता है और इस पर काम करता है। वह खेत में अच्छे व बेहतरीन बीज डालता है और फसल आने का इंतजार करता है। किसान यह जानता है मगर अफसोस है कि इंसान यह नहीं जानता। दिया कभी बेकार नहीं जाता । याद रखो दे जाना ही ल जाने का मार्ग है।

आज का राशिफल



ज्योतिषाचार्य पंडित लोकेश व्यास

पंचांगः-5 नवम्बर, 2026
दिन-गुरुवार, अश्विन शुक्ल 10
विक्रम संवत 2083

मेष चू, चे, चो, ला, ली, लू, ले, लो, आ
दिन सामान्य रहने वाला है किसी की मदद करने से खुशी मिलेगी

वृष इ, उ, ए, ओ, वा, वी, वू, वे, वो
किसी विशेष कार्य को करने में दिन व्यतीत होगा लोगों की प्रशंसा मिल सकती है

मिथुन का, की, कू, घ, ङ, छ, के, को, ह
आत्मविश्वास में बढ़ोतरी होगी दिन खुशनुमा रहने वाला है

कर्क ही, हू, हे, हो, डा, डी, डू, डे, डो
मानसिक उलझनें कम हो सकती हैं खर्चों की अधिकता बनी रहेगी

सिंह मा, मी, मू, मे, मो, टा, टी, टू, टे
दिन अनुकूल रहने वाला है माता-पिता का आशीर्वाद लेकर कार्य करें

कन्या ढो, पा, पी, पू, ष, ण, ठ, पे, पो
धन लाभ होने के संकेत मिल रहे हैं परिवार के साथ समय व्यतीत कर सकते हैं

तुला रा, री, रू, रे, रो, ता, ती, तू, ते
दिन उत्तम रहने वाला है सामाजिक कार्यों में गतिविधियां बढ़ेगी

वृश्चिक ये, यो, भा, भी, भू, धा, फा, ढा, भे
स्वास्थ्य में पहले से अब सुधार होगा योग प्राणायाम अवश्य करें

धनु ये, यो, भा, भी, भू, धा, फा, ढा, भे
घर में शुभ मांगलिक कार्य हो सकते हैं मन प्रफुल्लित रहेगा

मकर भो, जा, जी, खी, खू, खे, खो, गा, गी
साझेदारी के काम को सोच समझ कर आगे बढ़ाएं क्रोध में नियंत्रण रखें

कुंभ गू, गे, गो, सा, सी, सू, से, सो, दा
खर्चों की अधिकता की वजह से आर्थिक स्थिति प्रभावित रहेगी

मीन दी, दू, थ, झ, ञ, दे, दो, चा, ची
वाणी में नियंत्रण रखकर कार्य करें दिन सामान्य रहने वाला है

नदियों की गाद से बनेंगे राष्ट्रीय राजमार्ग, बिहार के विकास को मिलेगी नई गति

'नदी संजीवनी' पहल से बाढ़ नियंत्रण, जलाशयों के पुनर्जीवन और सड़क निर्माण को जोड़ने की ऐतिहासिक पहल

बिहार की नदियों में जमा गाद अब राज्य के लिए केवल बाढ़ और जलजमाव की समस्या नहीं रहेगी,बल्कि विकास का नया संसाधन बनने जा रही है। नदियों और जलाशयों से वैज्ञानिक तरीके से निकाली गई उपयुक्त गाद का उपयोग राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण में किया जाएगा। इस उद्देश्य से 3 नवंबर 2026 को नई दिल्ली में केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय और बिहार सरकार के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी और बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की उपस्थिति में हुई यह पहल 'नदी संजीवनी' के माध्यम से जल प्रबंधन और आधारभूत संरचना के विकास को एक साथ जोड़ती है। इसका लक्ष्य नदियों की जलवहन क्षमता में सुधार, बाढ़ के जोखिम को कम करने और निर्माण कार्यों के लिए स्थानीय स्तर पर उपलब्ध उपयुक्त सामग्री का उपयोग करना है।बिहार जैसे बाढ़ प्रभावित राज्य के लिए इस समझौते का विशेष महत्त्व है। राज्य का बड़ा भूभाग गंगा के मैदानी क्षेत्र में स्थित है। गंगा के साथ गंडक, कोसी, बागमती, कमला-बालन, महानंदा, सोन और पुनपुन जैसी नदियाँ बिहार की जीवनरेखा हैं। नेपाल से आने वाली नदियों में वर्षा के मौसम में जलस्तर बढ़ने और उनके साथ बड़ी मात्रा में गाद आने से राज्य के अनेक जिलों में बाढ़ और जलजमाव की स्थिति उत्पन्न होती है। नदियों के तल में लगातार जमा होती गाद जलप्रवाह और जलधारण क्षमता को प्रभावित करती है। बिहार में 50 हजार से अधिक जल निकायों की मौजूदगी इस समस्या के व्यापक स्वरूप को दर्शाती है। ऐसे में वैज्ञानिक तरीके से गाद निकालने और उसका उपयोगी पुनः इस्तेमाल करने की पहल जल संसाधनों के बेहतर प्रबंधन की दिशा में महत्त्वपूर्ण कदम है।

इस समझौते की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसमें गाद को अपशिष्ट के बजाय निर्माण कार्य में उपयोगी संसाधन के रूप में देखा गया है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के आकलन के अनुसार,बिहार में निर्माणाधीन 16 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं में नदियों से निकाली गई लगभग 243 लाख घन मीटर गाद का उपयोग किया जाएगा। भविष्य की 27 परियोजनाओं के लिए लगभग 835 लाख घन मीटर गाद के उपयोग का प्रस्ताव है। यह सामग्री तकनीकी परीक्षण और निर्धारित गुणवत्ता मानकों पर खरी उतरने के बाद ही सड़क निर्माण में इस्तेमाल की जाएगी। इससे सड़क निर्माण के लिए मिट्टी की उपलब्धता बढ़ेगी और प्राकृतिक ऊपरी मिट्टी के अनावश्यक दोहन को सीमित करने में मदद मिलेगी।बिहार में इस समय लगभग 1,561 किलोमीटर लंबाई की 39 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाएँ निर्माणाधीन हैं, जिनकी कुल लागत करीब 58,340 करोड़ रुपये है। इसके अतिरिक्त लगभग 1,982 किलोमीटर लंबाई की 11 नई परियोजनाएँ प्रस्तावित हैं, जिनकी अनुमानित लागत करीब 75,200 करोड़ रुपये है। इन परियोजनाओं के लिए बड़े पैमाने पर निर्माण सामग्री की आवश्यकता होगी। नदियों और जलाशयों से वैज्ञानिक तरीके से निकाली गई उपयुक्त गाद इस आवश्यकता को पूरा करने में सहायक हो सकती है। इस व्यवस्था से एक ओर जल निकायों की सफाई और पुनर्जीवन को गति मिलेगी, वहीं दूसरी ओर राजमार्ग निर्माण के लिए स्थानीय संसाधनों का बेहतर उपयोग संभव होगा।केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी लंबे समय से बिहार में बाढ़ की समस्या के स्थायी समाधान के लिए व्यापक जल प्रबंधन, नदियों की ड्रेजिंग, तट संरक्षण और जल ग्रिड की अवधारणा पर जोर देते रहे हैं। पटना में आयोजित बिहार निवेशक सम्मेलन के दौरान उन्होंने राष्ट्रीय राजमार्ग और बिजली ग्रिड की तर्ज पर जल ग्रिड विकसित करने का विचार रखा था। उनका कहना था कि एक नदी बेसिन में उपलब्ध अतिरिक्त पानी को दूसरे बेसिन तक पहुँचाने की व्यवस्था से जल संसाधनों का बेहतर उपयोग किया जा सकता है। उन्होंने नदियों से गाद निकालकर उसका उपयोग राजमार्ग निर्माण में करने की संभावना भी व्यक्त की थी। अब केंद्र और बिहार सरकार के बीच हुआ यह समझौता उस विचार को संस्थागत रूप देने की दिशा में महत्त्वपूर्ण कदम है।

मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर के अवसर पर बिहार की गाद प्रबंधन नीति को राज्य के लिए दूरगामी महत्त्व का कदम बताया। उन्होंने कहा कि बिहार में नेपाल से आने वाली सात प्रमुख नदियों के कारण बाढ़ की चुनौती गंभीर बनी रहती है। राज्य सरकार ने इस समस्या से निपटने के लिए व्यापक गाद प्रबंधन नीति तैयार की है, ताकि नदियों में जमा गाद को विकास के संसाधन में बदला जा सके। मुख्यमंत्री ने बांका जिले के ओढ़नी बांध का उदाहरण देते हुए बताया कि गाद निकालने के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार कराने पर लगभग 350 करोड़ रुपये की आवश्यकता बताई गई थी, जबकि राज्य सरकार की ओर से निविदा आमंत्रित किए जाने पर एक निजी ठेकेदार ने काम करने के बदले सरकार को 60 करोड़ रुपये देने की पेशकश की। इस उदाहरण से स्पष्ट होता है कि वैज्ञानिक और व्यावसायिक दृष्टिकोण अपनाने पर गाद प्रबंधन आर्थिक अवसर भी बन सकता है।मुख्यमंत्री ने गंगा के दोनों किनारों पर बिहार में चार लेन के मार्ग विकसित करने की संभावना पर भी ध्यान आकर्षित किया। उन्होंने गंगा के जलमार्गों को व्यवस्थित करने और नदी तल से गाद निकालने के माध्यम से बड़े भूभाग को उपयोगी बनाने की संभावना का उल्लेख किया। मुख्यमंत्री की दृष्टि में नदी प्रबंधन को बाढ़ नियंत्रण तक सीमित रखने के बजाय कृषि, परिवहन, औद्योगिक विकास और रोजगार से जोड़ना आवश्यक है। हालाँकि, इस प्रकार की व्यापक परियोजनाओं को आगे बढ़ाने से पहले विस्तृत तकनीकी, पर्यावरणीय और सामाजिक अध्ययन जरूरी होगा, ताकि नदी के प्राकृतिक प्रवाह और पारिस्थितिकी तंत्र पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े।इस पहल की सफलता केवल गाद निकालने की मात्रा से नहीं, बल्कि उसकी वैज्ञानिक प्रक्रिया और पर्यावरणीय सुरक्षा से तय होगी। नदियों और जलाशयों की पहचान, गाद की मात्रा का आकलन, उसकी गुणवत्ता की जाँच और उपयोग की उपयुक्तता निर्धारित करना आवश्यक होगा। सड़क निर्माण में इस्तेमाल होने वाली सामग्री को मंत्रालय तथा भारतीय सड़क कांग्रेस के निर्धारित तकनीकी मानकों के अनुरूप होना चाहिए। नदी के तटों, तटबंधों, पुलों और आसपास की बस्तियों की सुरक्षा का भी ध्यान रखना होगा। गाद की निकासी, ढुलाई और उपयोग की मात्रा का पारदर्शी रिकॉर्ड तथा नियमित निगरानी इस पूरी व्यवस्था को जवाबदेह बनाएगी। बिहार सरकार की गाद प्रबंधन नीति और केंद्र के साथ हुए इस समझौते का वास्तविक लाभ तभी मिलेगा, जब क्रियान्वयन में पर्यावरणीय संतुलन और स्थानीय समुदायों के हितों को प्राथमिकता दी जाएगी।बिहार में सड़क अवसंरचना का विस्तार भी इस पहल को विशेष महत्त्व देता है। वर्ष 2014 के बाद राज्य में राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई और निवेश में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। वर्ष 2014 के बाद राज्य की प्रमुख नदियों पर 29 नए पुलों के निर्माण की दिशा में भी काम हुआ है। बेहतर सड़क संपर्क से कृषि उत्पादों को बाजार तक पहुँचाने, औद्योगिक गतिविधियों को बढ़ावा देने, पर्यटन विकसित करने और रोजगार के अवसर सृजित करने में सहायता मिलती है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने हाल ही में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से लगभग 49,751 करोड़ रुपये की चार प्रमुख सड़क एवं एक्सप्रेस-वे परियोजनाओं को शीघ्र मंजूरी देने का अनुरोध किया था।

(लेखक - विनोद सिंह 'तकियावाला')

दान की महिमा जीवन को महान बनाने का सबसे पवित्र मार्ग है

मनुष्य के जीवन की वास्तविक सार्थकता केवल धन कमाने और सुख-सुविधाओं का संग्रह करने में नहीं, बल्कि अपने अर्जित संसाधनों से दूसरों के जीवन में खुशियां लाने में है। भारतीय संस्कृति और धर्म परंपरा में दान को हमेशा सर्वोच्च स्थान दिया गया है। दान केवल धन या वस्तु देने का नाम नहीं, बल्कि करुणा, उदारता, परोपकार और मानवीय संवेदनाओं की अभिव्यक्ति है। एक प्रसिद्ध लोकोक्ति है- भीख में से भीख दे, तीन लोक जीत ले। इसका भाव यही है कि जिसके पास स्वयं बहुत कम है, वह भी अपनी सामर्थ्य के अनुसार किसी जरूरतमंद की सहायता कर सकता है। दान का मूल्य वस्तु की कीमत से नहीं, बल्कि देने वाले की भावना से निर्धारित होता है।

संतों और महापुरुषों ने कहा है कि धन की तीन गतियां होती हैं- दान, भोग और नाश। जो धन दूसरों के काम आता है, वही धन सार्थक होता है। जो व्यक्ति न स्वयं उसका सदुपयोग करता है और न किसी जरूरतमंद को देता है, उसका धन अंततः नष्ट हो जाता है। इसलिए जीवन में संचय के साथ सदुपयोग और परोपकार का भाव भी आवश्यक है। अनुभव बताता है कि केवल संग्रह करने से मनुष्य को स्थायी संतोष नहीं मिलता, जबकि दूसरों के साथ बांटने से आत्मिक आनंद और समाज में सम्मान प्राप्त होता है। यही कारण है कि भारतीय चिंतन में कहा गया है कि कमाई अपने हाथों से करो और दान हजार हाथों से करो।

प्रकृति भी हमें देने का संदेश देती है। सूर्य बिना किसी भेदभाव के प्रकाश देता है, वायु सभी को जीवन प्रदान करती है और नदियां अपना जल दूसरों के लिए बहाती हैं। वृक्ष स्वयं धूप और वर्षा सहन करके दूसरों को फल, छाया और प्राणवायु देते हैं। प्रकृति का प्रत्येक तत्व हमें सिखाता है कि जीवन का उद्देश्य केवल लेना नहीं, बल्कि देना भी है। मनुष्य प्रकृति से जीवनभर अनेक उपहार प्राप्त करता है। इसलिए उसके प्रति कृतज्ञता प्रकट करने का एक मार्ग परोपकार और दान भी है। जैसे किसान खेत में बीज डालता है और कुछ समय बाद वही बीज अनेक गुना होकर लौटता है, वैसे ही निस्वार्थ भाव से किया गया दान भी जीवन में सद्भाव और पुण्य का आधार बनता है।

दान करते समय भावना की पवित्रता सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। दान का उद्देश्य किसी पर उपकार जताना, अपना नाम चमकाना अथवा प्रसिद्धि प्राप्त करना नहीं होना चाहिए। वास्तविक दानी वही है जो बिना किसी अपेक्षा के जरूरतमंद की सहायता करे। दान लेने वाले के प्रति सम्मान और विनम्रता का भाव रखना चाहिए। किसी की मजबूरी का प्रदर्शन करना या दान देकर उसका अपमान करना दान की मूल भावना के विपरीत है। सेवा का सच्चा आनंद तभी मिलता है जब देने वाले के मन में अहंकार नहीं, बल्कि करुणा और आत्मीयता हो।

दान के अनेक स्वरूप हैं। ज्ञानदान, अभयदान, वस्त्रदान, औषधदान, आवासदान और आहारदान सभी का अपना महत्व है। इनमें आहारदान को विशेष रूप से महादान माना गया है, क्योंकि भोजन जीवन का आधार है। भूखे व्यक्ति को भोजन कराना केवल उसकी भूख मिटाना नहीं, बल्कि उसे जीवन जीने की शक्ति देना है। धन, वस्त्र और अन्य सुविधाएं बाद में भी प्राप्त हो सकती हैं, लेकिन भूख की पीड़ा तत्काल भोजन मांगती है। इसलिए किसी जरूरतमंद को भोजन कराना मानवीय सेवा का अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य है।

गौतम बुद्ध से जुड़ा एक प्रसंग दान की भावना को सुंदर ढंग से समझाता है। एक दिन कुछ बालक खेल रहे थे। बुद्ध वहां से गुजरे तो एक बालक ने उनसे कहा कि बाबा, दान लो। बुद्ध ने अपनी झोली फैला दी और बालक ने उसमें रेत डाल दी। शिष्य ने आश्चर्य से पूछा कि आपने रेत क्यों स्वीकार की? बुद्ध ने समझाया कि रेत का कोई विशेष मूल्य नहीं, लेकिन बालक के मन में दान करने की भावना जागी है। यदि मैं उसका दान अस्वीकार कर देता तो उसकी उदारता का भाव कमजोर हो सकता था। आज वह रेत दे रहा है, संभव है कि कल अपनी सामर्थ्य के अनुसार भोजन भी दान करे। इस प्रसंग से स्पष्ट होता है कि दान की शुरुआत छोटी भावना से होती है, लेकिन उसका प्रभाव बहुत व्यापक हो सकता है।

जैन धर्म में आहारदान का विशेष आध्यात्मिक महत्व है। श्रावक के बारह व्रतों में अतिथि संविभाग व्रत भी शामिल है। इसका आशय है कि गृहस्थ अपने भोजन में से साधु-संतों और सुपात्रों के लिए भी हिस्सा निकाले। जैन परंपरा में मुनियों को विधिपूर्वक आहारदान देना पुण्यकारी माना गया है। मान्यता है कि सुपात्रदान से कर्मों की निर्जरा होती है और आत्मकल्याण का मार्ग प्रशस्त होता है। भगवान महावीर की शिक्षाओं में त्याग, संयम, अहिंसा और जीवमात्र के प्रति करुणा का जो संदेश मिलता है, उसमें दान की भावना भी महत्वपूर्ण स्थान रखती है। अन्य धर्मों में भी भोजन बांटने की परंपरा रही है। ऋग्वेद में अकेले भोजन करने की प्रवृत्ति को उचित नहीं माना गया है। गीता में भी दूसरों को भोजन कराए बिना केवल अपने लिए भोजन करने वालों के प्रति चेतावनी दी गई है। इससे स्पष्ट होता है कि भोजन बांटना किसी एक धर्म या संप्रदाय तक सीमित नहीं, बल्कि संपूर्ण मानवता का साझा आदर्श है।

आज के समय में जब समाज में आर्थिक असमानता और जरूरतमंदों की समस्याएं दिखाई देती हैं, तब दान की महत्ता और बढ़ जाती है। प्रत्येक परिवार अपनी सामर्थ्य के अनुसार किसी भूखे को भोजन करा सकता है, किसी जरूरतमंद विद्यार्थी की सहायता कर सकता है अथवा किसी असहाय व्यक्ति के लिए उपयोगी वस्तुएं उपलब्ध करा सकता है। दान के लिए धनवान होना आवश्यक नहीं, उदार हृदय होना आवश्यक है।

अंततः जीवन में धन का वास्तविक महत्व उसके संग्रह में नहीं, बल्कि उसके सदुपयोग में है। जो भोजन हम अकेले खा सकते हैं, उसमें से किसी भूखे का हिस्सा निकालना ही सच्ची मानवता है। दान मनुष्य को विनम्र बनाता है, समाज में प्रेम बढ़ाता है और आत्मा को संतोष प्रदान करता है। इसलिए अपनी आय, सामर्थ्य और परिस्थिति के अनुसार दान को जीवन का हिस्सा बनाना चाहिए। विशेषकर आहारदान के माध्यम से किसी की भूख मिटाना सबसे सहज और पुण्यकारी सेवा है। दान से हाथ खाली नहीं होते, बल्कि हृदय समृद्ध होता है। यही दान की महिमा है और यही मानव जीवन का सच्चा कल्याण मार्ग है।

(लेखक- कांतिलाल मांडोत)

युवाओं में जीवन से पलायन की खतरनाक प्रवृत्ति

युवाओं में आत्महत्या (सुसाइड) और जीवन से पलायन करने की बढ़ती प्रवृत्ति आज एक अत्यंत गंभीर और चिंताजनक सामाजिक और मानसिक स्वास्थ्य मुद्दा बन चुकी है। आधुनिक जीवनशैली, अत्यधिक दबाव और सामाजिक बदलावों ने युवाओं को एक ऐसे चौराहे पर खड़ा कर दिया है जहाँ वे कई बार दिशाहीन और असहाय महसूस करने लगते हैं।विश्व स्वास्थ्य संगठन और अंतरराष्ट्रीय संगठनों के वैश्विक डेटा के अनुसार, पूरी दुनिया में हर साल लगभग 7,20,000 से अधिक लोग आत्महत्या से अपनी जान गंवाते हैं।

दुनिया में हर 40 सेकंड में लगभग एक व्यक्ति आत्महत्या के कारण मर जाता है।

15 से 29 वर्ष के युवाओं के बीच दुनिया भर में मौत का यह चौथा सबसे बड़ा कारण बन चुका है।

विश्व स्वास्थ्य संगठन का अनुमान है कि हर एक सफल आत्महत्या के पीछे कम से कम 20 या उससे अधिक बार आत्महत्या के प्रयास किए जाते हैं।

दुनिया भर में होने वाली कुल आत्महत्याओं का लगभग 73त्न से 77त्न हिस्सा निम्न और मध्यम आय वाले देशों में होता है, जिसमें भारत भी शामिल है।

भारत सरकार के नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार, भारत में हर साल लगभग 1.70 लाख से अधिक लोग आत्महत्या करते हैं।

वर्ष 2024 में भारत में कुल 1,70,746 लोगों ने आत्महत्या की, जबकि 2023 में यह संख्या 1,71,418 थी।

भारत में प्रति 1,00,000 आबादी पर आत्महत्या की दर 12.2 है।

कुल मामलों में पुरुषों की संख्या लगभग 73.5त्न है, जिसमें दिहाड़ी मजदूर और छात्र सबसे संवेदनशील समूहों में शामिल हैं।

महाराष्ट्र, तमिलनाडु और मध्य प्रदेश में देश की कुल आत्महत्याओं के करीब एक-तिहाई मामले दर्ज होते हैं।

अब आपको अक्टूबर माह के अंतिम दिन अख़बार की सुरखी बने सुसाइड मामलों की बानगी से अवगत कराते हैं ताकि आप आत्महत्या की बढ़ती घटनाओं को समझें

पुणे से एक खौफनाक धटना सामने आई 30 अक्टूबर को एक महिला ने अपने 6 साल के बेटे के साथ 18वीं मंजिल से छलांग लगाकर जान दे दी. यह घटना एक हाई-प्रोफाइल सोसायटी में फुटेज में महिला अपने बेटे के साथ 18वीं मंजिल पर जाती दिखाई दे रही है पुलिस आत्महत्या के पीछे के कारणों की जांच कर रही है.मामला पुणे के पिंपरी-चिंचवड़ शहर के थेरगांव वाकड इलाके में सिग्नेचर पार्क नाम की एक हाई-प्रोफाइल सोसायटी का है, यहां 33 साल की एकता भांगड ने अपने 6 साल के बेटे माधव भांगड के साथ इमारत की 18वीं मंजिल से छलांग लगाकर आत्महत्या कर ली. जानकारी के मुताबिक, एकता भांगड अपने पति मनोज भांगड और बेटे माधव के साथ पिछले कुछ सालों से इस सोसायटी में रह रही थी जानकारी मिलते ही वाकड पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और पंचनामा भरकर आगे की जांच शुरू की. मृतक महिला का परिवार मूल रूप से राजस्थान का रहने वाला है. वे पिछले दो सालों से इस सोसायटी की सातवीं मंजिल पर रह रहे थे. मृतक महिला का पति मनोज भांगड यरवदा स्थित एक आईटी कंपनी में काम करता है। मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले से ऐसी हृदयविदारक घटना सामने आई है, जिसने पूरे प्रदेश को झकझोर कर रख दिया है. यहां दो सगी बहनों ने अलग-अलग जगहों पर अपने बच्चों के साथ कुएं में कूदकर जान दे दी. पहली घटना में पति की मौत के सदमे से गुजर रही 8 महीने की गर्भवती महिला ने अपने बेटे के साथ जान दी, जबकि कुछ घंटे बाद उसकी बड़ी बहन ने भी अपने तीन बच्चों के साथ कुएं में छलांग लगा दी. इन घटनाओं में दो बहनों और चार मासूम बच्चों समेत कुल 6 लोगों की मौत हो गई, जबकि गर्भ में पल रहे शिशु की भी जान चली गई। इसी तरह राजस्थान की राजधानी जयपुर से इस वक्त एक हादसे में पूर्णिमा यूनिवर्सिटी की छठी मंजिल से एक छात्रा कूद गई है. छात्रा के कूदने से यूनिवर्सिटी में हड़कंप मच गया है. प्रशासन ने इलाके को सील कर जांच शुरू कर दी है. इस हादसे के बाद यूनिवर्सिटी को फिलहाल बंद कर दिया है. पूर्णिमा यूनिवर्सिटी से छात्रा से कूदने का एक सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया है. इस वीडियो में छात्रा छत की छठी मंजिल पर बिल्कुल किनारे बैठी नजर आ रही है.पूर्णिमा यूनिवर्सिटी की छठी मंजिल से कूदने वाली छात्रा की पहचान यशस्वी रोहिला के रूप में हुई है. एमबीए सेकंड ईयर की स्टूडेंट है. बताया जाता है कि यशस्वी जयपुर के गुर्जर की थ्री इलाके के प्रेम नगर की रहने वाली है. शिवदासपुरा थाना की पुलिस मौके पर जांच में जुटी है.

यह आंकड़े दर्शाते हैं कि मानसिक स्वास्थ्य और आत्महत्या रोकथाम पर वैश्विक और राष्ट्रीय स्तर पर बड़े बदलावों की तत्काल आवश्यकता है।

भारत सरकार देश में आत्महत्या की बढ़ती वारदातों को रोकने और मानसिक स्वास्थ्य में सुधार के लिए बहु-स्तरीय प्रयास कर रही है। सरकार ने इसके लिए कानूनी बदलाव, डिजिटल तकनीक और जमीनी स्तर पर स्वास्थ्य ढांचे को मजबूत किया है।

सरकार द्वारा कुछ खास कदम उठाए जा रहे हैं

भारत सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा देश की पहली राष्ट्रीय आत्महत्या रोकथाम रणनीति लागू की गई है।

इसका मुख्य उद्देश्य वर्ष 2030 तक देश में आत्महत्या मृत्यु दर में 10त्न की कमी लाना है।

इसके तहत अगले कुछ वर्षों में सभी शिक्षण संस्थानों में मानसिक कल्याण पाठ्यक्रम को शामिल करने और देश के सभी जिलों में मनोरोग ओपीडी स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है।

दूरदराज के क्षेत्रों तक मुफ्त और गोपनीय मानसिक परामर्श पहुँचाने के लिए सरकार ने डिजिटल तकनीक का बड़े पैमाने पर विस्तार किया हैदेश भर के 1.83 लाख से अधिक आयुष्मान आरोग्य मंदिरों (प्राथमिक स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों) में बुनियादी मानसिक स्वास्थ्य जांच और काउंसलिंग सेवाओं को एकीकृत किया गया है।समाज में मानसिक स्वास्थ्य को लेकर फैले अंधविश्वास, शर्म (स्ह्लद्बद्घद्बड्ड) और रूढ़िवादिता को खत्म करने के लिए सरकार ने सामुदायिक स्तर पर जागरूकता अभियान शुरू किए हैं, ताकि लोग समय रहते मदद मांगने के लिए आगे आ सकें।इन व्यापक सरकारी रणनीतियों में केवल स्वास्थ्य मंत्रालय ही नहीं, बल्कि शिक्षा, कृषि, महिला एवं बाल विकास और सूचना एवं प्रसारण जैसे मंत्रालयों को भी एक साथ जोड़ा गया है ताकि युवाओं, किसानों और हर संवेदनशील वर्ग को सुरक्षा घेरा दिया जा सके।

(लेखक - मनोज कुमार अग्रवाल)

जब बंद एयरपोर्ट को दोबारा चालू करके प्लेन की हुई लैंडिंग

अहमदाबाद के मरीज़ को नया जीवन देने रातभर ग्राउंड पर रहा जबलपुर एयरपोर्ट स्टाफ

जबलपुर।

मानवता की सेवा और कर्तव्यनिष्ठा की कोई समय सीमा नहीं होती, इसे जबलपुर एयरपोर्ट के अधिकारियों और कर्मचारियों ने सोमवार की रात सच साबित कर दिखाया। 'यश भारत' में कल चिकित्सा जगत के योगदान पर विस्तृत खबर प्रकाशित होने के बाद, आज का पूरा फोकस जबलपुर एयरपोर्ट की उस जांबाज टीम पर है, जिसने बंद एयरपोर्ट को आधी रात के बाद दोबारा ऑपरेशनल कर तीन गंभीर मरीजों को नया जीवनदान दिलाने में अहम भूमिका निभाई।

सोमवार की रात शहर में बने ग्रीन कॉरिडोर के जरिए एक मानव अंग को अहमदाबाद पहुँचाया जाना था। नियम और शेड्यूल के मुताबिक, जबलपुर एयरपोर्ट का सामान्य संचालन रात 8:15 बजे इंडिगो की अंतिम फ्लाइट के प्रस्थान के बाद थम जाता है और रात 9:30 बजे तक एयरपोर्ट पूरी



तरह बंद होकर कर्मचारी अपने घर लौट जाते हैं।

लेकिन, जब रात करीब 10:00 बजे घर लौट रहे कर्मचारियों को अहमदाबाद से चार्टर्ड प्लेन आने और आपातकालीन ग्रीन कॉरिडोर की सूचना मिली, तो बिना एक पल गंवाए प्रशासनिक तत्परता दिखाई गई।

रातभर ऐसे चला आपातकालीन तकनीकी टीमों का असाधारण समन्वय

एक विमान को रात के वक्त सुरक्षित उतारने और उड़ाने के लिए एयर ट्रैफिक कंट्रोल (ATC) से लेकर कई तकनीकी और सुरक्षा प्रणालियों की जरूरत होती है। इस आपात स्थिति में विमानपत्तन निदेशक श्री राजेश कुमार मौर्य और एटीसी प्रभारी श्री नीरज गुडवानी के नेतृत्व में एटीसी टीम, फायर फाइटिंग सिस्टम, रनवे लाइटिंग, ग्राउंड सेफ्टी और सुरक्षा अमले के सभी कर्मचारी पूरी मुस्तैदी से डटे रहे। आधी रात के बाद संसाधनों और कर्मियों को जुटाकर एयरपोर्ट को सुचारू रूप से चलाना और तीन लोगों की जिंदगी बचाने में लॉजिस्टिक सपोर्ट देना जबलपुर एयरपोर्ट की उच्च पेशेवर क्षमता और मानवीय संवेदना का सबसे बड़ा उदाहरण है। जबलपुर के इस गौरवशाली क्षण में एयरपोर्ट परिवार का यह समर्पण हर नागरिक के लिए वंदनीय है।

एयरपोर्ट ऑपरेशन

रात 10:00 बजे: घर जाने की तैयारी कर रहे एयरपोर्ट कर्मियों को आपातकालीन चार्टर और ग्रीन कॉरिडोर की मिली सूचना।

रात 10:30 बजे: विमानपत्तन निदेशक श्री राजेश कुमार मौर्य और एटीसी प्रभारी श्री नीरज गुडवानी के निर्देश पर बंद एयरपोर्ट को दोबारा एक्टिवेट किया गया।

रात 12:30 बजे: अहमदाबाद से विशेष चार्टर्ड प्लेन ने जबलपुर रनवे पर सुरक्षित लैंडिंग की।

भोर 04:30 बजे: आवश्यक प्रक्रिया के बाद प्लेन ने मानव अंगों को लेकर अहमदाबाद के लिए भरी सफल उड़ान।

सुबह 05:00 बजे: पूरी प्रक्रिया के सुरक्षित संपन्न होने तक एयरपोर्ट पर सेवाएं सक्रिय रहीं।

फायर सेफ्टी को लेकर प्रशासन सख्त

नियमों का उल्लंघन करने पर माढ़ोताल की 6 पटाखा दुकानें सील



जबलपुर, यशभारत। त्योहारी सीजन में सुरक्षा नियमों और शर्तों की सरेआम धज्जियां उड़ाने वाले पटाखा कारोबारियों के खिलाफ प्रशासन ने कड़ा रुख अपना लिया है। माढ़ौताल के कठौदा स्थित पटाखा बाजार में फायर सेफ्टी के पर्याप्त इंतजाम न मिलने पर प्रशासनिक टीम ने आधी रात को ताबड़तोड़ कार्रवाई करते हुए 6 दुकानों को मौके पर ही सील कर दिया। प्रशासनिक दल को देखकर दुकानदारों में हड़कंप मच गया और विवाद की स्थिति भी बनी, लेकिन मौके पर मौजूद भारी पुलिस बल ने तुरंत मोर्चा संभालकर स्थिति को नियंत्रण में लिया। SDM मदन रघुवंशी और तहसीलदार रंजना यादव के नेतृत्व में SDOP अंजुल अयंक मिश्रा, नगर निगम के एडिशनल कमिश्नर विद्यानंद बाजपेयी सहित पूरा मैदानी अमला रात 1 बजे तक कार्रवाई में डटा रहा। अधिकारियों ने सख्त हिदायत दी है कि दुकानों के बाहर सामान रखने और सुरक्षा में लापरवाही बरतने पर बख्शा नहीं जाएगा। प्रशासन का यह जांच अभियान अब जिले के अन्य पटाखा बाजारों में भी पूरी सख्ती के साथ जारी रहेगा।

मप्र को लारा परियोजना से मिलेगी 800 मेगावाट किफायती बिजली

एनटीपीसी और एमपीपीएमसीएल के बीच हुआ पीपीए



जबलपुर। मध्यप्रदेश में भविष्य की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने और प्रदेशवासियों को सस्ती एवं निर्बाध बिजली उपलब्ध कराने की दिशा में ऊर्जा विभाग ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर, प्रमुख सचिव ऊर्जा मनीष सिंह और ऊर्जा सचिव व एमपी पावर मैननजमेंट कंपनी के प्रबंध संचालक विशेष गढ़पाले की उपस्थिति में छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में स्थित एनटीपीसी की लारा चरण-III (2म800 मेगावाट) परियोजना से विद्युत क्रय के लिए एमपी पावर मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड (एमपीपीएमसीएल) और एनटीपीसी के मध्य विद्युत क्रय अनुबंध निष्पादित किया गया। इस अनुबंध के तहत मध्य प्रदेश को लारा परियोजना से 800 मेगावाट बिजली प्राप्त होगी। वर्ष 2031-32 तक इस संयंत्र से मध्य प्रदेश को उचित दरों पर विश्वसनीय बिजली मिलनी शुरू हो जाएगी। अनुबंध के अनुसार लारा-III परियोजना से मध्य प्रदेश को कुल 4.97 रुपये प्रति यूनिट की अनुमानित दर पर बिजली उपलब्ध होगी।ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने इस अनुबंध पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि राज्य सरकार प्रदेश के प्रत्येक उपभोक्ता को गुणवत्तापूर्ण एवं सस्ती बिजली उपलब्ध कराने के लिए संकल्पित है। यह अनुबंध भविष्य में राज्य के कृषि, उद्योग और घरेलू क्षेत्रों की बढ़ती मांग को पूरा करने में मील का पत्थर साबित होगा। कैप्टिव खदान से ईंधन सुरक्षा और कम लागत-लारा परियोजना की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यह संयंत्र कोयला खदान के अत्यंत निकट स्थित है और इसमें एनटीपीसी की अपनी कैप्टिव खदान से कोयला प्राप्त होता है। कोयले की सीधी और सुरक्षित उपलब्धता के कारण ढुलाई खर्च में बचत होगी, जिससे बिजली की आपूर्ति पूरी तरह विश्वसनीय और न्यूनतम लागत पर संभव हो सकेगी। इस अवसर पर एनटीपीसी दिल्ली से मुख्य महाप्रबंधक कॉमर्शियल ए.एस. पांडे, महाप्रबंधक संदेश जायसवाल, रायपुर से अतिरिक्त मुख्य महाप्रबंधक कॉमर्शियल भूपेश कुमार और एमपीपीएमसीएल की ओर से मुख्य महाप्रबंधक कॉमर्शियल डॉ. आर.बी. सक्सेना उपस्थित थे।

सिहोरा और पाटन की मिठाई और मावा की दुकानों की जांच.

जबलपुर - त्यौहारों पर उपभोक्ताओं को शुद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण खाद्य पदार्थों की उपलब्धता सुनिश्चित कराने के कलेक?टर अरुण कुमार विश्वकर्मा के निर्देशानुसार चलाये जा रहे जाँच अभियान के तहत राजस्व एवं खाद्य सुरक्षा अधिकारियों ने मंगलवार को सिहोरा और पाटन में खाद्य प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किया। राजस्व एवं खाद्य सुरक्षा अधिकारियों ने सिहोरा स्थित विजय स्वीट्स से मिल्क केक, शिवम स्वीट्स से सलोनी और बर्फी तथा बीकानेर स्वीट्स से मावा के नमूने लिए। इसी प्रकार पाटन स्थित बड़ू खोवा से खोवा के 2, बीकानेर स्वीट्स से मिठाई एवं मावा के 4, नेमा स्वीट्स से मिठाई के 2 तथा कृष्णा स्वीट्स से मिठाई के 2 सैंपल लिए गए। सभी सैंपल जांच हेतु राज्य खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला, भोपाल भेजे जा रहे हैं। प्रयोगशाला से परीक्षण रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद यदि नमूने खाद्य सुरक्षा एवं मानकों के अनुरूप नहीं पाए जाते हैं, तो खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 तथा संबंधित नियमों के तहत वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।

पार्वती कोल को तत्काल चार लाख रूपये की अनुग्रह सहायता राशि स्वीकृत

जबलपुर। कलेक्टर श्री विश्वकर्मा ने जनसुनवाई में पहुंची सिहोरा के वार्ड नंबर 01 निवासी आवेदिका पार्वती कोल को उनके पति स्व. कमलेश कोल की 29 जनवरी 2026 को मुहारी डेम में डूबने से हुई अकाल मृत्यु पर तत्काल संज्ञान लेते हुए एसडीएम ग्रामीण को निर्देश दिए कि उन्हें नियमानुसार अनुग्रह सहायता राशि प्रदान की जाए। इस पर त्वरित कार्रवाई करते हुए एसडीएम ग्रामीण ने राजस्व पुस्तक परिपत्र छह-चार के प्रावधानों के तहत मृतक के परिवार को चार लाख रुपये की सहायता राशि स्वीकृत कर दी है, जिससे पीड़ित परिवार को बड़ी राहत मिली है। कलेक्टर विश्वकर्मा ने संबंधित अधिकारी को निर्देश दिये कि अनुग्रह राशि के स्वीकृति पत्र पीड़ित परिवार के घर जाकर प्रदाय करें।

एक्सीडेंट में घायल युवक का कटंगी बायपास स्थित अस्पताल में दो दिनों से चल रहा था इलाज

हेल्थ सिटी हॉस्पिटल पर आरोप मौत के बाद भी करते रहे इलाज

परिजनों का कहना है मौत के बाद भी अस्पताल ने लगा रखा था वेंटिलेटर

जबलपुर,यशभारत। शहर के निजी अस्पतालों में मरीजों के इलाज और उनकी जिंदगी से जुड़े सवाल एक बार फिर खड़े हो गए हैं। माढोताल थाना क्षेत्र स्थित कटंगी बाईपास के हेल्थ सिटी हॉस्पिटल में सड़क दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल एक युवक की मौत के बाद परिजनों ने अस्पताल प्रबंधन पर बेहद गंभीर आरोप लगाए हैं। परिजनों का दावा है कि मरीज की मौत होने के बावजूद अस्पताल प्रबंधन ने उसे वेंटिलेटर पर रखकर इलाज जारी रखा और मृत्यु की जानकारी नहीं दी। मामले ने निजी अस्पतालों की कार्यप्रणाली और मरीजों के परिजनों को दी जाने वाली जानकारी पर सवाल खड़े कर दिए हैं।



दूसरे अस्पताल ले जाने पर पता चला कि पहले ही हो गई थी युवक की मौत

जानकारी के मुताबिक, औरिया निवासी भगवत रजक (38) दो नवंबर की शाम सड़क दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल हो गया था। परिजन उसे तत्काल कटंगी बाईपास स्थित हेल्थ सिटी हॉस्पिटल लेकर पहुंचे, जहां उसे भर्ती कर उपचार शुरू किया गया। परिजनों का आरोप है कि देर रात भगवत की मौत हो गई थी, लेकिन इसके बावजूद अस्पताल में उसे वेंटिलेटर पर रखकर इलाज जारी रखा गया। परिजनों के अनुसार, तीन नवंबर की दोपहर उन्होंने भगवत को दूसरे अस्पताल ले जाने की बात कहकर हेल्थ सिटी हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कराया और उसे एक निजी अस्पताल लेकर पहुंचे। वहां चिकित्सकों ने परीक्षण के बाद भगवत को मृत घोषित कर दिया। इस घटनाक्रम के बाद परिजनों ने हेल्थ सिटी हॉस्पिटल की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए आरोप लगाया कि यदि मरीज की मौत पहले ही हो चुकी थी, तो अस्पताल प्रबंधन ने उन्हें इसकी जानकारी क्यों नहीं दी?

महज दो किलोमीटर की दूरी, फिर भी मौत की जानकारी दूसरे अस्पताल में

इस पूरे मामले में सबसे चौंकाने वाला पहलू यह है कि हेल्थ सिटी हॉस्पिटल से जिस निजी अस्पताल में भगवत को ले जाया गया, उसकी दूरी महज दो किलोमीटर बताई जा रही है। परिजनों का कहना है कि इतने कम अंतराल में दूसरे अस्पताल पहुंचने पर मरीज को मृत घोषित किया गया, जबकि हेल्थ सिटी हॉस्पिटल में उसे वेंटिलेटर पर रखकर उपचार जारी होने की बात कही जा रही थी। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि आखिर मरीज की वास्तविक स्थिति क्या थी और परिजनों को उसकी जानकारी कब और किस रूप में दी गई?

अब उठ रहे हैं जवाबदेही के सवाल

भगवत रजक की मौत के बाद सामने आए आरोपों ने अस्पताल प्रबंधन की जवाबदेही को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। आखिर मरीज की स्थिति क्या थी? क्या परिजनों को समय पर उसकी वास्तविक स्थिति की जानकारी दी गई? क्या उपचार के दौरान मरीज की मृत्यु हुई थी या उसे दूसरे अस्पताल ले जाने के समय उसकी हालत गंभीर बनी हुई थी? इन सवालों का जवाब चिकित्सकीय दस्तावेजों, उपचार के रिकॉर्ड और निष्पक्ष जांच से ही सामने आ सकेगा।

पोस्टमार्टम रिपोर्ट से होगा मौत के समय का खुलासा

मामले में युवक की मौत के सही समय को लेकर स्थिति फिलहाल स्पष्ट नहीं है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही भगवत रजक की मौत के वास्तविक समय और उससे जुड़े महत्वपूर्ण तथ्यों का खुलासा हो सकेगा। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस द्वारा अस्पताल में हुए उपचार, चिकित्सकीय दस्तावेजों और परिजनों के आरोपों की पड़ताल की जा रही है। जांच के बाद ही पूरे मामले की वास्तविक स्थिति स्पष्ट हो सकेगी।

अस्पताल प्रबंधन की सफाई–दो बार सीपीआर देकर मरीज को किया रिकवर

वहीं, हेल्थ सिटी हॉस्पिटल प्रबंधन ने परिजनों के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि भगवत रजक की हालत बेहद गंभीर थी। उपचार के दौरान उसे दो बार सीपीआर दिया गया, जिसके बाद उसे रिकवर किया गया और इलाज जारी रखा गया। अस्पताल प्रबंधन का दावा है कि मरीज की स्थिति और उपचार की जानकारी परिजनों को भी दी गई थी तथा उसे वेंटिलेटर पर रखा गया था। प्रबंधन के अनुसार, परिजन अपनी जवाबदारी पर मरीज को दूसरे अस्पताल लेकर गए थे, जहां उसकी मौत हुई।

विधानसभा में नोडल अधिकारियों को दिया ई-विधान का प्रशिक्षण

विधानसभा के कामकाज को पेपरलेस बनाने पर जोर

भोपाल, यश भारत।

मध्यप्रदेश विधानसभा में बुधवार को राज्य मंत्रालय के नोडल अधिकारियों के लिए ई-विधान प्रणाली के अंतर्गत प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें अधिकारियों को डिजिटल माध्यम से विधानसभा संबंधी कार्यों के निष्पादन की प्रक्रिया और प्रणाली के विभिन्न पहलुओं की जानकारी दी गई। प्रशिक्षण के दौरान अधिकारियों को ई-विधान प्रणाली की कार्यप्रणाली ऑनलाइन प्रक्रियाओं और डिजिटल माध्यम से शासकीय कार्यों के संचालन के बारे में विस्तार से समझाया गया। साथ ही विधानसभा से जुड़े कार्यों को ऑनलाइन संपादित करने की प्रक्रिया से भी अवगत कराया गया। प्रशिक्षण का मुख्य उद्देश्य विधानसभा की कार्यप्रणाली को आधुनिक तकनीक से जोड़ना और कागजी प्रक्रिया को कम करते हुए कामकाज को अधिक सुगम पारदर्शी एवं प्रभावी बनाना है। ई विधान प्रणाली के माध्यम से विधानसभा की विभिन्न प्रक्रियाओं को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर संचालित करने की दिशा में यह पहल महत्वपूर्ण मानी जा रही है।

नलों में आ रहा नालियों का दूषित पानी, पी रहे लोग, पार्षद धरने पर बैठे

भोपाल ,यश भारत।

वार्ड क्रमांक 4 बरसई में पेयजल व्यवस्था की बदहाली को लेकर मंगलवार को भाजपा पार्षद संजय कुशवाह नगर पालिका परिषद कार्यालय के सामने धरने पर बैठ गए। उन्होंने मुख्य नगर पालिका अधिकारी राजेंद्र सक्सेना को ज्ञापन सौंपकर क्षतिग्रस्त पाइपलाइन बदलने और स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने की मांग की। पार्षद ने बताया कि वार्ड में कई वर्षों से पाइपलाइन की समस्या बनी हुई है। कहीं पाइपलाइन फूटी है तो कहीं लाइन ही नहीं है। हालात यह हैं कि नालियों का गंदा पानी पेयजल पाइपलाइन में मिलकर घरों तक पहुंच रहा है। इससे रहवासियों को दूषित



पानी पीने की मजबूरी है। पार्षद ने प्रशासन से तत्काल पाइपलाइन बदलने की मांग की। सीएमओ राजेंद्र सक्सेना ने समस्या के निराकरण का आश्वासन दिया, जिसके बाद धरना समाप्त हुआ।

10 दिन में समाधान नहीं तो आंदोलन-संजय कुशवाह ने चेतावनी दी है कि पाइपलाइन नहीं बदली गई तो वार्डवासियों के साथ तहसील कार्यालय पर उग्र प्रदर्शन करेंगे। साथ ही मुख्यमंत्री के नाम एसडीएम को ज्ञापन सौंपेंगे।

घरों से निकला कचरा बना मुसीबत, सड़कों पर ढेर

चेतावनी के बाद भी नहीं जागा प्रशासन, सफाई कर्मचारियों की नाराज़गी का खामियाज़ा भुगत रही भोपाल की जनता

भोपाल, यश भारत।

एक तरफ राजधानी के आम लोग प्रकाश पर्व दीपावली के स्वागत और उल्लास के लिए अपने-अपने घरों की गहन साफ-सफाई में जुटे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ नगर निगम के सफाई कर्मचारियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल ने पूरे शहर को कचरे के ढेर में तब्दील कर दिया है। स्थिति यह है कि पिछले दो दिनों से लोगों द्वारा घरों की सफाई के दौरान निकाला गया अतिरिक्त कचरा और कबाड़ मुख्य सड़कों, गलियों और चौराहों पर ही पड़ा हुआ है, जिसे उठाने वाला कोई नहीं है।

घरों की सफाई का कचरा और हड़ताल बनी जी का जंजाल- त्योहारी सीजन के मद्देनजर इन दिनों हर घर में विशेष सफाई अभियान चल रहा है। घरों से निकलने वाला पुराना सामान, कचरा और मलबे जैसी चीजें लोग सड़कों के किनारे या कॉलोनियों के बाहर डाल रहे हैं। लेकिन, सफाई कर्मियों के काम पर न होने के कारण यह कचरा सड़कों पर ही सड़ रहा है। न्यू मार्केट, एमपी नगर, पुराने शहर के बाजारों से लेकर आवासीय कॉलोनियों तक हर तरफ कचरे के अंबार और उससे उठने वाली दुर्गंध ने नागरिकों का जीना मुहाल कर दिया है।





सफाई कर्मचारियों ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर बीते दिनों जोरदार प्रदर्शन किया था। कर्मचारियों को उम्मीद थी कि इस आंदोलन के बाद शासन या नगर निगम प्रशासन की तरफ से उनकी मांगों पर कोई सकारात्मक पहल होगी। लेकिन, कोई ठोस आश्वासन न मिलने के कारण कर्मचारियों ने काम ठप कर दिया, जिससे अब यह विकट स्थिति उत्पन्न हो गई है। त्योहार की इस व्यस्तता के बीच बाजारों और गलियों में फैली इस गंदगी के कारण संक्रामक बीमारियां फैलने का गंभीर खतरा मंडराने लगा है। त्योहारी उमंग के बीच मक्खियों-मच्छरों के प्रकोप और गंदगी के ढेरों ने बच्चों, बुजुर्गों और आम नागरिकों की सेहत पर बड़ा संकट खड़ा कर दिया है। व्यापारियों और शहरवासियों का कहना है कि जब प्रशासन को यह भली-भांति पता था कि इस सीजन में घरों और बाजारों से सबसे अधिक कचरा निकलता है, तो ऐसे में समय रहते वैकल्पिक व्यवस्था क्यों नहीं की गई? फिलहाल, शहर की जनता की निगाहें एक बार फिर नगर निगम के उच्च अधिकारियों पर टिकी हैं कि वे कब इस गंभीर समस्या का संज्ञान लेते हैं और त्योहारी सीजन में शहर को इस बदहाली से मुक्ति दिलाते हैं।

महतारी वंदन की 33वीं किस्त जारी

विधायक ललित चंद्राकर बोले- महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण को समर्पित है सरकार

यश भारत



दुर्ग। छत्तीसगढ़ राज्योत्सव के समापन अवसर पर नवा रायपुर स्थित राज्योत्सव मैदान से केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने महतारी वंदन योजना की 33वीं किस्त जारी की। इसके तहत प्रदेश की पात्र महिला हितग्राहियों के बैंक खातों में डीबीटी के माध्यम से एक-एक हजार रुपये की राशि अंतरित की गई। दिवाली से पहले मिली इस आर्थिक सहायता को महिलाओं के लिए खुशियों के उपहार के रूप में देखा जा रहा है।

महतारी वंदन योजना की 33वीं किस्त जारी होने पर दुर्ग ग्रामीण विधायक ललित चंद्राकर ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय एवं प्रदेश सरकार के प्रति आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी के अनुरूप प्रदेश सरकार महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में लगातार कार्य कर रही है।

विधायक चंद्राकर ने कहा कि महतारी वंदन योजना के माध्यम से दुर्ग ग्रामीण सहित प्रदेश की लाखों महिलाओं को प्रतिमाह आर्थिक सहायता मिल रही है। इस राशि से महिलाएं अपनी छोटी-छोटी जरूरतों को स्वयं पूरा कर पा रही हैं। महिलाओं के चेहरे पर खुशी और उनके जीवन में आ रहा सकारात्मक बदलाव ही इस योजना की सार्थकता को दर्शाता है।

उन्होंने कहा कि महिलाओं का सम्मान और उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त बनाना केंद्र एवं राज्य सरकार की प्राथमिकता है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में प्रदेश सरकार किसानों, महिलाओं, युवाओं सहित समाज के प्रत्येक वर्ग के कल्याण के लिए कार्य कर रही है। किसानों से 3100 रुपये प्रति क्विंटल की दर से धान खरीदी सहित विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से लोगों को आर्थिक संबल प्रदान किया जा रहा है।

विधायक ने कहा कि महतारी वंदन योजना की 33वीं किस्त जारी होना महिला सशक्तिकरण की दिशा में सरकार के निरंतर प्रयासों का हिस्सा है। राज्य सरकार यह सुनिश्चित कर रही है कि योजना की पात्र महिलाओं को नियमित रूप से इसका लाभ मिलता रहे।

उन्होंने कहा कि महिला सशक्तिकरण से परिवारों में समृद्धि आएगी और हर आंगन में खुशियों की रोशनी फैलेगी। इस जनकल्याणकारी पहल के लिए उन्होंने केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, महिला एवं बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े तथा प्रदेश मंत्रिमंडल के सभी सदस्यों के प्रति आभार व्यक्त किया।

जनगणना और परीक्षाओं के बीच नियमों को ताक पर रखकर बेची जा रही है पोस्टिंग, शिक्षा विभाग बना वसूलीबाजों का चारागाह - कांग्रेस

यश भारत



रायपुर। जनगणना और एसआईआर जैसी अत्यंत संवेदनशील और कानूनी रूप से प्रतिबंधित प्रशासनिक प्रक्रियाओं के बीच चल रहे बेलगाम तबादला उद्योग पर सवाल उठाते हुए प्रदेश कांग्रेस संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने कहा है कि इस सरकार में तबादला कोई प्रशासनिक प्रक्रिया नहीं, बल्कि बोली लगाने वाला एक खुला बाजार बन चुका है। चुनाव आयोग के नियमों को ताक पर रखकर जनगणना के समय ट्रांसफर करना, प्रशासनिक अराजकता की पराकाष्ठा है। सबसे अग्रणी स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट है, छत्तीसगढ़ के शिक्षा के मंदिर को इन लोगों ने वसूलीबाजों का चारागाह बना दिया है, जहां अर्धवार्षिक परीक्षा के समय गरीब बच्चों की पढ़ाई दांव पर लगी है।

प्रदेश कांग्रेस संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने कहा है कि आज छत्तीसगढ़ की भाजपा सरकार ने राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था और शिक्षा व्यवस्था को पूरी तरह से गर्त में धकेल दिया है। भारत सरकार और चुनाव आयोग के स्पष्ट निर्देश हैं कि जनगणना और एसआईआर प्रक्रिया के दौरान ड्यूटीरत कर्मचारियों-अधिकारियों का ट्रांसफर पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। लेकिन, साय सरकार में नियमों की बलि चढ़ाकर खुलेआम तबादला उद्योग चलाया जा रहा है। शिक्षा विभाग इसमें नंबर वन बन चुका है। शिक्षक विहीन और एकल शिक्षकीय स्कूलों की चिंता इस सरकार को नहीं है उल्टे वहां पर से सुविधाजनक स्थानों पर पदस्थ कर रहे हैं। अर्धवार्षिक परीक्षाओं के ठीक बीच में, मोटी रकम की बोलियां लगाकर शिक्षकों और कर्मचारियों की पोस्टिंग खरीदी-बेची जा रही है। यह सरकार जनता के विकास के लिए नहीं, बल्कि उगाही और दलाली के लिए आई है। प्रदेश कांग्रेस संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने कहा है कि जनगणना जैसे गोपनीय और राष्ट्रीय कार्य के बीच में तबादलों का खेल इस बात का सबूत है कि इस सरकार में नीति-नियम नहीं, बल्कि वसूली का रेट कार्ड चल रहा है। छत्तीसगढ़ के गरीब बच्चों की शिक्षा को सत्ता में बैठे लोगों ने अपनी तिजोरी भरने का साधन बना लिया है। दूरदराज के आदिवासी और ग्रामीण अंचलों के स्कूलों को भगवान भरोसे छोड़कर शहरों में दलालों के जरिए पोस्टिंग बेची जा रही है। क्या अर्धवार्षिक परीक्षाओं और जनगणना के बीच में ही प्रशासनिक आवश्यकता जागती है? क्या ट्रांसफर के बदले ली जा रही दलाली के रेट तय करना ही साय का सुशासन है?

छह गारंटियों के साथ रिसाली में आम आदमी पार्टी ने खोला संभागीय कार्यालय

शिक्षा, खेल और पारदर्शी नगर निगम व्यवस्था पर जोर, जनता के लिए निशुल्क एंबुलेंस सुविधा भी शुरू

यश भारत



रिसाली। आगामी नगरीय निकाय चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी ने रिसाली में अपनी चुनावी गतिविधियां तेज कर दी हैं। पार्टी ने छह गारंटियों के साथ बदलाव, विकास और जनता के सम्मान का संकल्प लेकर रिसाली में अपने संभागीय कार्यालय का शुभारंभ किया। छत्तीसगढ़ प्रभारी एवं दिल्ली के पूर्व मंत्री मुकेश अहलावत ने फीता काटकर कार्यालय का उद्घाटन किया।

बच्चों की शिक्षा और खेल पर पहली गारंटी

आम आदमी पार्टी ने अपनी प्रमुख गारंटियों में हर बच्चे को बेहतर शिक्षा और खेल सुविधाएं देने का वादा किया है। इसके तहत हृश्वश्वज्ञ और छ्वश्व जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं की निशुल्क कोचिंग तथा खेल मैदानों के विकास की बात कही गई है। पार्टी का कहना है कि बच्चों को बेहतर अवसर उपलब्ध कराना उसकी प्राथमिकता होगी।

पारदर्शी निगम व्यवस्था का वादा

पार्टी की दूसरी प्रमुख गारंटी नगर निगम में पारदर्शिता लाने की है। इसके तहत भ्रष्टाचार और कमीशनखोरी पर रोक लगाने के साथ निगम के बजट और विकास योजनाओं की जानकारी जनता के सामने सार्वजनिक करने का दावा किया गया है। पार्टी ने स्पष्ट किया कि जनता का पैसा केवल जनता के विकास पर खर्च होना चाहिए।

निशुल्क एंबुलेंस सुविधा की शुरुआत

कार्यालय उद्घाटन के अवसर पर रिसाली की जनता के लिए निशुल्क एंबुलेंस सुविधा भी शुरू की गई। प्रदेश संगठन मंत्री संजीत विश्वकर्मा की पहल पर मुख्य अतिथि मुकेश अहलावत ने एंबुलेंस सुविधा जनता को समर्पित की। पार्टी ने इसे जनसेवा की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया।

संजीत विश्वकर्मा और गीतेश्वरी बघेल के नेतृत्व में आयोजन

प्रदेश संगठन मंत्री संजीत विश्वकर्मा और दुर्ग लोकसभा अध्यक्ष गीतेश्वरी बघेल के नेतृत्व में आयोजित कार्यक्रम में बड़ी संख्या में पार्टी पदाधिकारी, कार्यकर्ता और क्षेत्रीय नागरिक शामिल हुए। कार्यक्रम में पहुंचे लोगों ने पार्टी की नीतियों और चुनावी गारंटियों में रुचि दिखाई। अतिथियों ने आयोजन और संगठन की सक्रियता को लेकर संजीत विश्वकर्मा की सराहना भी की।

सभी वार्डों में बेहतर सुविधाएं देने का संकल्प

इस दौरान पार्टी ने रिसाली नगर निगम के सभी वार्डों में बेहतर मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने की बात कही। शिक्षा, बिजली, पानी और रोजगार सहित विभिन्न मुद्दों पर अपनी छह गारंटियों का ब्यौरा जनता के सामने रखा। साथ ही आगामी नगरीय निकाय चुनाव में पार्टी को समर्थन देने की अपील की। कार्यक्रम में प्रदेश संगठन मंत्री संजीत विश्वकर्मा, दुर्ग लोकसभा अध्यक्ष गीतेश्वरी बघेल, देवेंद्र सिंह भाटिया प्रदेश प्रभारी छत्तीसगढ़ मुकेश अहलावत, प्रदेश सह प्रभारी समर कुमार प्रदेश संगठन मंत्री एवं दुर्ग राजनांदगांव संभाग प्रभारी, रिसाली नगर निगम चुनाव प्रभारी संजीत विश्वकर्मा दुर्ग लोकसभा अध्यक्ष एवं रिसाली नगर निगम चुनाव सह प्रभारी श्रीमती गीतेश्वरी बघेल प्रदेश सचिवट्ठ देविंदर सिंह भाटिया लक्ष्मी निर्मलकर,बसंती साहू, मोहसिन अहमद रीता चौधरी, मालती यादव , कुन्ती ठाकुर, असलम खान रूबी खान, सुषमा गायकवाड, ज्योति चंदेल, छगन चंदेल, लीलावती चौधरी, लालती चौधरी, पिंकी चौधरी, प्रमिला, प्रेमन, रीमान पटेल , सुनीता देशलहरा, भानुमति देशलहरा, शिवा रायुडु, योगिता देशलहरा, गीता, सन्नी सिका, दीपक साहू,सहित क्षेत्रीय पदाधिकारी, कार्यकर्ता और बड़ी संख्या में आम नागरिक मौजूद रहे।

शहर की प्रकाश व्यवस्था को सुदृढ़ करने आयुक्त ने ली अधिकारियों की बैठक

यश भारत



भिलाईनगर। नगर पालिक निगम भिलाई की आयुक्त सुरूचि सिंह ने आज निगम सभागार कक्ष में शहर की प्रकाश व्यवस्था को लेकर अधिकारियों की बैठक ली। बैठक में उन्होंने शहर के सभी क्षेत्रों में प्रकाश व्यवस्था को बेहतर एवं सुचारू बनाने के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। आयुक्त ने कहा कि नागरिकों की सुविधा, सुरक्षा एवं आवागमन को ध्यान में रखते हुए शहर की प्रकाश व्यवस्था को सुदृढ़ करना निगम की प्राथमिकता है।आयुक्त ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि शहर के प्रमुख मार्गों, चौक-चौराहों, गली-मोहल्लों एवं बाजार क्षेत्रों में विशेष प्राथमिकता के साथ स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। जिन स्थानों पर लाइट बंद हैं अथवा प्रकाश की पर्याप्त व्यवस्था नहीं है, उनका चिन्हांकन कर तत्काल सुधार कार्य कराया जाए। आवश्यकता वाले स्थानों पर नई लाइट लगाने के साथ ही खराब एवं बंद पड़ी लाइटों को शीघ्र बदलने की कार्रवाई की जाए, ताकि शहर के नागरिकों को रात्रि के समय आवागमन में किसी प्रकार की परेशानी न हो। बैठक में आयुक्त ने सीएम हेल्पलाइन पोर्टल, जनदर्शन एवं अन्य ऑनलाइन माध्यमों से प्राप्त प्रकाश व्यवस्था संबंधी शिकायतों की भी समीक्षा करते हुए अधिकारियों को उनका त्वरित निराकरण करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि नागरिकों से प्राप्त शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए समय-सीमा में समाधान सुनिश्चित किया जाए। शिकायतों के निराकरण में किसी प्रकार की लापरवाही नहीं होनी चाहिए आयुक्त ने अधिकारियों को आपसी समन्वय के साथ कार्य करते हुए शहर की प्रकाश व्यवस्था की नियमित मॉनिटरिंग करने तथा आवश्यकतानुसार मैदानी निरीक्षण कर व्यवस्था में सुधार लाने के निर्देश दिए। निगम का प्रयास है कि शहर के प्रत्येक वार्ड में पर्याप्त प्रकाश व्यवस्था उपलब्ध हो, जिससे नागरिकों को सुरक्षित एवं सुविधाजनक वातावरण मिल सके।

पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से बिजली खर्च में मिल रही राहत

विशाल शाह ने 05 किलोवाट सोलर पैनल लगवाकर उठाया योजना का लाभ

यश भारत



सुकमा। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के माध्यम से जिले के नागरिक सौर ऊर्जा को अपनाकर बिजली खर्च में बचत कर रहे हैं। इसी कड़ी में नगर पालिका सुकमा के बगीचा पारा निवासी विशाल शाह ने योजना का लाभ लेते हुए अपने घर पर 05 किलोवाट क्षमता का सोलर पैनल स्थापित कराया है।

विशाल शाह ने बताया कि पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना की जानकारी मिलने के बाद उन्होंने अपने घर में सोलर पैनल लगवाने का निर्णय लिया। 05 किलोवाट क्षमता का सोलर पैनल स्थापित होने से अब उनके घर में बिजली की जरूरत सौर ऊर्जा के माध्यम से पूरी हो रही है। इससे उन्हें बिजली खर्च में राहत मिल रही है और पारंपरिक बिजली पर निर्भरता भी कम हुई है।

उन्होंने बताया कि सोलर पैनल से उत्पादित बिजली का घरेलू उपयोग करने के साथ ही अतिरिक्त बिजली ग्रिड में भेजी जा सकती है। इसके बदले बिजली खाते में क्रेडिट दर्ज होता है, जिसका समायोजन आगामी बिजली बिल में किया जाता है। इस व्यवस्था से सौर ऊर्जा का बेहतर उपयोग हो रहा है और परिवार को आर्थिक बचत का लाभ मिल रहा है।

विशाल शाह ने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना को आम नागरिकों के लिए उपयोगी एवं लाभकारी पहल बताते हुए कहा कि इससे परिवारों को बिजली खर्च में राहत मिलने के साथ स्वच्छ एवं नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा मिल रहा है। उन्होंने मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय को योजनांतर्गत सब्सिडी दिलाने के लिए धन्यवाद ज्ञापित किया।

आरटीओ विभाग में एनआईसी प्रोग्रामर की कार्यशैली पर उठे सवाल

हफ्तों तक फाइलें अटकाने और काम न करने की चेतावनी देने का आरोप

यश भारत



राजनांदगांव (दावा)। जिला परिवहन विभाग में नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर (एनआईसी) से जुड़े तकनीकी कार्यों और फाइलों के निपटारे को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं।

एनआईसी प्रोग्रामर कुंदन तिवारी की कार्यशैली और कथित मनमाने व्यवहार को लेकर संबंधित पक्षों में भारी नाराजगी देखी जा रही है। आरोप है कि सामान्य व जरूरी तकनीकी कार्यों के लिए भी कई-कई हफ्तों तक चक्कर काटने पड़ते हैं, जिससे शासकीय कामकाज की गति प्रभावित हो रही है।

कार्यशैली से परेशान लोगों में आक्रोश

मामले में सबसे गंभीर आरोप यह सामने आया है कि जब कोई काम की प्रगति जानने या फॉलोअप करने के लिए संपर्क करता है, तो कथित तौर पर उन्हें दो टूक कह दिया जाता है कि 'बार-बार फॉलोअप करोगे तो काम ही नहीं करूंगा।' इस प्रकार की कार्यशैली से परेशान लोगों का कहना है कि संबंधित प्रोग्रामर का रवैया ऐसा रहता है मानो उनके सामने किसी पद, प्रोटोकॉल या शासकीय दायित्व की कोई अहमियत ही न हो। उनके कथित ऊंचे तेवर और असंवेदनशील रुख को लेकर अब विभागीय स्तर पर भी कानाफूसी तेज हो गई है।

जवाबदेही और सेवा शर्तों पर भी उठ रहे सवाल

इस पूरे प्रकरण ने परिवहन विभाग की सरकारी व्यवस्था में जवाबदेही और कार्य संस्कृति पर बड़ा सवालिया निशान लगा दिया है।

आखिर जनता और विभागों के काम को अपनी मर्जी से अटकाने या रोकने का अधिकार किसे है? साथ ही यह भी सवाल उठ रहा है कि संबंधित प्रोग्रामर की नियुक्ति, संविदा अथवा सेवा शर्तें क्या हैं और उनकी सीधी जवाबदेही किस उच्चाधिकारी के प्रति तय है।

प्रशासनिक समीक्षा की मांग

शासकीय दफ्तरों में सहयोग, पारदर्शिता और संवेदनशीलता की अपेक्षा की जाती है, न कि अपने ही वाजिब काम के लिए दुर्व्यवहार सहने की। कार्यों में अनावश्यक लेटलतीफी और कथित दुर्व्यवहार के बढ़ते मामलों को देखते हुए अब जिला प्रशासन व एआरटीओ अनिल भगत से इस पूरे मामले की निष्पक्ष समीक्षा और ठोस कार्रवाई की मांग की जा रही है।

जिला स्तरीय तिलहन मेले में सांसद विजय बघेल ने किसानों को किया संबोधित

किसान देश की अर्थव्यवस्था की मजबूत रीढ़

यश भारत



दुर्ग। कृषि विभाग द्वारा खूबचंद बघेल सभागार, अटारी पाटन में जिला स्तरीय तिलहन मेले का आयोजन किया गया। मेले में किसानों को कृषि विशेषज्ञों द्वारा तिलहन फसलों में लगने वाले कीट एवं रोगों की पहचान, उनके उपचार तथा आधुनिक कृषि तकनीकों की जानकारी दी गई।

कार्यक्रम के मुख्य अतिथि दुर्ग लोकसभा सांसद श्री विजय बघेल ने किसानों को संबोधित करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा और भारत को कृषि प्रधान देश कहा जाता है। देश की अर्थव्यवस्था की मजबूती में किसानों का महत्वपूर्ण योगदान है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसानों और मजदूरों की चिंता करते हुए उनके हित में लगातार योजनाएं बना रहे हैं, जिसका सकारात्मक परिणाम देश की अर्थव्यवस्था में देखने को मिल रहा है।

श्री बघेल ने कहा कि वर्तमान समय तकनीक का युग है। कृषि क्षेत्र में आधुनिक उपकरणों और नई तकनीकों के उपयोग से किसान उन्नत किस्म की फसलें तैयार कर आर्थिक रूप से मजबूत हो रहे हैं। उन्होंने हाल ही में प्राकृतिक आपदा से फसलों को हुए नुकसान पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि किसानों को निराश होने की आवश्यकता नहीं है। केंद्र एवं प्रदेश सरकार किसानों के साथ खड़ी है। फसल क्षति से प्रभावित किसानों को मुआवजा उपलब्ध कराने के निर्देश भी दिए गए हैं।

उन्होंने किसानों से रासायनिक खाद के अत्यधिक उपयोग से बचने तथा जैविक खाद को प्राथमिकता देने की अपील की, ताकि खेती की गुणवत्ता और मिट्टी की उर्वरता बनी रहे। इस अवसर पर किसानों को सरसों के बीज किट भी वितरित किए गए। कार्यक्रम में जिला पंचायत सदस्य श्रीमती नीलम राजेश चंद्राकर, जनपद अध्यक्ष कीर्ति नायक, उपाध्यक्ष कमलेश वर्मा, नगर पंचायत अध्यक्ष योगेश निक्की भाले, उपाध्यक्ष श्रीमती निशा सोनी, केवल देवांगन, प्रकाश बिजौरा, सहायक संचालक सुमन कोर्राम, राजा पाठक, रूप सिंह सिन्हा, वीरेंद्र साहू, डेहरलाल, मुकेश मढ़रिया, मानधाता वर्मा, मनीष साहू, हरीश वर्मा, शीतल साहू, नागेश कश्यप, सुनील वर्मा, रूपेंद्र साहू, छगन साहू, ममता वर्मा, योगेश वर्मा, झरना चंद्राकर, सतीश वर्मा सहित कृषि विभाग के अधिकारी-कर्मचारी एवं बड़ी संख्या में किसान उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संचालन परमेश साहू ने किया तथा आभार प्रदर्शन वरिष्ठ कृषि अधिकारी पुष्पा राम टेके ने किया।

राज्योत्सव बना विधिक जागरूकता का माध्यम, सुरक्षित बचपन अभियान के तहत बच्चों को मिली अधिकारों की सीख

यश भारत

कोण्डागांव । प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश/अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कोंडागांव खिलावन राम रिगरी* के मार्गदर्शन में छत्तीसगढ़ राज्योत्सव के अवसर पर विकास नगर स्टेडियम, कोंडागांव में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, कोंडागांव द्वारा विधिक जागरूकता स्टॉल लगाया गया। इस दौरान राज्योत्सव में नागरिकों को उनके कानूनी अधिकारों, निःशुल्क विधिक सहायता एवं शासन की विभिन्न विधिक कल्याणकारी योजनाओं के संबंध में जानकारी देकर जागरूक किया गया।

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, कोंडागांव की सचिव गायत्री साय* द्वारा स्टॉल में उपस्थित महिलाओं एवं बच्चों को विशेष रूप से उनके अधिकारों और कानूनी संरक्षण के संबंध में विस्तारपूर्वक जानकारी दी गई। महिलाओं को घरेलू हिंसा से संरक्षण, महिलाओं के कानूनी अधिकार, निःशुल्क विधिक सहायता एवं महिला सुरक्षा से संबंधित कानूनी प्रावधानों के बारे में बताया गया। वहीं बच्चों को बाल अधिकार, बाल संरक्षण, बाल विवाह, बाल शोषण एवं लैंगिक अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम (पॉक्सो एक्ट) के संबंध में जागरूक किया गया।वहीं राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली एवं छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, बिलासपुर* के निर्देशानुसार संचालित 'सुरक्षित बचपन अभियान' के तहत बच्चों को विशेष रूप से जागरूक किया गया। उन्हें बाल अधिकार, बाल विवाह की रोकथाम, बाल श्रम, बाल शोषण, लैंगिक अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम (पॉक्सो एक्ट), गुड टच-बैड टच तथा साइबर सुरक्षा जैसे महत्वपूर्ण विषयों की जानकारी दी गई। साथ ही बच्चों को किसी भी प्रकार की परेशानी, शोषण अथवा अनुचित व्यवहार होने पर बिना डर और संकोच के अपने अभिभावकों, शिक्षकों अथवा संबंधित अधिकारियों को इसकी जानकारी देने के लिए प्रेरित किया गया। इसके साथ ही आम नागरिकों को बताया गया कि आर्थिक रूप से कमजोर एवं पात्र व्यक्तियों को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के माध्यम से निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध कराई जाती है। किसी भी व्यक्ति को न्याय प्राप्त करने में आर्थिक या अन्य किसी प्रकार की बाधा नहीं होनी चाहिए। विधिक सहायता प्राप्त करने एवं अपनी समस्याओं के निराकरण के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण से संपर्क किया जा सकता है। इस पहल का उद्देश्य राज्योत्सव जैसे जनसामान्य के बड़े आयोजन के माध्यम से अधिक से अधिक लोगों तक विधिक जानकारी पहुंचाना तथा उन्हें अपने अधिकारों एवं कर्तव्यों के प्रति जागरूक करना है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा आम नागरिकों को न्याय सुलभ कराने एवं समाज के प्रत्येक वर्ग तक विधिक जागरूकता पहुंचाने के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं।

हार्दिक पांड्या छोड़ेंगे मुंबई इंडियंस का साथ

पंजाब किंग्स में ट्रेड होने की बड़ी खबर, अर्शदीप सिंह जाएंगे एमआई!

मुंबई, यशभारत। आईपीएल 2027 के 20वें सीजन के आगाज होने से पहले एक चौंकाने वाली खबर सामने आ रही है। पिछले सीजन में मुंबई इंडियंस की कप्तानी करने वाले स्टार ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या आगामी सीजन में पंजाब किंग्स की जर्सी में नजर आ सकते हैं।



दरअसल, रिपोर्ट्स के मुताबिक, मुंबई इंडियंस और पंजाब किंग्स के बीच हार्दिक पांड्या को लेकर एक बड़े ट्रेडज यानी खिलाड़ियों की अदला-बदली पर बातचीत अंतिम दौर में पहुंच चुकी है।

पंजाब किंग्स में जाएंगे पांड्या?

दरअसल, स्पोर्टस्टार की एक रिपोर्ट के अनुसार, पंजाब किंग्स ट्रेड विंडो के जरिए हार्दिक पांड्या को अपनी टीम में शामिल करने के समझौते के बेहद करीब पहुंच गई है। मुख्य कोच रिकी पोंटिंग की देखरेख में पंजाब फ्रेंचाइजी की मुंबई इंडियंस के साथ बातचीत काफी आगे बढ़ चुकी है।

इस मेगा ट्रेड डील के तहत, भारतीय स्टार तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह और विकेटकीपर-बल्लेबाज विष्णु विनोद के मुंबई इंडियंस (रूढ़) में जाने की पूरी संभावना है। अगर यह डील फाइनल होती है, तो अर्शदीप सिंह आईपीएल इतिहास में पहली बार पंजाब किंग्स के अलावा किसी दूसरी फ्रेंचाइजी के लिए खेलते हुए दिखाई देंगे। बता दें कि हार्दिक पांड्या को ट्रेड करने के लिए मुंबई इंडियंस ने केवल पंजाब ही नहीं, बल्कि कम से कम 3 अन्य आईपीएल फ्रेंचाइजी के साथ भी संभावनाएं तलाशी थीं। खबरों की मानें तो पंजाब किंग्स के अलावा कोलकाता नाइट राइडर्स (चयक्र) ही एकमात्र ऐसी टीम थी, जिसके साथ मुंबई इंडियंस की बातचीत काफी आगे बढ़ी थी।

पंजाब ने अर्शदीप को 18 करोड़ में रखा था बरकरार

गौरतलब है कि पंजाब किंग्स ने आईपीएल 2025 की मेगा नीलामी से पहले अर्शदीप सिंह को रिलीज कर दिया था। हालांकि, ऑक्शन टेबल पर पंजाब ने च्वाइट टू मैचज (ऋक्षरू) कार्ड का इस्तेमाल करके उन्हें वापस अपनी टीम में शामिल किया। नीलामी के दौरान सनराइजर्स हैदराबाद (स्क्रा) ने अर्शदीप के लिए अपनी बोली को 15.75 करोड़ रुपये से बढ़ाकर सीधे 18 करोड़ रुपये कर दिया था, जिसके बाद PBKS ने इसी मैचिंग प्राइस (18 करोड़ रुपये) की पेशकश कर इस धाकड़ बाएं हाथ के तेज गेंदबाज को अपने साथ बरकरार रखा था। हार्दिक पांड्या आईपीएल 2024 से पहले गुजरात टाइटंस से एक पूरी तरह से कैश डील के जरिए मुंबई इंडियंस में वापस लौटे थे। इससे पहले उन्होंने गुजरात टाइटंस के साथ दो बेहद सफल सीजन बिताए थे, जहां 2022 में उन्होंने अपनी कप्तानी में टीम को डेब्यू सीजन में ही खिताब जिताया था। हालांकि, मुंबई इंडियंस के कप्तान के रूप में उनकी वापसी सफल नहीं रही।

सिंधु और चानू समेत 10 खिलाड़ी आईओए एथलीट्स कमीशन में निर्विरोध निर्वाचित

सुधा सिंह और किदांबी श्रीकांत के नाम वापस लेने से मतदान की जरूरत नहीं पड़ी, 7 नवंबर को होगा चेयरमैन और वाइस चेयरमैन का चुनाव

नई दिल्ली। यशभारत। ओलंपिक पदक विजेता पीवी सिंधु और मीराबाई चानू समेत 10 दिग्गज खिलाड़ियों को भारतीय ओलंपिक संघ (आईओए) के एथलीट्स कमीशन में निर्विरोध चुन लिया गया है। मंगलवार को रिटर्निंग ऑफिसर संजय के. श्रीवास्तव ने सभी 10 सदस्यों के निर्वाचन की औपचारिक घोषणा की। आयोग में पांच पुरुष और पांच महिला खिलाड़ियों को जगह मिली है। सभी सदस्यों का कार्यकाल 2026 से 2030 तक रहेगा। दो उम्मीदवारों के नाम वापस लेने के कारण 3 नवंबर को प्रस्तावित मतदान रद्द करना पड़ा।

पूर्व एथलीट सुधा सिंह ने सोमवार देर रात अपनी उम्मीदवारी वापस ले ली थी। इससे पहले बैडमिंटन खिलाड़ी किदांबी श्रीकांत भी सोमवार को चुनाव मैदान से हट गए थे। दोनों के हटने के बाद 10 पदों के लिए 10 ही उम्मीदवार शेष रह गए। ऐसे में सभी का निर्विरोध निर्वाचन तय हो गया और मतदान कराने की आवश्यकता नहीं पड़ी।

आईओए के चुनाव नियमों के अनुसार 10 सदस्यीय एथलीट्स कमीशन में छह ऐसे खिलाड़ियों का होना अनिवार्य है, जिन्होंने पिछले तीन ओलंपिक में से कम से कम एक में भारत का प्रतिनिधित्व किया हो। इस श्रेणी में तीन पुरुष और तीन महिला खिलाड़ियों को शामिल किया जाता है। शेष चार सीटें उन खिलाड़ियों के लिए निर्धारित हैं, जिन्होंने पिछले तीन एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स, विश्व चैंपियनशिप, विश्व कप या राष्ट्रीय खेलों में कम से कम एक पदक जीता हो। इस श्रेणी में दो पुरुष और दो महिला खिलाड़ियों को जगह दी जाती है। ओलंपिक श्रेणी से पुरुषों में हॉकी खिलाड़ी हरमनप्रीत सिंह, तैराक साजन प्रकाश और एथलेटिक्स खिलाड़ी तजिंदरपाल सिंह तूर चुने गए हैं। महिलाओं में पीवी सिंधु, भारोत्तोलक मीराबाई चानू और तीरंदाज बॉम्बेला देवी को जगह मिली है। वहीं, पदक विजेता श्रेणी से पुरुषों में



निशानेबाज स्वप्निल कुसाले और मंजीत सिंह तथा महिलाओं में हॉकी खिलाड़ी सलीमा टेटे और तलवारबाज भवानी देवी निर्वाचित हुई हैं। एशियाई ओलंपिक परिषद के एथलीट्स कमीशन के दो भारतीय प्रतिनिधि भी आईओए कमीशन के पदेन सदस्य होंगे। इनमें उपाध्यक्ष शिवा केशवन और हाल ही में नियुक्त राजेश्वरी कुमारी शामिल हैं। इस तरह चेयरमैन और वाइस चेयरमैन के चुनाव में कुल 12 सदस्य मतदान करेंगे।

मैरी कॉम के कार्यकाल वाले आयोग के तीन सदस्य फिर चुने गए

आईओए के पूर्व एथलीट्स कमीशन की अध्यक्ष मुक्केबाज मैरी कॉम थीं। उस आयोग में पीवी सिंधु, मीराबाई चानू और भवानी देवी भी सदस्य थीं। तीनों खिलाड़ियों ने एक बार फिर अपनी जगह बरकरार रखी है।

7 नवंबर को होगा नेतृत्व का फैसला

नए चुने गए सदस्य अब एथलीट्स कमीशन के चेयरमैन और वाइस चेयरमैन का चुनाव करेंगे। इन दोनों पदों में एक पुरुष और एक महिला का चुना जाना अनिवार्य है। इसके लिए 4 और 5 नवंबर को नामांकन दाखिल किए जाएंगे, जबकि 6 नवंबर को उम्मीदवारों की अंतिम सूची जारी होगी। 7 नवंबर को वर्चुअल माध्यम से मतदान कराया जाएगा। चेयरमैन पद के लिए केवल ओलंपिक श्रेणी के छह सदस्य ही उम्मीदवार बन सकेंगे। वहीं, पदेन सदस्यों सहित सभी 12 सदस्य मतदान में हिस्सा लेंगे। एशियाई ओलंपिक परिषद के प्रतिनिधि शिवा केशवन और राजेश्वरी कुमारी इन पदों के लिए उम्मीदवार नहीं बन सकेंगे। नियमों के मुताबिक कोई सदस्य चेयरमैन-वाइस चेयरमैन के चुनाव अथवा आईओए की जनरल बॉडी के दो प्रतिनिधियों के चुनाव में से किसी एक के लिए ही उम्मीदवार बन सकता है।

कार्यकारी परिषद में भी मिलेगी अहम भूमिका

एथलीट्स कमीशन के चेयरमैन और वाइस चेयरमैन आईओए की कार्यकारी परिषद के सदस्य भी बनेंगे। इसके अलावा आयोग के दो प्रतिनिधि, एक पुरुष और एक महिला, मतदान के अधिकार के साथ आईओए की जनरल बॉडी में शामिल होंगे। ये दोनों प्रतिनिधि 5 दिसंबर को होने वाले आईओए की कार्यकारी परिषद के चुनाव में भी मतदान करेंगे। हॉकी खिलाड़ी सलीमा टेटे की उम्र फिलहाल 24 वर्ष है। इस कारण वह चेयरमैन या वाइस चेयरमैन पद का चुनाव नहीं लड़ सकतीं, क्योंकि इन पदों के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष निर्धारित है। हालांकि, जनरल बॉडी के दो प्रतिनिधियों के चुनाव में उम्मीदवार बनने के लिए न्यूनतम आयु 18 वर्ष है। ऐसे में सलीमा इस चुनाव में अपनी दावेदारी पेश कर सकती हैं।

34 हजार की क्षमता और 80 लाख दावेदार, वनडे विश्व कप 2027 में भारत-पाक मैच के टिकटों की मची भारी लूट

मुंबई,यशभारत। आईसीसी वनडे विश्व कप 2027 में भारत और पाकिस्तान के बीच होने वाले महामुकाबले के लिए टिकटों की अभूतपूर्व मांग चल रही है। जोहान्सबर्ग के वांडरर्स स्टेडियम में होने वाले इस मैच के लिए 80 लाख से अधिक टिकटों के अनुरोध आए हैं, जबकि स्टेडियम की क्षमता सिर्फ 34,000 सीटों की है। जानें आईसीसी (ढ्ढष्टष्ठ) का क्या कहना है। क्रिकेट जगत की सबसे बड़ी प्रतिद्वंद्विता यानी भारत और पाकिस्तान के बीच होने वाले मैचों का क्रेज किस कदर सिर चढ़कर बोलता है, इसका अंदाजा आगामी वनडे विश्व कप 2027 के टिकटों की मांग से लगाया जा सकता है। जोहान्सबर्ग के वांडरर्स स्टेडियम में होने वाले भारत-पाकिस्तान मैच के लिए अब तक 80 लाख से अधिक प्रशंसकों ने टिकटों की मांग की है, जबकि इस ऐतिहासिक मैदान की दर्शक क्षमता महज 34,000 सीटों की है। ढ्ढष्टष्ठ द्वारा जारी किए गए इन आंकड़ों ने



टिकटिंग इतिहास के पुराने कई रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। दरअसल, अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (ICC) ने हाल ही में पुष्टि की है कि भारत-पाकिस्तान मैच के टिकटों के लिए चल रहे बैलेट यानी लॉटरी प्रक्रिया के जरिए कुल 8,397,294 (लगभग 84 लाख) अनुरोध प्राप्त हुए हैं। दिलचस्प बात यह है कि 21 नवंबर को इसी मैदान पर होने वाले विश्व कप फाइनल के लिए अब तक लगभग 79 लाख अनुरोध ही आए हैं। यानी फाइनल मुकाबले से भी ज्यादा क्रेज भारत और पाकिस्तान के लीग मैच को लेकर है। बता दें कि, इस मेगा टूर्नामेंट के लिए आईसीसी की टिकट बैलट प्रक्रिया को दुनिया भर से अभूतपूर्व प्रतिक्रिया मिल रही है। अब तक 193 देशों के प्रशंसकों की ओर से कुल 12 करोड़ से अधिक टिकट अनुरोध प्राप्त हो चुके हैं। इस प्रतियोगिता को लाइव देखने के लिए करीब 28 लाख अलग-अलग क्रिकेट प्रेमियों ने अपनी रुचि दिखाई है।

डब्ल्यूटीए 125 टेनिस टूर्नामेंट आयोजित करने की योजना बना रहा टीएनटीए

चेन्नई (ईएमएस)। तमिलनाडु टेनिस संघ (टीएनटीए) अगले साल से देश में तीन से चार डब्ल्यूटीए 125 टेनिस टूर्नामेंट आयोजित कर सकता है। दिग्गज टेनिस स्टार विजय अमृतराज भी टीएनटीए के इस कदम का समर्थन कर रहे है। उनका कहना है कि चेन्नई ओपन जैसे डब्लूटीए टूर्नामेंट की मेजबानी खोने के बाद किसी न किसी मुकाबले की सख्त जरुरत है। जिससे कि उभरती हुई प्रतिभाओं को कोई मंच मिल सके।

अमृतराज का कहना है कि चेन्नई ओपन को भारत में ही बनाये रखे जाने की जरुरत थी पर डब्ल्यूटीए इसके लिए तैयार नहीं था। इसके पीछे उसने खराब मौसम और फिलीपींस की एलेक्जेंड्रा इला के उभरने को बताया। एलेक्जेंड्रा के विजेता बनने के कारण नियमों के तहत टूर्नामेंट की मेजबानी फिलीपींस को दे दी गयी। अमृताराज ने ये भी माना है कि मौसम ठीक नहीं होने के कारण भारत में चेन्नई ओपन में बेहतर रैंकिंग वाले अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी भी नहीं आ रहे थे। इससे भी फिलीपींस का पलड़ा भारी पड़ गया। इला, महिला रैंकिंग में शीर्ष 20 खिलाड़ियों में शामिल हैं.

रंग संसार



अभिनेत्री कनिका मान ने बताई पूर्व प्रेमी की हैवानियत भरी कहानी

मुंबई (यशभारत)। अभिनेत्री कनिका मान ने हाल ही में अपने जीवन के एक दर्दनाक अध्याय को साझा करते हुए अपने पहले रिश्ते के भयावह अनुभवों का खुलासा किया है। उन्होंने बताया कि किस तरह उनका पूर्व प्रेमी उनके साथ शारीरिक और भावनात्मक रूप से बुरा बर्ताव करता था, जिसने उनकी जिंदगी को नर्क बना दिया था। इस आपबीती ने उन कई महिलाओं की कहानी को सामने लाया है, जो ऐसे रिश्तों में फंसकर हिंसा का शिकार होती हैं। कनिका ने बताया कि कॉलेज के दिनों में जब उनका पहला बॉयफ्रेंड बना, तो वह मानसिक रूप से अस्थिर था और बेहद बुरा बर्ताव करता था। कनिका ने एक डरावनी घटना साझा की, जब उनके पूर्व प्रेमी ने बिना बताए उनकी क्लास में आकर उन्हें केवल धारीदार सूट पहनने की वजह से पूरे कॉरिडोर के सामने इतनी जोर से थप्पड़ मारा कि उनके कानों से खून बहने लगा। उस समय उनके कानों में हाल ही में छेद करवाए गए थे। उन्होंने बताया कि उस वक्त कोई भी उनकी मदद के लिए आगे नहीं आया, जिसने उन्हें और भी अकेला महसूस कराया। यह केवल एक घटना नहीं थी। कनिका ने बताया कि उनका पूर्व प्रेमी उनके हर कदम पर नजर रखता था, उन्हें नियंत्रित करने की कोशिश करता था और उनका फोन छीनकर भीड़ में फेंक देता था। एक बार उसने उनके हॉस्टल के कमरे की चाबियां भी फेंक दी थीं, जिससे वह मुश्किल में पड़ गई।

कृति सेनन ने अंतरराष्ट्रीय फिल्म ऑब्सेशन के हिंदी संस्करण को दी अपनी आवाज

मुंबई (यशभारत)। अभिनेत्री कृति सेनन एक बार फिर अपने एक खास प्रोजेक्ट को लेकर चर्चा का विषय बन गई हैं। इस बार उन्होंने एक अंतर्राष्ट्रीय फिल्म, ऑब्सेशन के हिंदी संस्करण के लिए अपनी आवाज दी है, जिसके लिए वह बेहद उत्साहित हैं। कृति ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर डबिंग सेशन की कुछ तस्वीरें और वीडियो साझा किए हैं, जिनमें उनके साथ फिल्म भेड़िया के निर्देशक अमर कौशिक और उनके को-स्टार वरुण धवन भी नजर आए। इस तिकड़ी की मुलाकात ने फैंस को उनकी पुरानी ऑनस्क्रीन जोड़ी और पर्दे पर उनकी केमिस्ट्री की याद दिला दी।



कृति ने अपने पोस्ट में बताया कि ऑब्सेशन जैसी शानदार फिल्म की सशक्त परफॉर्मेंस को हिंदी में अपनी आवाज देना उनके लिए एक अनूठा और बेहद खास अनुभव रहा। उन्होंने विशेष रूप से फिल्म में इंडेना नवरेटे के अभिनय की जमकर तारीफ की। कृति ने कहा कि डबिंग के दौरान इंडेना की परफॉर्मेंस को देखकर उनके एक बार फिर रोंगटे खड़े हो गए। अभिनेत्री के मुताबिक, यह एक बेहद शानदार फिल्म है जिसमें सभी कलाकारों ने अद्भुत काम किया है। उन्होंने इस प्रतिष्ठित प्रोजेक्ट का एक छोटा-सा हिस्सा बनने पर अपनी खुशी भी व्यक्त की, जो उनके करियर में एक और महत्वपूर्ण पड़ाव जोड़ता है। डबिंग स्टूडियो में वरुण धवन और अमर कौशिक के साथ उनकी मुलाकात भी उनके पोस्ट का एक अहम हिस्सा बनी। कृति ने मजाकिया अंदाज में लिखा कि जब वुल्फपैक को किसी चीज का जुनून चढ़ जाए, तो कुछ ऐसा ही होता है। यह टिप्पणी उनकी हिट फिल्म भेड़िया के संदर्भ में थी, जहां तीनों ने साथ काम किया था। कृति ने दोनों के साथ दोबारा मिलना और काम के सिलसिले में एक साथ समय बिताना यादगार बताया और उनके प्रति अपना स्नेह व्यक्त किया। यह मुलाकात उनके प्रशंसकों के लिए भी एक ट्रीट थी, जो उन्हें फिर से एक साथ देखने का इंतजार कर रहे थे। ऑब्सेशन के हिंदी वर्जन के दो प्रमोशनल वीडियो भी कृति की आवाज में जारी किए जा चुके हैं।





किंग के नए गाने में सुहाना खान की पहली झलक को लेकर अटकलें

मुंबई (यशभारत)। अभिनेता शाहरुख खान की आने वाली फिल्म किंग को लेकर सोशल मीडिया पर जबरदस्त उत्साह बना हुआ है। हाल ही में फिल्म का नया गाना तू मिल जाए जारी किया गया है, जिसने दर्शकों के बीच उत्सुकता और बढ़ा दी है। इस रोमांटिक गाने में शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण की शानदार केमिस्ट्री देखने को मिल रही है, जिसे फैंस खूब पसंद कर रहे हैं। हालांकि, इस गाने के साथ एक और बात सुर्खियों में आ गई है। कई फैंस यह दावा कर रहे हैं कि उन्हें इस गाने में शाहरुख खान की बेटी, सुहाना खान की भी एक झलक देखने को मिली है। इस कथित झलक ने सोशल मीडिया पर चर्चाओं का बाजार गर्म कर दिया है और लोग फिल्म में उनके किरदार को लेकर कयास लगा रहे हैं। यह खास सीन गाने के लगभग दो मिनट बाद आता है, जो देखने में एक एक्शन सीक्वेंस का हिस्सा प्रतीत होता है। इसमें एक लड़की आग की लपटों से घिरे एक घर की तरफ देखती हुई नजर आती है। हालांकि, लड़की का चेहरा स्पष्ट रूप से नहीं दिखता, लेकिन फैंस का मानना है कि यह सुहाना खान ही हैं, जिन्होंने शायद फिल्म में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इस छोटी सी झलक ने दर्शकों के बीच कई तरह की अटकलें पैदा कर दी हैं। एक फैन ने कमेंट किया, सुहाना खान? वहीं एक अन्य यूजर ने लिखा, मुझे लगता है कि किंग के नए गाने में ये सुहाना खान ही हैं। कुछ ने इससे भी आगे बढ़कर सवाल किए, जैसे क्या सुहाना खान किसी चीज का सिर पकड़े हुए हैं?

अमिताभ बच्चन ने गलत खबर पर मीडिया को लताड़ा

मुंबई (यशभारत)। मेगास्टार अमिताभ बच्चन ने अपने ताजा सोशल मीडिया पोस्ट में मीडिया में छपी एक खबर को लेकर अपनी गहरी नाराजगी व्यक्त की है। अमिताभ ने आरोप लगाया है कि उनके शब्दों को मीडिया प्रचार के लिए गलत संदर्भ में पेश कर रहा है। इतना ही नहीं, सदी के महानायक ने इसके लिए मीडिया को कड़ी चेतावनी भी दी है। दरअसल, मेगास्टार अमिताभ बच्चन ने हाल ही में एक पोस्ट साझा किया था, जिसमें उन्होंने भगवान कृष्ण के लिए अक्सर इस्तेमाल होने वाली पारंपरिक पंक्ति, हाथी घोड़ा पालकी, जय कन्हैया लाल की से जुड़ा एक भावुक संदेश और ब्लॉग लिखा था। अमिताभ का कहना है कि मीडिया ने इन शब्दों को तोड़मरोड़कर प्रस्तुत किया है।

अमिताभ ने स्पष्ट किया कि उनका पोस्ट वास्तव में भगवान कृष्ण के प्रति एक प्रार्थना थी और उनके शब्द न किसी राजनीतिक बयान का हिस्सा थे, न ही किसी विरोधी पर उन्होंने कोई तंज कसा था। उन्होंने कहा कि मीडिया ने ऐसी



खबर छापकर धार्मिक नजरिए से भी गलत किया है और इसे धर्म का निरादर भी बताया है। अपनी पोस्ट में, अमिताभ ने मीडिया में संबंधित खबर की हैडिंग का भी जिक्र किया, जिसमें उनके शब्दों को गलत तरीके से चुनौती के रूप में पेश किया गया था। उन्होंने कहा, और मीडिया उसका निरादर करके, अपना प्रचार करने के लिए, छापता है, देखिए ये अमिताभ अपने विरोधियों को चुनौती दे रहा है, की, ले आओ हाथी घोड़ा हम अपने हथियारों से लड़ेंगे, डरेंगे नहीं ! एक तो घोर निंदा एक जय श्री कृष्ण के उपलक्ष्य में, और दूसरा , शब्दों को पलट कर विरोधियों को चुनौती देने की बात कर रहे है।

अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए, दिग्गज अभिनेता ने मीडिया को एक कड़ा संदेश भी दिया, जिसमें कहा गया कि उनके पांच करोड़ से अधिक फॉलोअर्स हैं और अगर उन्हें केवल एक इशारा भी मिल जाए तो उनमें से दस प्रतिशत भी उनके समर्थन में आ जाएंगे, जिससे स्थिति भारी पड़ सकती है। मेगास्टार ने अपने पोस्ट के जरिए यह भी कहा कि जब किसी सार्वजनिक हस्ती से गलती होती है, तो वे तुरंत माफी मांग लेते हैं और सुधार करने का प्रयास करते हैं, लेकिन जब किसी भी मीडिया की तरफ से गलती होती है, तो उनकी तरफ से कोई माफी नहीं आती है।

दूरस्थ अंचलों के युवाओं तक पहुंचे विश्वस्तरीय वैज्ञानिक शिक्षा और तकनीकी प्रशिक्षण का लाभ : साय

■ विज्ञान, तकनीक और अनुसंधान के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ को देश के अग्रणी राज्यों में करेंगे स्थापित

■ मुख्यमंत्री साय ने भारतीय विज्ञान संस्थान, बेंगलुरु के निदेशक एवं वरिष्ठ वैज्ञानिकों के साथ की उच्चस्तरीय बैठक

■ छत्तीसगढ़ को वैज्ञानिक अनुसंधान, उच्च शिक्षा, तकनीकी नवाचार और चिकित्सा प्रौद्योगिकी का प्रमुख राष्ट्रीय केंद्र बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल

■ मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को प्रस्तावित परियोजनाओं की व्यवहार्यता का परीक्षण कर ठोस कार्ययोजना तैयार करने के दिए निर्देश

यश भारत

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा है कि छत्तीसगढ़ को प्राकृतिक संसाधनों के साथ-साथ ज्ञान, विज्ञान, तकनीक और नवाचार की शक्ति से समृद्ध बनाना राज्य सरकार का संकल्प है। हमारा लक्ष्य छत्तीसगढ़ को केवल औद्योगिक और आर्थिक विकास में ही नहीं, बल्कि वैज्ञानिक अनुसंधान, उच्च शिक्षा, आधुनिक प्रौद्योगिकी और चिकित्सा नवाचार के क्षेत्र में भी देश के अग्रणी राज्यों में स्थापित करना है। उन्होंने कहा कि प्रदेश की समृद्ध खनिज संपदा, ऊर्जा संसाधनों, औद्योगिक संभावनाओं और प्रतिभाशाली मानव संसाधन को आधुनिक वैज्ञानिक अनुसंधान से जोड़कर विकास का एक नया अध्याय लिखा जा सकता है। मुख्यमंत्री साय आज राजधानी रायपुर स्थित अपने निवास कार्यालय में भारतीय विज्ञान संस्थान (आईआईएससी), बेंगलुरु के निदेशक प्रोफेसर जी. रंगराजन एवं संस्थान के वरिष्ठ वैज्ञानिकों तथा राज्य शासन के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ आयोजित उच्चस्तरीय बैठक को संबोधित कर रहे थे। बैठक में छत्तीसगढ़ को विज्ञान, प्रौद्योगिकी, उच्च शिक्षा, कौशल विकास और चिकित्सा अनुसंधान के प्रमुख केंद्र के रूप में विकसित करने की संभावनाओं पर व्यापक विचार-विमर्श किया गया। इस दौरान भारतीय विज्ञान संस्थान और छत्तीसगढ़ शासन के बीच तीन महत्वाकांपरियोजनाओं पर संभावित सहयोग, आवश्यक वैज्ञानिक अधोसंरचना, संस्थागत व्यवस्थाओं और क्रियान्वयन की प्रारंभिक रूपरेखा पर विस्तार से चर्चा हुई।





मुख्यमंत्री साय ने भारतीय विज्ञान संस्थान के निदेशक एवं वरिष्ठ वैज्ञानिकों का छत्तीसगढ़ आगमन पर आत्मीय स्वागत एवं अभिनंदन किया। उन्होंने कहा कि भारतीय विज्ञान संस्थान देश ही नहीं, विश्व के प्रतिष्ठित वैज्ञानिक एवं अनुसंधान संस्थानों में शामिल है। इसकी विशेषज्ञता, अनुसंधान क्षमताओं और शैक्षणिक अनुभवों का लाभ छत्तीसगढ़ के विश्वविद्यालयों, तकनीकी शिक्षण संस्थानों, उद्योगों, स्वास्थ्य सेवाओं और विशेष रूप से युवाओं को मिलना चाहिए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत विज्ञान, प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष अनुसंधान, डिजिटल नवाचार और आत्मनिर्भरता के क्षेत्र में नई उपलब्धियां हासिल कर रहा है। विकसित भारत के संकल्प को साकार करने में वैज्ञानिक अनुसंधान, तकनीकी उत्कृष्टता और उच्च कौशलयुक्त मानव संसाधन की निर्णायक भूमिका होगी। छत्तीसगढ़ भी इसी राष्ट्रीय दृष्टिकोण के अनुरूप विकसित छत्तीसगढ़ के निर्माण की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है।

कहा कि राज्य सरकार ऐसी विश्वस्तरीय वैज्ञानिक और शैक्षणिक अधोसंरचनाएं विकसित करना चाहती है, जिनका लाभ केवल वर्तमान पीढ़ी तक सीमित न रहे, बल्कि आने वाली अनेक पीढ़ियों को प्राप्त हो। विज्ञान और अनुसंधान में निवेश प्रदेश के दीर्घकालिक विकास, औद्योगिक प्रतिस्पर्धा और युवाओं के उज्ज्वल भविष्य में निवेश है।

मुख्यमंत्री साय ने विशेष रूप से इस बात पर जोर दिया कि भारतीय विज्ञान संस्थान जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों की विशेषज्ञता का लाभ केवल बड़े शहरों और प्रमुख शिक्षण संस्थानों तक सीमित नहीं रहना चाहिए। बस्तर, सरगुजा सहित प्रदेश के ग्रामीण, जनजातीय और दूरस्थ अंचलों में भी प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं है। आवश्यकता इन प्रतिभाओं को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, आधुनिक प्रयोगशालाओं, वैज्ञानिक मार्गदर्शन और तकनीकी प्रशिक्षण के बेहतर अवसर उपलब्ध कराने की है।

मुख्यमंत्री साय ने संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों को निर्देश दिए कि भारतीय विज्ञान संस्थान के साथ सहयोग की सभी संभावनाओं का गंभीरता से परीक्षण किया जाए। प्रस्तावित परियोजनाओं की तकनीकी, वित्तीय एवं संस्थागत व्यवहार्यता का अध्ययन कर ठोस और समयबद्ध कार्ययोजना तैयार की जाए, ताकि इन पहलों को व्यावहारिक स्वरूप दिया जा सके। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार विज्ञान, अनुसंधान और नवाचार से संबंधित इन महत्वपूर्ण प्रयासों को आगे बढ़ाने के लिए हरसंभव सहयोग प्रदान करेगी। बैठक में भारतीय विज्ञान संस्थान और छत्तीसगढ़ शासन के बीच तीन प्रमुख परियोजनाओं पर सहयोग की संभावनाओं को लेकर विस्तृत चर्चा हुई। इनमें प्रदेश में विश्वस्तरीय मटेरियल कैरेक्टराइजेशन एंड टेस्टिंग फैसिलिटी की स्थापना, विज्ञान एवं गणित के उत्कृष्ट शिक्षक तैयार करने के लिए चार वर्षीय एकीकृत बीएससी-बीएड संस्थान का विकास तथा आधुनिक चिकित्सा अनुसंधान और स्वास्थ्य प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारतीय विज्ञान संस्थान के मेडिकल स्कूल की विशेषज्ञता का लाभ छत्तीसगढ़ तक पहुंचाना शामिल है। इन प्रस्तावित परियोजनाओं के माध्यम से प्रदेश में अत्याधुनिक वैज्ञानिक अधोसंरचना विकसित करने, गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा एवं प्रशिक्षण उपलब्ध कराने, अनुसंधान आधारित औद्योगिक विकास को प्रोत्साहित करने तथा आधुनिक स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार की संभावनाओं पर विचार किया गया। बैठक में छत्तीसगढ़ में विश्वस्तरीय मटेरियल कैरेक्टराइजेशन एंड टेस्टिंग फैसिलिटी की स्थापना के प्रस्ताव पर विशेष रूप से चर्चा हुई। यह प्रस्तावित केंद्र प्रदेश के खनिज, इस्पात, धातु, ऊर्जा, उन्नत विनिर्माण और महत्वपूर्ण खनिजों से संबंधित उद्योगों के लिए अत्यंत उपयोगी सिद्ध हो सकता है।

भिलाई इस्पात संयंत्र की प्लेट मिल ने अक्टूबर में बनाए तीन नए रिकॉर्ड

1.23 लाख टन फिनिश्ड प्लेट का उत्पादन, कुल डिस्पैच और डायरेक्ट डिस्पैच में भी रचा नया कीर्तिमान

यश भारत



भिलाई। सेल-भिलाई इस्पात संयंत्र की प्लेट मिल ने अक्टूबर 2026 में उत्पादन और डिस्पैच के क्षेत्र में शानदार प्रदर्शन करते हुए तीन नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं। मिल ने फिनिश्ड प्लेट उत्पादन, कुल डिस्पैच और डायरेक्ट डिस्पैच में अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन दर्ज किया है। यह उपलब्धि अधिकारियों, कर्मचारियों और संबंधित विभागों के सामूहिक प्रयासों का परिणाम है।

प्लेट मिल ने अक्टूबर 2026 में 1,23,106 टन फिनिश्ड प्लेट का उत्पादन किया, जो अक्टूबर 2023 में दर्ज 1,21,675 टन के पिछले रिकॉर्ड से अधिक है। इसी तरह कुल डिस्पैच 1,19,237 टन दर्ज किया गया, जबकि अक्टूबर 2025 में यह रिकॉर्ड 1,18,502 टन था।

वहीं, डायरेक्ट डिस्पैच के क्षेत्र में भी प्लेट मिल ने नया रिकॉर्ड बनाते हुए अक्टूबर में 85,614 टन प्लेट का डिस्पैच किया। इससे अगस्त 2026 में दर्ज 85,101 टन का पिछला रिकॉर्ड टूट गया। इसके अतिरिक्त अक्टूबर माह में 14,349 टन का रोड डिस्पैच भी दर्ज किया गया।

प्लेट मिल की यह उपलब्धि बेहतर कार्यसमन्वय, उत्पादन क्षमता में वृद्धि और परिचालन दक्षता का परिणाम है। इस प्रदर्शन से भिलाई इस्पात संयंत्र के उत्पादन एवं डिस्पैच को नई मजबूती मिली है। साथ ही ग्राहकों को समय पर गुणवत्तापूर्ण उत्पाद उपलब्ध कराने की दिशा में संयंत्र की प्रतिबद्धता भी प्रदर्शित हुई है।

अमित जोगी की सूरत से तस्वीर वायरल, 9 को पुलिस के सामने होंगे पेश

यश भारत

रायपुर। 'ज्ञानु और जानू' वीडियो को लेकर विवादों में आए जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ (जे) के नेता अमित जोगी की तलाश में रायपुर पुलिस जुटी हुई है।

इसी बीच अमित जोगी की गुजरात के सूरत शहर से एक तस्वीर सोशल मीडिया पर सामने आई है, जिसमें वे गुजराती थाली का आनंद लेते नजर आ रहे हैं। इस तस्वीर के सामने आने के बाद मामला एक बार फिर चर्चा में आ गया है।

विवादित वीडियो को लेकर दर्ज हुई FIR- दरअसल, सोशल मीडिया पर कथित आपत्तिजनक 'ज्ञानु और जानू' वीडियो वायरल होने के बाद भाजपा नेताओं ने अमित जोगी के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत के आधार पर रायपुर की सिविल लाइंस थाना पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता की धारा 196, 352, 353(2), 356(2) और आईटी एक्ट के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू की है। पुलिस ने पूछताछ के लिए जोगी निवास के बाहर नोटिस भी चस्पा किया है।

माफी के बाद भी जारी है पुलिस की कार्रवाई- विवाद बढ़ने के बाद अमित जोगी ने सोशल मीडिया पर माफी मांगते हुए संबंधित पोस्ट हटा दिया था। हालांकि, पुलिस इस पूरे मामले में उनका पक्ष जानने और पूछताछ करने के लिए संपर्क करने का प्रयास कर रही है। उनके रायपुर से बाहर होने के कारण उनके फरार होने की चर्चाएं भी सामने आईं।

वहीं, जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ (जे) के प्रदेश संगठन महामंत्री निलेश चौहान ने अमित जोगी के फरार होने की खबरों को भ्रामक बताया है।

उन्होंने कहा कि अमित जोगी का 2 नवंबर से 8 नवंबर तक निजी कार्यक्रम के तहत प्रदेश से बाहर रहने का दौरा पहले से निर्धारित था। इसकी जानकारी संबंधित थाने के प्रभारियों को ईमेल के माध्यम से दी जा चुकी है।

एकता नगर में छत्तीसगढ़ का परचम लहराने वाले जांबाज पुलिस अधिकारियों से मिले विजय शर्मा, साहस और अनुशासन की सराहना की



■ राष्ट्रीय एकता दिवस परेड में छत्तीसगढ़ के वीर जवानों ने पूरे देश के सामने प्रस्तुत की बस्तर के शौर्य, संघर्ष और विजय की गौरवगाथा

■ बस्तर की महिला कमांडो के आत्मविश्वास और शानदार मार्च पास्ट ने पूरे देश को कराया बस्तर की नारी शक्ति का एहसास ङ्क उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा

■ जवानों ने साझा किए एकता नगर के अविस्मरणीय अनुभव

यश भारत

रायपुर। गुजरात के एकता नगर में आयोजित राष्ट्रीय एकता दिवस परेड में अपने अदम्य साहस, अनुशासन और शानदार प्रदर्शन से छत्तीसगढ़ का गौरव बढ़ाने वाले पुलिस अधिकारियों से आज उप मुख्यमंत्री एवं गृह मंत्री विजय शर्मा ने आत्मीय मुलाकात की। उन्होंने परेड में छत्तीसगढ़ का प्रतिनिधित्व करने वाले अधिकारियों को बधाई देते हुए उनके अनुभवों को जाना और राष्ट्रीय स्तर पर प्रदेश के सुरक्षा बलों के उत्कृष्ट प्रदर्शन की सराहना की और सभी के साथ भोजन किया।

इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा कि गुजरात के एकता नगर में राष्ट्रीय एकता दिवस पर आयोजित भव्य परेड में छत्तीसगढ़ के जवानों की सहभागिता पूरे प्रदेश के लिए अत्यंत गौरवपूर्ण क्षण था। उन्होंने कहा कि मैंने स्वयं इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण देखा। जब हमारे जवान पूरे आत्मविश्वास, अनुशासन और गर्व के साथ कदम से कदम मिलाकर मार्च कर रहे थे, तब वह दृश्य अत्यंत भावुक और गर्व से भर देने वाला था। हमारे जवान केवल एक परेड में हिस्सा नहीं ले रहे थे, बल्कि वे पूरे देश के सामने छत्तीसगढ़ के साहस, संघर्ष और बदलते बस्तर की नई पहचान प्रस्तुत कर रहे थे।उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने विशेष रूप से बस्तर फाइटर्स की महिला कमांडो के शानदार प्रदर्शन की सराहना की। उन्होंने कहा कि जिस आत्मविश्वास, जोश और दृढ़ता के साथ बस्तर की महिला कमांडो ने परेड में मार्च किया, वह अद्भुत था। उस क्षण वे केवल अपनी टुकड़ी का नेतृत्व नहीं कर रही थीं, बल्कि पूरे बस्तर की महिलाओं की शक्ति, साहस और आत्मसम्मान का प्रतिनिधित्व कर रही थीं। शर्मा ने कहा कि जिन क्षेत्रों को कभी नक्सल हिंसा और भय के कारण जाना जाता था, आज उन्हीं क्षेत्रों की बेटियां पूरे देश के सामने अपने साहस और सामर्थ्य का प्रदर्शन कर रही हैं। यह बदलते बस्तर की सबसे सुंदर और प्रेरणादायक तस्वीर है। बस्तर की इन बेटियों ने दिखा दिया है कि अवसर मिलने पर वे किसी भी चुनौती का सामना करने और देश का गौरव बढ़ाने में सक्षम हैं।

मुलाकात के दौरान परेड में शामिल अधिकारियों ने उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा के साथ अपने अनुभव साझा करते हुए बताया कि राष्ट्रीय एकता दिवस परेड के लिए उन्होंने लगातार कठिन अभ्यास और मेहनत की थी। देश के विभिन्न सुरक्षा बलों के साथ एक ही मंच पर प्रदर्शन करना उनके लिए जीवन का अविस्मरणीय अनुभव रहा। अधिकारियों ने बताया कि एकता नगर की सुंदरता, भव्यता और वहां की व्यवस्थाएं उनकी कल्पना से भी कहीं अधिक शानदार थीं। उन्होंने कहा कि पूरे छत्तीसगढ़ से उन्हें लगातार बधाइयां और शुभकामनाएं प्राप्त हुईं, जिससे उनका उत्साह कई गुना बढ़ गया।

छत्तीसगढ़ को फिल्म हब बनाने की तैयारी, चित्रोत्पला फिल्म सिटी और नई फिल्म नीति पर सरकार का फोकस

यश भारत

रायपुर। छत्तीसगढ़ को राष्ट्रीय स्तर पर प्रमुख फिल्म शूटिंग डेस्टिनेशन के रूप में स्थापित करने की दिशा में राज्य सरकार ने पहल तेज कर दी है। प्रदेश की प्राकृतिक सुंदरता, समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और पर्यटन स्थलों को फिल्म निर्माताओं के सामने प्रभावी ढंग से प्रस्तुत करने के साथ फिल्म निर्माण गतिविधियों को बढ़ावा देने की रणनीति तैयार की जा रही है। इसी सिलसिले में मंत्रालय महानदी भवन में मुख्य सचिव विकासशील की अध्यक्षता में उच्चस्तरीय बैठक आयोजित की गई।

बैठक में छत्तीसगढ़ को फिल्म शूटिंग के लिए आकर्षक केंद्र बनाने, राज्य की मौजूदा फिल्म नीति को अधिक व्यावहारिक एवं प्रभावी बनाने और फिल्म निर्माण से जुड़ी प्रक्रियाओं को सरल व पारदर्शी करने पर चर्चा हुई। मुख्य सचिव विकासशील ने कहा कि छत्तीसगढ़ में फिल्मांकन के लिहाज से प्राकृतिक और सिनेमैटिक दृश्यों की व्यापक संभावनाएं हैं।

प्रदेश के अनछुए प्राकृतिक स्थलों, सांस्कृतिक विरासत और पर्यटन केंद्रों को राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने की जरूरत है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्रदेशभर में फिल्म शूटिंग के लिए उपयुक्त नए स्थानों की पहचान कर उन्हें विकसित और प्रोत्साहित किया जाए। बैठक में बहुप्रतीक्षित चित्रोत्पला फिल्म सिटी के प्रस्ताव और उसकी संभावनाओं पर भी विस्तार से विचार-विमर्श किया गया। सरकार का प्रयास है कि फिल्म निर्माताओं और प्रोडक्शन हाउस को छत्तीसगढ़ में शूटिंग के लिए बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं, ताकि अधिक से अधिक फिल्म निर्माता प्रदेश की ओर आकर्षित हों।

मुख्य सचिव ने कहा कि फिल्म निर्माण गतिविधियों के विस्तार से पर्यटन को बढ़ावा मिलने के साथ स्थानीय कलाकारों, तकनीशियनों, युवाओं और होटल उद्योग के लिए रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे। इससे प्रदेश की सांस्कृतिक पहचान को व्यापक मंच मिलेगा और स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी गति मिलेगी। बैठक में निफ्टेम के प्रस्तावित भ्रमण तथा खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में तकनीकी सुविधाओं और प्रशिक्षण के विस्तार पर भी चर्चा की गई।

राज्योत्सव से कांग्रेस की दूरी छत्तीसगढ़ महतारी के स्वाभिमान और जनभावनाओं का घोर अपमान : भाजपा

प्रदेश प्रवक्ता गौरीशंकर श्रीवास का तीखा प्रहार - छत्तीसगढ़ की पहचान और विकास से कांग्रेस को कोई सरोकार नहीं, केवल आकाओं को खुश करने में व्यस्त हैं कांग्रेसी नेता

यश भारत



रायपुर। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता गौरीशंकर श्रीवास ने 1 से 3 नवंबर तक आयोजित त्रि-दिवसीय ऐतिहासिक राज्योत्सव से कांग्रेस नेताओं द्वारा बनाई गई दूरी पर कड़ा प्रहार किया है। श्रीवास ने कांग्रेस के इस रवैये को छत्तीसगढ़ की अस्मिता, स्वाभिमान और प्रदेश की तीन करोड़ जनता की भावनाओं का सीधा अपमान करार दिया।

भाजपा प्रदेश प्रवक्ता श्रीवास ने कहा कि 1 नवंबर का दिन समूचे छत्तीसगढ़ के लिए ऐतिहासिक गर्व, गौरव और आत्मसम्मान का प्रतीक है। पूर्व प्रधानमंत्री श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी की देन इस छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना का उत्सव पूरा प्रदेश एक परिवार की तरह मनाता है। ऐसे पावन अवसर पर जहाँ सभी को दलगत राजनीति से ऊपर उठकर छत्तीसगढ़वासियों के साथ कंधा-से-कंधा मिलाकर खड़ा होना चाहिए था और प्रदेश के विकास तथा जन-कल्याण के संकल्प को दोहराना चाहिए था, वहीं प्रदेश कांग्रेस के नेताओं ने इस भव्य राज्योत्सव से दूरी बनाकर अपनी संकीर्ण मानसिकता का परिचय दिया है। श्रीवास ने कांग्रेस नेताओं के राजनीतिक चरित्र और आचरण पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि जनता द्वारा पूरी तरह नकारे जाने के बाद अपनी राजनीतिक प्रासंगिकता खो चुकी कांग्रेस को छत्तीसगढ़ की संस्कृति, पहचान और स्वाभिमान से कोई लेना-देना नहीं रह गया है।

भाजपा प्रदेश प्रवक्ता श्रीवास ने कहा कि कांग्रेसी नेताओं की निष्ठा छत्तीसगढ़ महतारी और यहाँ की जनता के प्रति नहीं, बल्कि केवल दिल्ली दरबार में बैठे अपने आकाओं को खुश करने तक सीमित है। अपने आलाकमान की परिक्रमा में व्यस्त कांग्रेसी नेता अब राज्य की खुशहाली और जनता की भावनाओं का सौदा करने पर उतर आए हैं। श्रीवास ने कहा कि जब राज्य में भाजपा की विष्णुदेव साय सरकार छत्तीसगढ़ की गौरवशाली संस्कृति को सहेजते हुए विकास के नए कीर्तिमान स्थापित कर रही है, तब कांग्रेस की यह नकारात्मकता दर्शाती है कि वे प्रदेश को केवल लूट और भ्रष्टाचार का चारागाह समझते थे।

भाजपा प्रदेश प्रवक्ता श्रीवास ने कहा कि राज्योत्सव जैसे गरिमामयी आयोजन का अघोषित बहिष्कार कर कांग्रेस ने यह सिद्ध कर दिया है कि वे न केवल जनविरोधी हैं, बल्कि छत्तीसगढ़ के अस्तित्व और स्वाभिमान के भी घोर विरोधी हैं। ?श्रीवास ने कहा कि छत्तीसगढ़ की प्रबुद्ध जनता कांग्रेस के इस दोहरे चरित्र और अपमानजनक आचरण को भली-भाँति देख रही है और आने वाले समय में इसका मुँहतोड़ जवाब देगी।

मैट्स यूनिवर्सिटी ने मनाया 21वां स्थापना दिवस

विद्यार्थियों का सर्वांगीण विकास करना हमारा लक्ष्य-पगारिया

यश भारत

रायपुर। राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन आयोग से ए प्लस ग्रेड प्राप्त मैट्स यूनिवर्सिटी, रायपुर ने 3 नवंबर, 2826 मंगलवार एको अपना 21वां स्थापना दिवस मनाया। इस अवसर पर विश्वविद्यालय के कुलसचिव सहित कर्मठ प्राध्यापकों, अधिकारियों एवं कर्मचारियों का सम्मान भी किया गया।

21वें स्थापना दिवस का आयोजन यहां पंडरी स्थित मैट्स टॉवर के इंपैक्ट सेंटर में किया गया।

कार्यक्रम का शुभारंभ मां सरस्वती की प्रतिमा पर दीप प्रज्जवलन एवं माल्यार्पण के साथ किया गया। इस अवसर पर मैट्स यूनिवर्सिटी के कुलाधिपति श्री गजराज पगारिया ने कहा कि मैट्स यूनिवर्सिटी सिर्फ विश्वविद्यालय नहीं है बल्कि विश्वविद्यालय परिवार है जहां कार्यरत प्राध्यापकों से लेकर विभिन्न विभागों के पदाधिकारी, कर्मचारी सभी मिलकर प्रदेश व देश में उच्च शिक्षा के विकास के लिए निरंतर परिश्रम करते हैं। उन्होंने कहा कि मैट्स विश्वविद्यालय वर्ष 2006 में छत्तीसगढ़ राज्य में स्थापित होने वाला प्रथम निजी विश्वविद्यालय है और



वर्तमान में इसे राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन आयोग से ए प्लस ग्रेड प्राप्त है जो गौरव का विषय है। श्री पगारिया ने कहा कि हमारा उद्देश्य है गुणवत्ता से परिपूर्ण विश्वस्तरीय उच्च शिक्षा प्रदान कर विद्यार्थियों का सर्वांगीण विकास करना।

श्री पगारिया ने कहा कि हमारे विश्वविद्यालय में अच्छा वातावरण है जो सभी के सहयोग से है। हम गर्व के साथ कह सकते हैं कि हम छत्तीसगढ़ में नम्बर वन हैं और इसका श्रेय विश्वविद्यालय के सभी अधिकारियों , प्राध्यापकों, कर्मचारियों को जाता है।

इल अवसर पर यूनिवर्सिटी के कुलपति प्रो. के. पी. यादव ने कहा कि मैट्स विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़ में अग्रणी रहा है और सदैव अग्रणी रहेगा। हम सदैव समय के साथ चलते रहे हैं और आगे भी चलते रहेंगे, बल्कि समय से आगे चलना आवश्यक है। वर्तमान में हम ए प्लस ग्रेड प्राप्त हैं, भविष्य में हमें ए प्लस प्लस ग्रेड प्राप्त होगा, हमें पूर्ण विश्वास है।

इसके पूर्व कुलसचिव श्री गोकुलानंदा पंडा ने बीते बीस वर्षों की मैट्स विश्वविद्यालय की विकास यात्रा पर प्रकाश डाला। श्री पंडा ने विश्वविद्यालय की अनेक महत्वपूर्ण उपलब्धियों की जानकारी दी और कहा कि सभी के प्रयासों से विश्वविद्यालय ने उपलब्धियां हासिल की हैं। उन्होंने कुलाधिपति श्री गजराज पगारिया और महानिदेशक श्री प्रियेश पगारिया के कुशल नेतृत्व की सराहना की।

इस दौरान लेखा विभाग के प्रमुख श्री सौरभ सोनी सहित सभी संकायों के विभाग प्रमुखों ने भी अपने विचार रखे।

इस अवसर पर सभी विभागों के विभागाध्यक्ष, प्राध्यापकगण, विश्वविद्यालय के अधिकारीगण और कर्मचारी उपस्थित थे। इसके पूर्व विश्वविद्यालय के कुलसचिव श्री गोकुलानंदा पंडा सहित लेखा विभाग प्रमुख श्री सौरभ सोनी, डॉ. वी.पी. रॉय, वाय कृष्णा राव, डॉ. आशीष झा, श्रीमती परमिंदर कौर, डॉ. प्रशांत मुंडेजा, विकास निर्मलकर, दीप्तांशु शर्मा का शॉल, श्रीफल और स्मृति चिन्ह देकर सम्मान किया गया।

स्वामी प्रकाशक मुद्रक आशीष कुमार शुक्ला , मिशन मीडिया (प्रा.लि.) प्लाट नम्बर -9/1 छत्तीसगढ़ भवन, प्रेस काम्प्लेक्स,रजबंधा मैदान, रायपुर छत्तीसगढ़ -492001 से मुद्रित एवं हॉउस नम्बर 18/303 सेक्टर 27 ,नवा रायपुर ,रायपुर छत्तीसगढ़ -492018 से प्रकाशित। संपादक आशीष कुमार शुक्ला सलाहकार संपादक श्याम कटारे
प्रबंध संपादक अजय क्षत्रे, स्थानीय संपादक अरविंद कुमार पांडेय मो .-9827117441 RNI-CTHI/26/A5 206 ईमेल -raipuryashbharat@gmail.com (पीआरबी एक्ट के तहत समाचार चयन के लिए जिम्मेदार) , सिटी ऑफिस- आर्यन टॉवर द्वितीय तल द्रोणाचार्य स्कूल के पास रायपुर, मो .-9111201000 (न्यायालय क्षेत्र अधिकार रायपुर)